चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

रामदेव के ख़िलाफ़ संत समाज मुखर

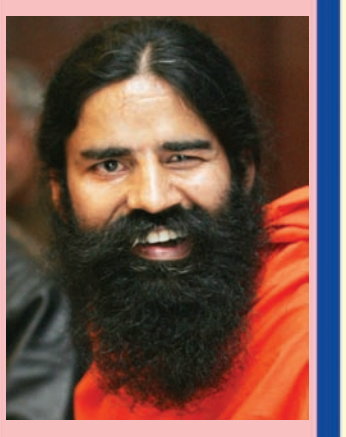

पेज-3

वाममोर्चा की विदाई आसान नहीं

पेज-5

एक गांव, जो विकास का मॉडल है

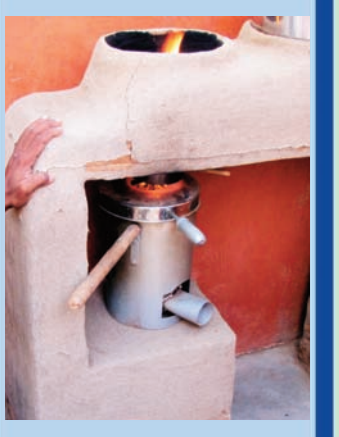

पेज-7

इस्लामी दुनिया के महानायक

पेज-11

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 07 मार्च -13 मार्च 2011 | मूल्य 5 रुपये

बाबा रामदेव अब सिर्फ़ रामदेव

धर्माचार्यों का बाबा रामदेव पर आरोप

- गुरु शंकर देव की हत्या का आरोप
- राजीव दीक्षित, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव, की मौत के ज़िम्मेवार
- आस्था चैनल को ज़ोर-ज़बरदस्ती और धोखाधड़ी से हथियाने का आरोप
- आस्था चैनल के हेड किरीट सी मेहता के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का आरोप
- संत समाज को भ्रष्टाचार की आग में झोंकने का आरोप
- धर्म को धंधा बनाने का आरोप

मनीष कुमार

राजनीति काजल की काली कोठरी है. ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं, जो इस काली कोठरी में घुस जाएं और बेदाग़ निकल जाएं. बाबा रामदेव राजनीति की इस काली कोठरी में घुसे नहीं कि उनके दामन पर दाग़ लगने लगे हैं. पहले कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने बाबा को मिलने वाले काले धन की जांच की मांग की. अब बाबा रामदेव संत समाज के निशाने पर आ गए हैं. हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि जब-जब राजनीति का सामना संतों से हुआ, राजनीति हारी है, संत हमेशा जीते हैं. दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बाबा रामदेव ने हुंकार भरी और यह बोल गए कि वह आज हज़ारों करोड़ के ब्रांड बन चुके हैं. क्या संत ब्रांड बन सकते हैं? क्या धर्म का धंधा किया जा सकता है? क्या योग की मार्केटिंग हिंदू धर्म की परंपरा के मुताबिक़ है? देश और धर्म से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमने अखिल भारतीय संत समिति के उत्तर भारत के अध्यक्ष एवं श्री कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम से बात की. बातचीत के दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बाबा रामदेव के बारे में कई ऐसी बातें बताईं, जिन पर भरोसा करने में डर लगता है.

बाबा रामदेव ने हरिद्वार के एक आश्रम में योग की शिक्षा ली. यह आश्रम गुरु शंकरदेव का था. कहा जाता है कि बाबा रामदेव और गुरु शंकरदेव एक ही कमरे में रहते थे. वह जाने-माने संत थे. भारत के शीर्षस्थ संतों के संपर्क में थे. अच्छे साधक थे. एक दिन वह अचानक ग़ायब हो गए. गुरु शंकरदेव कहां गए, यह किसी को पता नहीं है. न तो उनकी लाश मिली और न ही यह पता चल पाया है कि उनके साथ आख़िर क्या हुआ. बाबा रामदेव ने गुरु शंकरदेव को खोजने का कोई प्रयत्न नहीं किया. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सीधा-सीधा आरोप लगाया है कि पूरे देश का संत समाज यह मानता है कि शंकरदेव की हत्या बाबा रामदेव ने की, ताकि वह ज़मीन उन्हें मिल जाए और जो उन्हें मिली. एक उच्चस्तरीय जांच का गठन होना चाहिए. इतने बड़े ऋषि शंकरदेव ग़ायब हो गए, लेकिन उनके साथ रहने वाले बाबा रामदेव से किसी ने पूछताछ नहीं की. आचार्य का कहना है कि यह बाबा रामदेव का प्रभाव है कि आज तक इस मामले में कोई तहक़ीक़ात नहीं हुई. अब सवाल यह है कि शंकरदेव कहां गए, उनकी लाश कहां है, उनकी मौत कैसे हुई? अगर वह ज़िंदा हैं तो उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता. उनका अचानक ग़ायब हो जाना एक गंभीर विषय है. अखिल भारतीय संत समिति इसकी उच्चस्तरीय जांच की मांग करती है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि उन्हें यह आशंका है कि गुरु शंकरदेव कहीं किसी साज़िश का शिकार तो नहीं हो गए.

बाबा रामदेव के इतिहास को जानने लिए हमने वैष्णव संप्रदाय के सर्वोच्च जगतगुरु से बात की. जगतगुरु ने खुलकर सारी बातें बताईं, लेकिन अपना नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया. जगतगुरु के कहने पर हम उनका नाम नहीं लिख रहे हैं. इस बातचीत से यह पता चला कि बाबा रामदेव से संत समाज न सिर्फ़ निराश है, बल्कि डरता भी है. कई संत ऐसे हैं, जो बाबा रामदेव के क्रियाकलापों को धर्म के विरुद्ध बताते हैं, लेकिन देश के सामने आकर बाबा के ख़िलाफ़ बोलने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता है. वैष्णव संप्रदाय के सर्वोच्च जगतगुरु की शंकरदेव से भी निकटता थी. जगतगुरु ने फोन पर बताया कि बाबा रामदेव 1994 में मेरे आश्रम में बैठा रहता था, एक्यूप्रेशर वगैरह करता था. टूटे से स्कूटर से आता था, तबसे मैं उसे जानता हूं. साधु भी बनने को मैंने ही उसे कहा था. गुरुकुल कांगड़ी में छटे हुए लड़कों में गिना जाता था. एक प्रॉपर्टी है दिव्य योग मंदिर. उसे धोखे से लिखवाया गया था स्वामी शंकरदेव जी से, जिनका आज कोई अता-पता नहीं है. हत्या भी कराई होगी तो उसी ने कराई होगी न. वह तो बहुत दुखी थे. इसने लिखवा लिया तो बहुत रोते थे हमारे पास आकर. हमें पता तब लगा था, जब इसने लिखवा लिया. हम पूछना चाहते हैं कि वसीयत है तो दिखाए हमें. उसने बहुत बड़ा झूठ बोला कि आश्रम की ज़मीन कब वह उसके नाम कर गए, पता ही नहीं. लेकिन वह तो डिग्री है, कोर्ट से सूचना के अधिकार से तो मिल सकती है. कोई भी आदमी ग़ायब हो जाए तो ख़बर तो करता है, मर गया तो श्राद्ध तो करता है. यह आदमी तो पैदा ही बेईमान हुआ था. मैंने इसे एक दिन उठाया और दो-चार थप्पड़ लगाए, फिर पूछा कि यह बता

(शेष पृष्ठ 2 पर)

रामदेव संतों की मर्यादा में रहकर काम करें

बाबा रामदेव पर लगे आरोपों की सच्चाई जानने के लिए समन्वय संपादक डॉ. मनीष कुमार ने सुमेर पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती से बातचीत की. प्रस्तुत हैं मुख्य अंश:

बाबा रामदेव से संत समाज क्यों नाराज़ है?

संतों को दवाइयां नहीं बेचनी चाहिए और अगर दवाएं बेचनी ही हैं तो संत के वेश को त्याग देना चाहिए, व्यवसाइयों की वेशभूषा और परिवेश अपना लेना चाहिए. वह जो कर रहे हैं, वह बिल्कुल भी उचित नहीं है. वैसे राजनीति में राजनीतिज्ञों को दिशा-निर्देश तो देना चाहिए. यह तो इतिहास रहा है. चाणक्य थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, लेकिन उन्होंने गद्दी नहीं संभाली, बस दिशा दिखाते रहे. यह उनकी अज्ञानता है, जो वह बिज़नेस कर रहे हैं. संतों का धर्म बिजनेस करना नहीं है.

क्या आपको भी लगता है कि गुरु शंकर देव की हत्या में बाबा रामदेव शक़ के घेरे में हैं, क्या इसकी जांच होनी चाहिए?

अवश्य होनी चाहिए, अगर बाबा रामदेव ने उनकी हत्या नहीं

(शेष पृष्ठ 2 पर)

छोटी-छोटी सफाइयां चाहिए...

आचार्य बालकृष्ण भारत के नागरिक नहीं हैं

बाबा रामदेव के दाहिने हाथ माने जाने वाले आचार्य बालकृष्ण भारत के नागरिक नहीं हैं. देश के संतों का आरोप है कि वह नेपाल के नागरिक हैं. उनका जन्म नेपाल में हुआ. उनका पूरा परिवार नेपाल का नागरिक है, लेकिन उनके पासपोर्ट पर यह लिखा है कि वह जन्म से भारतीय हैं. आचार्य बालकृष्ण पहले बाबा रामदेव के शिविरों और उनके कार्यक्रमों का ध्यान रखते थे. जबसे बाबा रामदेव दवाइयां बेचने लगे और बिज़नेस करने लगे तो आचार्य बालकृष्ण ने बाबा का पूरा साम्राज्य संभाल लिया. बाबा रामदेव ने जबसे राजनीति में आने का फ़ैसला किया है, तबसे बाबा के राजनीतिक मोर्चे की कमान आचार्य बालकृष्ण ने संभाल ली है. अब जबकि बाबा रामदेव ने राजनीतिक दल बनाने की घोषणा कर दी है तो आचार्य बालकृष्ण की नागरिकता पर सवाल उठना लाज़िमी है. बाबा रामदेव को आज नहीं तो कल, इस सवाल का जवाब देना ही होगा.

बाबा रामदेव के नाम ज़मीन नहीं तो क्या उनके भाई और रिश्तेदारों के नाम पर तो है

बाबा रामदेव पर यह आरोप लगा कि वह देश और विदेश में सैकड़ों एकड़ ज़मीन के मालिक हैं. बाबा रामदेव मीडिया के सामने आए. उन्होंने साफ़-साफ़ कहा कि उनके नाम एक भी इंच ज़मीन नहीं है. साधु-संतों को ज़मीन की क्या ज़रूरत है. बाबा रामदेव का खंडन सराहनीय है. लेकिन संत समाज के लोग इसे बाबा रामदेव की एक चाल बता रहे हैं. उनका सवाल है कि बाबा रामदेव के नाम से ज़मीन नहीं है तो क्या हुआ, उनके सगे भाई और रिश्तेदारों के नाम से तो करोड़ों की संपत्ति है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है. उनकी मांग है कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि वर्ष 2000 से पहले बाबा रामदेव के सगे भाई और उनके रिश्तेदारों के पास कितनी ज़मीन थी और कितनी संपत्ति थी और अब 2011 में उनके पास क्या है. इस जांच से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा.

बाबा रामदेव और मीडिया

संतों ने यह सफ़ाई मांगी है कि बाबा रामदेव का देश के एक बड़े मीडिया घराने और उसके मुख्य कार्यकर्ता से क्या रिश्ता है? और इस कार्यकर्ता ने बाबा रामदेव की अंतरराष्ट्रीय मार्केटिंग में इतना बड़ा रोल क्यों निभाया?

झूठ का पुलिंदा है रामदेव

अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सबसे पहले बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ आधिकारिक बयान दिए. डॉ. मनीष कुमार ने परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता बाबा हठयोगी से बातचीत की. पेश हैं मुख्य अंश:

बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कर दिया है कि अचानक पूरा संत समाज, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और अखिल भारतीय संत समिति उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं?

नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा संत समाज हाथ धोकर बाबा रामदेव के पीछे पड़ गया है. अगर साधु ही इस वेश की आड़ में सभी तरह के व्यापार करने लगेंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा. हम, जो धर्म और संस्कृति का उपदेश देने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा देने वाले, यदि हम ही लोगों का शोषण करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, टैक्स की चोरी करेंगे, योग का कैंप करेंगे तो क्या होगा? निस्वार्थ करें तो बात अलग है, लेकिन हम ग्यारह सौ रुपये, ग्यारह हज़ार रुपये लेंगे तो क्या होगा? वह शिविरों की सीट टिकट की तरह बेचते हैं और जो ज़्यादा पैसे देता है वह आगे और जो कम देता है, उसे पीछे वाली सीट देते हैं. और फिर सरकार को टैक्स की चोरी कर नुक़सान पहुंचाएंगे, सारे सरकारी लाभ पाएंगे और फिर बाहर से पाक-साफ़ बनेंगे कि विदेशों में जो काला धन है, उसे वापस लाएंगे. लेकिन सबसे ज़्यादा काला धन हमारी संस्था में लग रहा है, जिसका हिसाब हम नहीं दे रहे हैं.

एक चैनल पर मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि वह पहले अखाड़ा परिषद को पैसा दिया करते थे?

(शेष पृष्ठ 2 पर)

माओवादियों के आगे सरकार द्वारा झुकने के बाद बाबुओं की ओर से एक और सवाल आया है कि अगली बार माओवादियों के निशाने पर कौन?

दिल्ली, 07 मार्च –13 मार्च 2011
चौथी दुनिया

दिल्ली का बाबू

विद्रोह की क़ीमत

क्या सरकार और माओवादियों के बीच चूहे-बिल्ली की तरह चल रहे खूनी संघर्ष में बाबुओं की हालत एक बंधक की तरह हो गई है? मलकानगिरी के जिलाधिकारी आर विनील कृष्णा एवं जूनियर इंजीनियर पी एम मांझी के अपहरण और बाद में उनकी रिहाई से यह सवाल उठ रहा है. खासकर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा माओवादियों की 14 मांगों को मान लेने की खबर आने के बाद यह सवाल और भी मजबूत हुआ है. अन्य मांगों के अलावा इसमें माओवादियों के खिलाफ सुरक्षाबलों की कार्रवाई रोकने और जेल में बंद उनके साथियों की रिहाई की मांग भी शामिल थी. सूत्रों के मुताबिक, उड़ीसा के मुख्य सचिव बी के पटनायक एवं गृह सचिव यू एन बेहरा और माओवादियों की तरफ से नियुक्त मध्यस्थ के बीच काफी तनावपूर्ण समझौते के बाद ही कृष्णा की सुरक्षित रिहाई संभव हो सकी. माओवादियों की मांगों के आगे सरकार द्वारा झुकने के बाद बाबुओं की ओर से एक और सवाल आया है कि अगली बार माओवादियों के निशाने पर कौन? क्योंकि सरकार और प्रभावित राज्यों की अपेक्षा माओवादियों की मंशा तो बिल्कुल साफ है.

ताक़तवर राजनीति

दिलीप चेरियन

पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने इस बात को ख़ारिज कर दिया है कि स्कूली शिक्षा के महानिदेशक कृष्ण कुमार का तबादला उन्हें प्रताड़ित करने की कार्रवाई के तहत किया गया, जैसा कि उनके राजनीतिक आलोचक आरोप लगा रहे थे. लेकिन राज्य के बाबू इस तर्क से सहमत नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि महज एक साल में ही कृष्ण कुमार का नौ बार तबादला किया गया. पंजाब के बाबुओं को यह बात भी अजीब लगती है कि राज्य स्तर के अधिकारियों की नियुक्तियों या तबादलों के मामले में किसी अन्य चीज के मुकाबले राजनीतिक कारण ज्यादा हावी रहते हैं. सूत्रों का कहना है कि अभी हाल में तहसील कल्याण अधिकारी मंजीत सिंह, अकाली नेता और पूर्व कृषि मंत्री गुरदेव सिंह बादल के बेटे को तथाकथित तौर पर तीन बार आरोपित किया गया, लेकिन हर बार उन्हें बहाल कर दिया गया. उन पर अपनी ड्यूटी से दो साल तक गायब रहने के अलावा बलात्कार का भी एक आरोप लगा था. जाहिर तौर पर बादल सरकार इस मामले में ख़ामोश रहा.

dilipcherian@gmail..com

बाबा रामदेव अब सिर्फ़ रामदेव

पृष्ठ एक का शेष

भाई, महात्मा से तूने जो लिखापढ़ी कराई, कैसे कराई. फिर वह मेरे पैर पकड़ कर बैठ गया. स्वामी अमलानंद जी के आश्रम में. कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपके ही अनुसार चलूंगा, सारा जीवन अब मैं अच्छे काम करूंगा. शंकरदेव के मामले में बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए. एक आदमी लापता है तो खोजो और मर गया तो सरकार इसकी घोषणा करे. कुछ तो करे. इस आदमी ने सरकार को भी नहीं लिखा कि उनकी खोज हो. जगतगुरु ने दु:ख के साथ कहा कि इसने न जाने कितने लोगों को मरवा दिया. यह लोगों को मरवा देता है. मैंने तो देखा है न, इसकी भाषा को. अगर कोई भी विरोधी है तो कहता है कि ख़त्म कर दो काम.

उत्तर भारत के संतों, आश्रमों और मठों में खलबली मची है. हर कोई बाबा रामदेव के बारे में बात कर रहा है. मीडिया में छाए रहने और प्रसिद्धि की दृष्टि से तो यह अच्छा माना जा सकता है, लेकिन बाबा रामदेव के लिए यह परीक्षा की घड़ी है. विडंबना यह है कि पितातुल्य संत, धर्माचार्य, गुरु एवं साथी, जिनके साथ बाबा रामदेव ने बचपन बिताया, जिनकी छड़ी खाकर और डांट सुनकर बड़े हुए, वही लोग आज बाबा रामदेव के ख़िलाफ़ खड़े हैं. बाबा रामदेव पर हत्या जैसा एक और आरोप है. अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष का मानना है कि अपने योग की साख बचाने के लिए रामदेव ने देश के एक होनहार विद्वान राजीव दीक्षित की बलि चढ़ा दी. राजीव दीक्षित जब जीवित थे तो वह हमेशा बाबा रामदेव के साथ नज़र आते थे. उनके शिविरों में वह भाषण देते थे. बाबा रामदेव के योग से हर तरह के रोग के इलाज के दावों का तर्क देते थे. उनकी उम्र चालीस साल की थी. माना जाता है कि राजीव दीक्षित की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई. बाबा रामदेव पूरी दुनिया के हृदय रोगियों का इलाज करते हैं तो क्या बाबा रामदेव को यह पता नहीं था कि उनके साथी को ही हार्ट की बीमारी है. अगर पता था तो उनका इलाज क्यों नहीं किया गया और अगर रामदेव अपने साथी का ही इलाज नहीं कर सकते तो दुनिया के सामने यह कैसे दावा करते हैं कि उनके योग से हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती है.

आचार्य ने कहा कि सूत्र बताते हैं कि राजीव दीक्षित और उनके रिश्तेदार मेडिकल ट्रीटमेंट चाहते थे, लेकिन बाबा रामदेव ने परिवारवालों को फोन करके या बात करके यह कहा कि तुम अगर अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करोगे तो इस देश में ख़राब मैसेज जाएगा. आचार्य का कहना है कि बाबा रामदेव के लिए मैसेज देने का मामला था, लेकिन राजीव दीक्षित की जान चली गई. सोचने वाली बात यह है कि राजीव दीक्षित का अंतिम संस्कार जल्दबाजी में क्यों किया गया. उनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया. आचार्य बताते हैं कि जिन लोगों ने राजीव दीक्षित की शवयात्रा में हिस्सा लिया, वे कहते हैं कि उनके होंठ नीले पड़ चुके थे. अब संत यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक से मरने वाले व्यक्ति की होंठ नीले पड़ते हैं? यह इतना ज्वलंत प्रश्न है, जिससे यह शंका पैदा होती है कि राजीव दीक्षित और शंकरदेव को रास्ते से हटाने वाले बाबा रामदेव और उनके इर्द-गिर्द वे लोग हैं, जिनकी जांच होना बहुत आवश्यक है.

एक कंपनी थी आस्था ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, जो अब वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड बन चुकी है. यह कंपनी आस्था नामक धार्मिक टेलीविजन चैनल चलाती थी. इस चैनल पर बाबा रामदेव के योग कार्यक्रमों का प्रसारण होता था. आस्था ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड के हेड किरीट सी मेहता हुआ करते थे. रामदेव तीन साल से इस चैनल पर कार्यक्रम कर रहे थे, जिसका पैसा आस्था चैनल को दिया जाना था. जब यह राशि बढ़कर बहुत ज़्यादा हो गई तो रामदेव और उनके लोगों ने किरीट सी मेहता का अपहरण किया और बंधक बना लिया. आचार्य प्रमोद कृष्णम का आरोप है कि किरीट सी मेहता को बंधक बनाने वालों में एक नाम है तीजारेवाला, दूसरे ख़ुद स्वामी रामदेव हैं और तीसरे एक उद्योगपति हैं, जिनका उन्होंने नाम नहीं बताया. किरीट सी मेहता को बंधक बनाकर उनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया गया. इसी के ज़रिए आस्था ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड को वैदिक ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड में बदल दिया गया. किरीट सी मेहता से एक सादे काग़ज़ पर हस्ताक्षर कराकर उन्हें छोड़ दिया गया. आचार्य प्रमोद ने ख़ुलासा किया कि इसके बाद किरीट सी मेहता और उनके परिवार को यह धमकी दी गई कि अगर वे हिंदुस्तान में रहे तो उनकी हत्या करा दी जाएगी. आचार्य प्रमोद कृष्णम का दावा है कि ये बातें ख़ुद किरीट सी मेहता ने उनसे कही हैं. वह बताते हैं कि गणेश चतुर्थी के दौरान दिशा नामक एक धार्मिक चैनल पर वह लाइव कार्यक्रम में शामिल थे. आचार्य प्रमोद इस चैनल के स्टूडियो में थे. देश भर से लोग आचार्य से सवाल पूछ रहे थे. उसी कार्यक्रम में किरीट सी मेहता ने लंदन से फोन किया और बताया कि वह सारी दुनिया को एक संत के कारनामों के बारे में बताना चाहते हैं. आचार्य कहते हैं कि इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसे पूरी दुनिया ने सुना. इस कार्यक्रम के एंकर थे माधवकांत मिश्र, जो इस वक्त दिशा टीवी चैनल के हेड हैं. आचार्य कहते हैं कि बाबा रामदेव की धमकी से डरकर किरीट सी मेहता आज तक भारत वापस नहीं लौटे. कभी दुबई तो कभी लंदन में छुपते फिर रहे हैं. मुंबई में उनके घर पर ताला लगा हुआ है. आचार्य प्रमोद कृष्णम बताते हैं कि उस लाइव कार्यक्रम में उन्होंने जब भारत वापस आने को कहा तो किरीट सी मेहता ने कहा कि उन्हें इस बात का डर है कि अगर वह भारत लौटे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी. बाबा रामदेव पर यह आरोप हैरान करने वाला है. आस्था चैनल ने बाबा रामदेव को ख्याति दिलाने में, पूरे देश में पापुलर करने में बड़ा योगदान किया है. मीडिया के कुछ लोग बताते हैं कि किरीट सी मेहता की वजह से ही रामदेव आज योग गुरु बाबा रामदेव बने हैं. अफ़सोस इस बात का है कि जिस शख्स ने बाबा की इतनी मदद की, वह आज दर-दर की ठोकरें खा रहा है. आचार्य से जब हमने इन आरोपों का सबूत मांगा तो उन्होंने दिशा चैनल के एंकर माधवकांत मिश्र को फोन किया और फोन के स्पीकर से हमें पूरी बातचीत सुनाई. फोन पर हुई बातचीत के दौरान माधवकांत मिश्र ने इस पूरी घटना की पुष्टि की और कहा कि वे सारे टेप चैनल के पास आज भी मौजूद हैं.

संतों ने बाबा रामदेव पर सिर्फ़ हत्या, अपहरण और धमकी देने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह भी कहा कि बाबा रामदेव संत समाज में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं. आचार्य प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि बुरे से बुरा आदमी भी संतों को छोड़ देता है. अत्याचारी और दुराचारी भी संतों को नहीं लूटते, लेकिन बाबा रामदेव आस्था चैनल के ज़रिए संत समाज को लूट रहे हैं. अब आस्था चैनल बाबा रामदेव की देखरेख में चल रहा है. आचार्य ने बताया कि आस्था चैनल पर जितने भी प्रवचन दिखाए जा रहे हैं, किसी से पांच लाख तो किसी से सात लाख रुपया महीना लिया जा रहा है. यह पैसा संतों से ओबी वैन के नाम से लिया जा रहा है. एक दिन का ओबी वैन का ख़र्च 2 लाख बताकर पैसा लिया जाता है. समझने वाली बात यह है कि जो संत पांच लाख रुपये चैनल को देगा तो वह ख़ुद 15 लाख कमाने की क्यों नहीं सोचेगा. कोई संत अगर पांच लाख रुपये आस्था चैनल को देता है तो वह पैसा कहां से आएगा. ज़ाहिर है, यह पैसा उद्योगपतियों और काले धन के ज़रिए ही इकट्ठा किया जाता है. आचार्य कहते हैं कि क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है, जो व्यक्ति संतों को लूट रहा है, वह देश की लूट के विषय में कैसे बात कर सकता है. बाबा रामदेव को वह चुनौती देते हैं कि उन्होंने जो तीन हज़ार एकड़ ज़मीन में बना यूरोप में एक टापू ख़रीदा है, उन्हें उसका ख़ुलासा करना चाहिए.

देश के बड़े-बड़े धर्माचार्य और जगतगुरु बाबा रामदेव से निराश हैं. उनका आरोप है कि रामदेव ने धर्म को धंधा बना दिया. कुछ संतों ने कहा कि यह संत का कैसा रूप है, जो गौमूत्र बेचकर मुनाफ़ा कमाता है. एक संत ने बताया कि महर्षि पतंजलि ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उनके नाम की ब्रांडिंग हो जाएगी और कलयुग में योग भारत की धरती पर साधना से हटकर व्यापार बन जाएगा. बाबा रामदेव कोई भी शिविर लगाते हैं तो वह 31 लाख रुपये लेते हैं. जबसे उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की है, तबसे वह मुफ्त में शिविर लगाने लगे हैं. आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह आरोप है कि बाबा रामदेव ने संत परंपरा को प्राइवेट लिमिटेड बना डाला. पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड को सरकार से पैसे मिले, जिसका इस्तेमाल वह बिजनेस में कर रहे हैं. देश के संत सवाल कर रहे हैं कि क्या यही देशभक्ति है? क्या यही भ्रष्टाचार से लड़ने का सही रास्ता है?

जहां तक बात उनकी राजनीति की है तो संत समाज को इससे कोई आपत्ति नहीं है. अखिल भारतीय संत समिति का कहना है कि उनकी राजनीति से किसी को भी कोई मतभेद नहीं है. बाबा रामदेव ने देश के हज़ारों लोगों का अपने योग से इलाज किया. देश भर में घूम-घूमकर शिविर लगाए. योग को फिर से जीवित किया और इसका पूरी दुनिया में प्रचार-प्रसार किया. अपने शिविरों में कपालभांति और प्राणायाम के दौरान राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दिया. वह देशभक्ति, स्वदेशी और ईमानदारी की बातें करते थे. लोगों को अच्छा लगता था. पूरे देश में इसके लिए बाबा रामदेव की जय-जयकार हुई. फिर बाबा रामदेव ने राजनीति में सक्रिय होने का ऐलान कर दिया. उन्होंने घोषणा भी कर दी कि अगले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 543 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. राजनीति और धर्म में अंतर होता है. संत की जवाबदेही धर्म से होती है. राजनेताओं को जनता को जवाब देना पड़ता है. क़ानून और न्यायालय किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं मानता, जब तक उसे सज़ा न मिल जाए. बाबा रामदेव पर लगे आरोप सिर्फ़ आरोप ही हैं. सच्चाई क्या है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी. बाबा रामदेव को याद रखना चाहिए कि क़ानून की निगाहों में ए राजा आज भी निर्दोष हैं, लेकिन जनता की अदालत ने उन्हें दोषी मान लिया है. संत और राजनेता में यह भी एक अंतर है, संत मौन धारण कर सकते हैं, यह छूट नेताओं को नहीं है. रामदेव संत से राजनेता बन चुके हैं. उन्हें अब सारे सवालों और आरोपों का जवाब देश की जनता को देना होगा.

manish@chauthiduniya.com

रामदेव संतों की मर्यादा में रहकर काम करें

पृष्ठ एक का शेष

कराई है तो समाज के सामने उनको लाना चाहिए. उनकी संपत्ति हड़पने के लिए, उनकी जायदाद लेने के लिए उनकी हत्या तो की गई है, इसकी जांच होनी चाहिए और अपराधी को दंड भी मिलना चाहिए.

बाबा रामदेव को आप कब से जानते हैं?

रामदेव को तो मीडिया के माध्यम से ही जानता हूं. एकाध बार मुलाक़ात हुई है. जिस वक़्त उन्होंने शंकराचार्य के सिद्धांत को चैलेंज किया था, उस वक़्त व्यक्तिगत मुलाक़ात हुई थी हमारी-उनकी. उन्होंने कहा कि हमने यह कहा ही नहीं, मीडिया ने झूठ बताया है, तो हमने कहा कि आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया. दूसरे ही दिन उनका खंडन छपा और उन्होंने हमारे यहां माफ़ीनामे का एक फैक्स भिजवाया. हरिद्वार में जगतगुरु के आश्रम में गए, वहां भी उन्होंने माला पहनाई और कहा कि हमने ऐसा बयान नहीं दिया है. मीडिया ने मेरी कही बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया है. उन्होंने सारा दोष मीडिया पर ही मढ़ दिया. हमने कहा था कि आप शंकराचार्य के सिद्धांत को चुनौती दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग उनके अनुयायी हैं, परंपरा के लिहाज़ से मैं चुनौती लेने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यही है कि जो हारेगा, उसको जीवित समाधि लेनी होगी.

तो बाबा रामदेव माला वगैरह लेकर पहुंच गए?

उन्होंने हस्तलिखित माफ़ीनामा दिया. जूना अखाड़े के महामंत्री हरि गिरीश जी महाराज से बात कराई कि माफ कर दीजिए, शांत हो जाइए.

बाबा रामदेव ने इतना पैसा, इतनी ख्याति प्राप्त कर ली है, इसलिए दूसरे संतों को उनसे ईर्ष्या हो गई है. इसलिए वे उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं?

अगर रामदेव काले धन पर ख़ुलासा करने की बात करते हैं तो पहले ख़ुद की विदेश में और दूसरी जगहों पर ख़रीदी हुई संपत्ति को लाएं. अगर उन्हें संपत्ति लेनी भी है तो भारत में लें. विदेशों में लेने का क्या मतलब है. भारत के पैसे से ख़रीद रहे हैं, उन्हें भारत में संपत्ति ख़रीदनी चाहिए. अब वह यह कहेंगे कि हमें विदेश से मिली. उनसे जलन किसी को नहीं है, लेकिन उन्हें संतों की मर्यादा के दायरे में रहकर काम करना चाहिए. क्यों जलेंगे दूसरे संत उनसे, क्या उनसे किसी की दुश्मनी है? लेकिन उल्टा-सीधा अनर्गल बोलेंगे तो वह ग़लत है.

आप लोग क्या चाहते हैं?

हम जैसे संत चाहते हैं कि अगर उन्हें बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करें और संत के वेश का परित्याग करें. संतत्व है तो संतत्व की मर्यादा में रहकर काम करें.

झूठ का पुलिंदा है रामदेव

पृष्ठ एक का शेष

अगर एक भी पैसा उन्होंने अखाड़ा परिषद को दिया है तो या तो वह अपनी पूरी संपत्ति दान कर देंगे या मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा. यह बिल्कुल झूठ है, झूठ का पुलिंदा है. बेचारा, जिसने उसे सब कुछ सिखाया, उसका पता तक नहीं लगाया. जिसने पांच बीघा ज़मीन दी, उसका पता नहीं है. ख़ुद इस समय अरबों रुपये पर अकेले राज कर रहा है. कर्णवीर, जिसने फाउंडेशन की स्थापना में अपना पूर्ण योगदान दिया, उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया. स्वामी योगानंद, जिसके नाम से उसने आयुर्वेद का लाइसेंस लिया था और इतनी बड़ी फार्मेसी चलाता था, उसे मरवा दिया और उसके भतीजे का नाम लगवा दिया. राजीव दीक्षित, जो उसके स्वाभिमान ट्रस्ट का पूरा काम करता था, वह आदमी जो दिन-रात योग करता है और योग से दुनिया भर के लोगों का इलाज करता है, क्या वह चालीस साल का आदमी हार्ट अटैक से मर जाएगा?

बाबा रामदेव ने कहा कि आपका अखाड़ा परिषद से कोई लेना-देना नहीं है?

मेरा अखाड़ा परिषद से लेना-देना नहीं है? मैं अखाड़ा परिषद का प्रवक्ता हूं. मैं कह दूं कि रामदेव का लेना-देना नहीं है अखाड़ा परिषद से तो उससे क्या होगा.

क्या ऐसा है कि किसी निजी क्लेश की वजह से आप लोगों के बीच ऐसी रंजिश हो रही है?

मैं किसी से एक भी पैसा नहीं लेता हूं, आप किसी से भी पूछ लें. आप पूरे हरिद्वार में पूछ सकते हैं. वह जो कह रहा है, वह बौखलाया हुआ बोल रहा है. अभी तो रामदेव की इतनी असलियत सामने आएगी कि वह रोएगा. जो धर्म और कर्म और योग और आयुर्वेद के नाम पर वह लोगों को लूट रहा है, जितनी वाहवाही उठा रहा है, उतना ही रोएगा. ठीक है आयुर्वेद का नाम किया, मैं भी इससे प्रसन्न हूं, लेकिन यह तो लोगों का शोषण करने लगा है, मज़दूरों को मज़दूरी भी नहीं देता है, उनका शोषण करता है, पचास-पचास करोड़ की सब्सिडी लेता है पगार के नाम पर और 3300 रुपये में बेचारों से बारह घंटे काम कराता है.

नोट : यह पूरी रिपोर्ट धर्माचार्यों और जगतगुरुओं से हुए इंटरव्यू पर आधारित है. इसके बावजूद हमने बाबा रामदेव पर लगे आरोपों के बारे में उनसे बात करने की कोशिश की. उनके सहायकों को फोन किया तो उन्होंने अजय आर्य का नंबर दे दिया. कई बार डायल करने के बाद भी उन्होंने फोन नहीं उठाया. फिर जब उन्होंने फोन उठाया तो कहा कि बाबा रामदेव ने अपनी तरफ़ से सारी बातें 23 तारीख़ को कह दी हैं. हमने जब यह कहा कि बाबा रामदेव पर नए आरोप लग रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप बाबा रामदेव के मीडिया प्रभारी एस के तीजारेवाला से बात कीजिए. तीजारेवाला के नंबर पर हम फोन करते रहे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया. हम बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में हैं.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 2 अंक 52
दिल्ली, 07 मार्च-13 मार्च 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय 0120-4783999/11-23418962
विज्ञापन व प्रसार +91 120 4783999
+91 9871194800
फैक्स न. 0120-4783950

पृष्ठ-16+4+4+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

योग गुरु रामदेव के ख़िलाफ़ एक दर्जन से अधिक संत-महात्मा धर्म नगरी हरिद्धार में मुखर हैं और उन्हें अधर्मी एवं वेश विरोधी बताते हुए आईना दिखाने का काम कर रहे हैं.

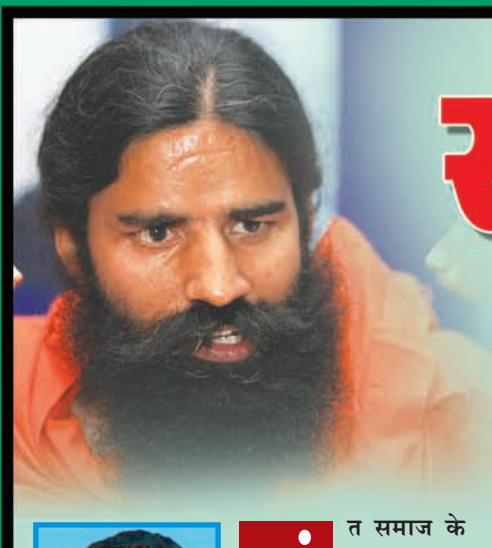

रामदेव के ख़िलाफ़ संत समाज मुखर

राजकुमार शर्मा

संत समाज के प्रमुख एवं राजग सरकार में केंद्रीय गृहराज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने बाबा रामदेव को ग़रीब विरोधी बताकर उनकी परेशानी बढ़ा दी है. चिन्मयानंद कहते हैं कि रामदेव ने बीते आठ वर्षों में ग़रीबों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपये इकट्ठा किए, लेकिन ग़रीबों का कोई कल्याण नहीं किया. वह अपने सभी उत्पादों पर करोड़ों रुपये की कर चोरी करते हैं. अगर रामदेव जन कल्याण के नाम पर लाभ रहित उत्पाद बनाते हैं तो उनके उत्पाद इतने महंगे क्यों हैं? इतने कम समय में उन्होंने हरिद्वार से स्काटलैंड तक साम्राज्य कैसे खड़ा किया, इसकी सीबीआई द्वारा जांच की जानी चाहिए.

चिन्मयानंद ने कहा कि रामदेव योग को बेचते हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि अगर शो करने पर देश के सिने कलाकारों को करोड़ों रुपये टैक्स देना पड़ता है तो बाबा के योग शो को सरकार ने इस दायरे से बाहर कैसे रखा है? उन्हें भी टैक्स के दायरे में लाया जाना चाहिए. बाबा ने जन कल्याण के नाम पर जनता से छल करके करोड़ों रुपये की काली कमाई की है. आयुर्वेदिक दवाएं तो डाबर एवं झंडू फार्मा सहित अनेक कंपनियां बनाती हैं, जो सभी तरह के टैक्स अदा करती हैं. इसके बावजूद उनके उत्पाद दिव्य योग पीठ फार्मेसी की दवाओं से कम दामों पर बिकतें हैं. चिन्मयानंद ने कहा कि अगर रामदेव सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो उन्हें वे सभी टैक्स ईमानदारी से जमा कर देने चाहिए, जिनकी उन्होंने अब तक चोरी की है. उन्होंने रामदेव से सवाल किया कि वह स्पष्ट करें कि दवाओं एवं योग की आमदनी का कितना प्रतिशत धन ग़रीबों के कल्याण पर अब तक ख़र्च किया गया. बाबा पचास करोड़ रुपये की मोटी रकम ग़रीबों के कल्याण के लिए अनुदान के रूप में भारत सरकार से स्वीकृत करा चुके हैं, जिसमें से वह तीस करोड़ रुपये का आहरण कर चुके हैं, बीस करोड़ रुपये निकालने की फिराक में है, जिसे सरकार को जारी करने से रोक देना चाहिए. स्वामी चिन्मयानंद ने बाबा का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा कि उनका काला धन उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है, जिसके चलते वह बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं. एकाध बुद्धि शुद्धी यज्ञ बाबा को अपने लिए भी करा लेना चाहिए.

योग गुरु रामदेव के ख़िलाफ़ एक दर्जन से अधिक संत-महात्मा धर्म नगरी हरिद्वार में मुखर हैं और उन्हें अधर्मी एवं वेश विरोधी बताते हुए आईना दिखाने का काम कर रहे हैं. प्रख्यात संत हठयोगी जी ने कहा कि रामदेव ने संत वेश का फ़ायदा लेकर, बाबाओं से झूठ बोलकर भगवा वेश को कलंकित किया है. वह साधु नहीं, व्यापारी हैं. साधु तो वे हैं, जो त्यागपूर्ण जीवन जी कर धर्म का प्रचार कर रहे हैं. हठयोगी जी कहते हैं कि अगर रामदेव में सच्चाई है तो वह अपने गुरु को क्यों नहीं खोजकर समाज के सामने प्रस्तुत करते. अपने गुरु को ठिकाने लगाने में उन्हीं की भूमिका रही है, पूरा समाज इस सच को जान चुका है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ, वह देश-समाज का क्या होगा? झूठ और काले धन पर निर्मित रामदेव का साम्राज्य बालू की भीत की तरह है, जो उनके बड़बोलेपन के चलते ध्वस्त हो जाएगा. राजीव दीक्षित की मौत को संदेह के घेरे में खड़ा करते हुए हठयोगी जी ने कहा कि रामदेव तो योग से ब्लॉकेज हटाने का लंबा-चौड़ा व्याख्यान करते हैं तो दीक्षित की मौत हार्ट अटैक से कैसे हुई?

हरिद्वार के प्रख्यात संत ऋषिश्वरानंद जी को रामदेव द्वारा काले धन पर निशाना साधने को लेकर दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है. उनका मानना है कि रामदेव एक राजनीतिक दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इसीलिए राजीव एवं इंदिरा गांधी की शहादत को भुलाकर वह उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं. विहिप के लोगों ने राम मंदिर के नाम पर जनता से अरबों रुपये की उगाही की, लेकिन रामदेव को राम के नाम पर धोखा देने वाले लोग इसलिए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि वे उन्हीं की जमात के हैं. रामदेव का आचरण किसी भी तरह से संत का आचरण नहीं दिखता. इसलिए उन्हें अपने नाम के पहले बाबा शब्द को हटा देना चाहिए. उन्होंने काले धन की बात करके जनता को भ्रमित करने का ठेका ले रखा है. जिस तरह रावण ने माता सीता का हरण करने के लिए भगवा वेश धारण किया था, उसी तरह रामदेव रावण के आचरण को अपनाते हुए जनता रूपी सीता का हरण करने के लिए भगवा वेश का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसे देश की जनता ही बेनकाब करेगी.

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का रामदेव के पाले में खुल कर खड़ा होना, हरिद्वार के संतों का मुखर विरोध इस बात को दर्शाता है कि राजनीति में कूदने को आतुर बाबा का बड़बोलापन उनके ही गले की हड्डी बनता जा रहा है. बाबा अपने समर्थकों से चाहे जितनी भी अपनी पीठ थपथपा लें, हरिद्वार का संत समाज मुखर विरोध के साथ उनसे किनारा कर रहा है. इंदिरा-नेहरू परिवार पर हाथ डालने वाले बाबा को जिस तरह फ़ज़ीहत झेलनी पड़ रही है, उससे एक ही बात स्पष्ट हो रही है कि उनके बलिदान के आगे बाबा की बाबागिरी टिकने वाली नहीं है. कनखल के दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट से शुरू हुए रामदेव का साम्राज्य आज स्काटलैंड तक फैला हुआ है. वर्ष 2003 में रामदेव एवं आचार्य बालकृष्ण इसी ट्रस्ट के तीन कमरों में मरीजों का उपचार किया करते थे. महज़ आठ साल में विदेशों तक साम्राज्य खड़ा करना देवभूमि के लोगों को खलने लगा है.

हाल में नितिन गडकरी के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी बाबा की सराहना करके अपनी रीति-नीति स्पष्ट कर दी है. ऋषिकेश से टिहरी तक बाबा को मुखर विरोध झेलना पड़ रहा है. टिहरी के सांसद विजय बहुगुणा ने बाबा की संपत्ति की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. लोगों ने योग गुरु का पुतला फूंककर भी अपनी भड़ास निकाली. जवाब में ऋषिकेश के दून चौराहे पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका. ऋषिकेश के वेदास्थानम् के महंत विनय सारस्वत ने सुझाव दिया है कि रामदेव को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए, उनका छद्म रूप जनता को बरगलाने में सफल नहीं होगा, उनके आचरण से भगवा वेश कलंकित हो रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

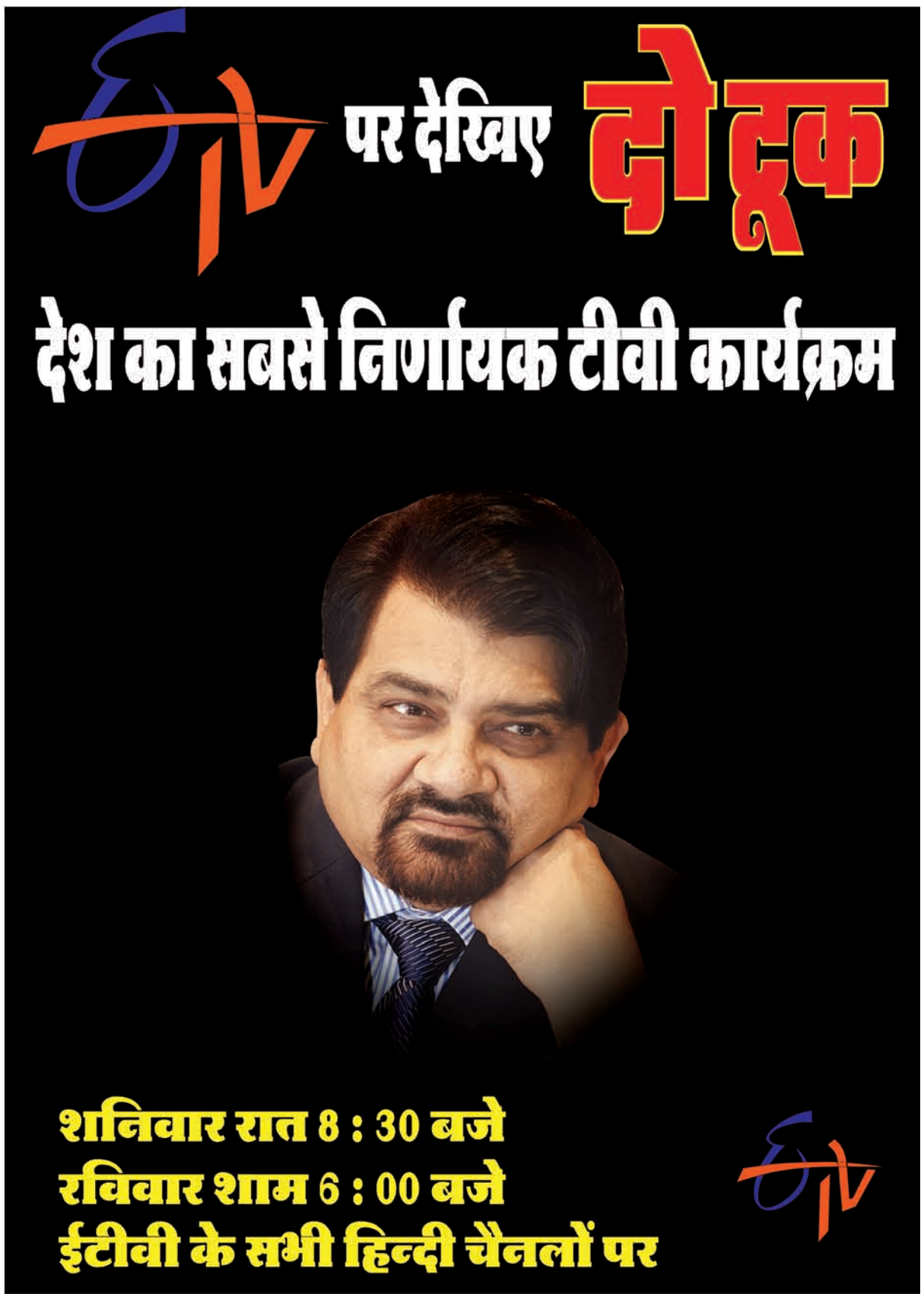

मिस्र के घटनाक्रम से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि अरब देशों के निवासी अनुशासित ढंग से शांतिपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक आंदोलन करने में सक्षम हैं

अरब देशों में परिवर्तन का दौर

डॉ. असगर अली इंजीनियर

मिस्र और ट्यूनीशिया का हालिया घटनाक्रम सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आया. शायद ही किसी को यह उम्मीद रही होगी कि इन देशों में अचानक जनाक्रोश का विस्फोट हो जाएगा, परंतु ज़मीनी हक़ीक़त जानने-समझने वाले लोगों के लिए इन दो देशों में हुई जनक्रांति अनापेक्षित नहीं थी. दुनिया के कई विद्वान और टीकाकार इस्लाम को प्रजातंत्र विरोधी और तानाशाहों का समर्थन करने वाला धर्म बताते रहे हैं. जबकि तथ्य यह है कि इस्लामिक दुनिया के तानाशाहों का समर्थन मुख्यत: पश्चिमी देशों ने अपने हितों के रक्षार्थ किया और अब भी कर रहे हैं. जब काहिरा की सड़कों पर होस्नी मुबारक को सत्ता से बाहर करने के लिए लाखों लोग सिर पर कफन बांधकर निकल पड़े तो पश्चिमी देश और उनके पिट्ठू हतप्रभ रह गए. अब इज़रायल चाहता है कि मिस्र में प्रजातंत्र का आगाज़ न हो सके, क्योंकि उसके अनुसार प्रजातंत्र का अर्थ होगा इस्लामिक ब्रदरहुड (इस्लामिक एकता या बंधुत्व) की जीत. इससे पहले जब फिलिस्तीन में प्रजातांत्रिक चुनाव के ज़रिए हमास पार्टी सत्ता में आई थी, तब इज़रायल और अमेरिका ने हमास सरकार को मान्यता देने से इंकार कर दिया था. ये हैं प्रजातंत्र के प्रति अमेरिका और इज़रायल की प्रतिबद्धता के नमूने.

कोई धर्म प्रजातंत्र विरोधी या प्रजातंत्र समर्थक नहीं होता. धर्म का वास्ता नैतिक, आध्यात्मिक एवं ईश्वर से संबंधित मसलों से है. जो लोग धर्म को राजनीति से जोड़ते हैं, वे अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं. कुरआन यह कहीं नहीं कहती कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता. वैसे भी राजनीति कुरआन की विषयवस्तु नहीं है. इस्लाम प्रजातंत्र का उतना ही समर्थक या विरोधी है, जितना कि कोई अन्य धर्म. इस्लाम के प्रजातंत्र विरोधी होने का दुष्प्रचार पश्चिमी राजनेता एवं मीडिया करते रहे हैं. जब भी किसी इस्लामिक देश में प्रजातंत्र के उदय की संभावनाएं परिलक्षित होती हैं, अमेरिका तुरंत वहां के तानाशाहों के समर्थन में सक्रिय हो जाता है. इंडोनेशिया से लेकर अरब देशों तक अमेरिका यही करता रहा है. अमेरिका एक ओर तानाशाहों का साथ देता है तो दूसरी ओर इस्लाम को प्रजातंत्र विरोधी बताता है. मिस्र में होस्नी मुबारक की तानाशाह सरकार को अमेरिका एवं इज़रायल का समर्थन प्राप्त था. जब ओबामा को लगा कि होस्नी मुबारक ने जनता का भरोसा पूरी तरह खो दिया है, तब उन्होंने मुबारक को अप्रत्यक्ष रूप से अपना पद छोड़ने की सलाह देनी शुरू कर दी. यह भी तय है कि अमेरिका पूरा प्रयास करेगा कि मिस्र में जो भी सत्ता में आए, वह अमेरिकी एवं इज़रायली हितों की रक्षा करे.

मिस्र में किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जनता का भरोसा जुटाना मुश्किल होगा, जो मुबारक की तरह अमेरिकी हितों का चौकन्ना पहरेदार हो. अरब देशों में परिवर्तन की एक नई बयार बह रही है. ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में मुट्ठी भर युवाओं ने अमेरिका एवं इज़रायल की हिंसा का जवाब हिंसा से देने की कोशिश की, परंतु इसके घातक परिणाम हुए. अरब के युवा वर्ग को यह एहसास हो गया है कि हिंसा के रास्ते पर चलकर वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेगा. शांतिपूर्ण-प्रजातांत्रिक संघर्ष ही दूरगामी और स्थायी परिवर्तन ला सकता है. मिस्र एवं ट्यूनीशिया के घटनाक्रम ने कई अरब शासकों को भयाक्रांत कर दिया है. यमन के राष्ट्रपति अली अबु सलेह ने घोषणा कर दी है कि 2013 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद सत्ता में बने रहने का उनका कोई इरादा नहीं है. ट्यूनीशिया, मिस्र एवं यमन में एक समानता है. तीनों ही देश ग़रीब हैं और तीनों में ही कुंठित एवं बेरोज़गार युवाओं की एक बड़ी फौज है. धनी अरब देशों के युवा ग़रीबी एवं बेरोज़गारी जैसी समस्याओं से नहीं जूझ रहे हैं और इस कारण ट्यूनीशिया, मिस्र एवं यमन जैसा जनाक्रोश भड़कने की आशंका वहां कम है.

जहां यह सही है कि तेल उत्पादक धनी अरब देशों के लोगों को आर्थिक समस्याओं से दो-चार नहीं होना पड़ रहा है, वहीं इसमें कोई संदेह नहीं कि मिस्र के घटनाक्रम का प्रभाव इन देशों की राजनीतिक संस्कृति पर पड़े बिना नहीं रह सकेगा. देर-सबेर सभी अरब देश इससे प्रभावित होंगे. इन सभी देशों में अमेरिका समर्थित तानाशाह राज कर रहे हैं. इन देशों के शासक अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर हैं और अमेरिका उनका इस्तेमाल अपने एवं इज़रायल के हितों की रक्षा के लिए करता है. यही कारण है कि इज़रायल द्वारा फिलिस्तीनियों के साथ किए जा रहे अमानवीय व्यवहार को उक्त देश चुपचाप देखते रहते हैं. उनमें अमेरिका एवं इज़रायल के ख़िलाफ़ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है. इन देशों की जनता अपने शासकों की इस कायरता से नाराज़ अवश्य है, परंतु प्रजातंत्र के अभाव में वह अपना रोष प्रकट नहीं कर पाती है. किसी भी प्रकार के विरोध को इन देशों में निर्ममतापूर्वक कुचल दिया जाता है. होस्नी मुबारक भी अपने विरोधियों को क्रूर शारीरिक यंत्रणा देने के लिए कुख्यात था. अरब देशों के शासकों, बादशाहों, शेखों एवं तानाशाहों की अलोकप्रियता का मुख्य कारण है फिलिस्तीनी समस्या के प्रति उनका रवैया. ये सभी इज़रायल को अमेरिकी समर्थन के मुद्दे पर स्थायी चुप्पी साधे रहते हैं और इनकी यह नीति इन देशों के नागरिकों को कतई रास नहीं आती. मिस्र की हालिया क्रांति भी फिलिस्तीन के प्रश्न पर नहीं हुई. वहां की जनता होस्नी मुबारक से त्रस्त थी.

इस सिलसिले में महत्वपूर्ण यह है कि मुबारक सरकार ने इज़रायल को गाज़ा पट्टी की घेराबंदी करने में हमेशा पूरी मदद की. इस घेराबंदी से फिलिस्तीनियों का जीवन दूभर हो गया है. यह भी ध्यान देने की बात है कि मिस्र की क्रांति का कोई एक नेता नहीं था. यह सही अर्थों में जनक्रांति थी. किसी एक नेता ने जनता से विद्रोह का झंडा उठाने का आह्वान नहीं किया था और न ही जनता के रोष को शांतिपूर्ण विद्रोह की दिशा देने के लिए कोई चमत्कारी नेता सामने आया था. एक सर्वमान्य नेता के अभाव के बावजूद मिस्र का आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासित बना रहा. कुछ स्थानों पर मामूली हिंसा, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं अवश्य हुईं, परंतु वे अपवादस्वरूप थीं. यह विद्रोह आम लोगों की पहल पर आम लोगों ने किया. यह अत्यंत विस्मयकारी है कि जिस देश में कई दशकों से प्रजातंत्र नहीं था, वहां की जनता ने अत्यंत अनुशासित ढंग से आंदोलन का संचालन किया. परिपक्व प्रजातंत्रों में भी आंदोलन अक्सर हिंसक रूप अख्तियार कर लेते हैं.

मिस्र के घटनाक्रम से एक बार फिर यह सिद्ध हो गया है कि अरब देशों के निवासी अनुशासित ढंग से शांतिपूर्ण एवं प्रजातांत्रिक आंदोलन करने में सक्षम हैं और यह भी कि मुसलमानों में प्रजातंत्र के प्रति आकर्षण है. इससे उस पश्चिमी दुष्प्रचार का पुरजोर खंडन होता है कि मुसलमानों का मिजाज़ प्रजातंत्र से मेल नहीं खाता. मिस्र का घटनाक्रम इंडोनेशिया के घटनाक्रम से काफी मिलता-जुलता है. इंडोनेशिया के तानाशाह सुहार्तो कई दशकों तक अमेरिका के समर्थन से अपने देश पर राज करते रहे. जैसे ही अमेरिका ने सुहार्तो को समर्थन देना बंद किया, उनकी सरकार गिर गई और बिना किसी समस्या के इंडोनेशिया में प्रजातंत्र का आगाज़ हो गया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है. वहां नियमित रूप से चुनाव होते हैं. मिस्र, ट्यूनीशिया, यमन एवं इंडोनेशिया आदि का फिलिस्तीन समस्या और कच्चे तेल के संसाधनों से कोई लेना-देना नहीं था. इसके विपरीत अरब देशों के तानाशाह अमेरिका को कहीं अधिक प्रिय हैं. इसका कारण है कच्चे तेल के भंडार और इज़रायल. अमेरिका के कारखाने चलते रहें और कारें दौड़ती रहें, इसके लिए तेल ज़रूरी है. वहीं अरब देश अमेरिका के नियंत्रण में बने रहें, इसके लिए इज़रायल की ज़रूरत है.

अत: यह स्पष्ट है कि मध्य पूर्व के मामले में अमेरिका उस तरह तटस्थ नहीं बना रहेगा, जैसा उसने इंडोनेशिया के संदर्भ में किया. मध्य पूर्व में अमेरिका के रणनीतिक एवं आर्थिक हित हैं, जिनकी वह हर क़ीमत पर रक्षा करने का प्रयास करेगा. अमेरिका की पहली कोशिश तो यही होगी कि मध्य पूर्व के देशों में उसकी कठपुतली सरकारें शासन में रहें. अगर ऐसा न भी हो सका तो अमेरिका कम से कम इतना तो चाहेगा कि वहां जो भी शासक हों, वे पश्चिमी देशों से मधुर संबंध रखें. बहरहाल, मिस्र के लोगों ने एक नया इतिहास रच दिया है. अपने तीन सप्ताह लंबे और सफल संघर्ष के ज़रिए उन्होंने दर्शा दिया है कि वे प्रजातंत्र और अहिंसा के पुजारी हैं और अहिंसा के रास्ते पर चलकर परिवर्तन लाने में सक्षम हैं. महात्मा गांधी जैसा कोई नेता मिस्र में नहीं था, परंतु फिर भी वहां की जनता अहिंसा के रास्ते से नहीं डिगी. मिस्र की जनता ने यह दिखा दिया कि वह प्रजातंत्र की हामी है और उसने इस मिथक को भी तोड़ दिया कि मुसलमान एक हिंसक कौम हैं और उन्हें प्रजातंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है. इससे यह भी साफ हो गया है कि अहिंसक संघर्ष से बहुत कम समय में जो हासिल किया जा सकता है, वह दशकों की हिंसक लड़ाई से भी नहीं मिल सकता. अहिंसा ज़िंदाबाद, शांतिपूर्ण संघर्ष की जय.

feedback@chauthiduniya.com

वाममोर्चा ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 7 प्रतिशत आरक्षण को 17 प्रतिशत कर दिया है और उसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को भी शामिल किया है.

पश्चिम बंगाल

वाममोर्चा की विदाई आसान नहीं

फोटो–*देवज्योति चक्रवर्ती*

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

बिमल राय

यह एक महज़ संयोग नहीं था कि जिस दिन बिहार विधानसभा चुनावों के परिणाम आ रहे थे, ठीक उसी दिन बंगाल की वाममोर्चा सरकार ने राज्य में पंचायतों की 50 फ़ीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फ़ैसला लिया. तमाम झिझक के बावजूद बांग्ला मीडिया के एक हलके में इस बात पर चर्चा हुई कि कामयाबी का बिहार मॉडल बंगाल में भी कारगर हो सकता है. झिझक की चर्चा मैंने इसलिए की कि यहां कुछ साल पहले तक बिहार का प्रसंग केवल नकारात्मक कारणों से ही उठता रहा है, पर अब हालात बदल रहे हैं. सत्ता विरोधी लहर की काट कैसे तैयार की जाती है, इसका रास्ता बिहार ने दिखाया है. थोड़ा विकास, पर बड़ी उम्मीद के मंत्र ने वाममोर्चा को भी बिहार मॉडल अपनाने के लिए प्रेरित किया है. हालांकि हालात बिहार से थोड़े अलग हैं. वहां लालू प्रसाद का राजद लगातार दूसरी बार लोगों का विश्वास जीतने में नाकाम रहा, तो ममता बनर्जी और उनकी पहले वाली पार्टी कांग्रेस के साथ ऐसा छह बार से हो रहा है. पिछले तीन सालों से बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है और इसकी काट तैयार करना वाममोर्चा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. परिवर्तन का साफ़ सिग्नल देने वाले लोकसभा चुनावों के बाद दो–ढाई साल का समय बीता है. इस दौरान बंगाल के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे उलटफेर हुए हैं. महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे दो कारकों ने उस यूपीए सरकार के ख़िलाफ़ लोगों का गुस्सा भड़का दिया है, जिसकी तृणमूल एक अहम घटक है. बड़बोली ममता पर रेलवे के दुरुपयोग, माओवादियों से साठगांठ और नीतिविहीनता जैसे आरोप लग रहे हैं. ऐसे हालात ने बंगाल के चुनावों को और रोचक बना दिया है. यानी मैच कीनिया और पाकिस्तान की तरह एकतरफा नहीं, कांटे का होगा.

बीती 13 फरवरी को वाममोर्चा ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विशाल जनसभा कर अपनी ताक़त का प्रदर्शन किया और एक तरह से प्रचार अभियान की शुरुआत की. लाखों की तादाद देख थोड़ी घबराईं ममता ने इसे वाममोर्चे की विदाई जनसभा तक कह दिया और उसी जगह पर नई सरकार के शपथ लेने का ऐलान भी किया. ममता के इस आत्मविश्वास की हवा निकालना चाहता है मोर्चा. इसके लिए उसने कई क़दम उठाए हैं. पिछले लोकसभा चुनावों के बाद से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की जो भी समीक्षा बैठकें हुई हैं, उनमें तय हुआ है कि ग़लतियां हुई हैं, उन्हें स्वीकार कीजिए, लोगों से माफी मांगिए और यह महसूस कीजिए कि अभी भी पलट कर खड़े होने की गुंजाइश है. सो वाममोर्चा, ख़ासकर माकपा पलट कर खड़े होने के मूड में आ गई है. लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा? बिहार में तो कुछ क्षेत्रों में विकास साफ़ दिखा, पर बंगाल के पिछले पांच साल विध्वंसात्मक राजनीति के साल रहे. इस दौरान बंगाल विकास दर के मामले में भले ही न पिछड़ा हो, पर ठहराव तो साफ़ दिख रहा है. नैनो की विदाई हुई तो उद्योगपति बंगाल आने से बिदक गए. नई औद्योगिक नीति के तहत दनादन हुए क़रार की फाइलों पर गर्द जम गई है. बदलाव की हवा उठने से एक संदेश गया कि अब संक्रांति काल की अशुभ घड़ी में शुभ काम न करना ही ठीक है. बताने की ज़रूरत नहीं कि उद्योगपति वर्ग भी स्थिर राजनीतिक व्यवस्था चाहता है. उसका सोचना स्वाभाविक है कि दो ध्रुवों के बीच पिसने से अच्छा है कि कुछ इंतज़ार कर लिया जाए. यह रही नए उद्योगों की बात. बंद पड़े कारखानों को खोलने जैसे किसी बड़े क़दम का भी ऐलान नहीं हुआ. उत्तर बंगाल के चाय बागान श्रमिकों की बदहाली जस की तस है. माकपा की श्रमिक शाखा का उग्रपंथी रवैया नहीं बदला है. मिसाल के तौर पर हाल का एक छोटा सा उदाहरण लें. बीती 23 फरवरी को कोलकाता के दमदम रेलवे स्टेशन पर मोबाइल पर बतियाते हुए लेवल क्रासिंग पार कर रहा एक आदमी ट्रेन की चपेट में आ गया. इसके बाद सीटू की स्थानीय हॉकर यूनियन ने स्टेशन मास्टर सहित रेलवे कर्मियों को पीटा और कार्यालय में भी आग लगा दी. इस तरह लाखों की संपत्ति स्वाहा हो गई. क़ानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी सरकार को बदनामी झेलनी पड़ रही है. फरवरी के दूसरे सप्ताह में अपनी बहन को गुंडों के चंगुल से बचाने की कोशिश में बरासात के राजीव दास नामक युवक को जान गंवानी पड़ी. चुनावी मौसम की वजह से मुख्यमंत्री भी उसके घर गए और 2 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया. विपक्ष ने भी इस मामले पर ख़ूब राजनीति की.

गोरखालैंड आंदोलन भले ही धधक रहा हो, पर सरकार उत्तर बंगाल के डुआर्स में कुछ हिंदीभाषी स्कूल खोलने की घोषणा कर हिंदीभाषी आदिवासियों का दिल जीतने में ज़रूर कामयाब हुई है. अभी हाल में वाममोर्चा ने स्कूली लड़कियों की यूनीफार्म के लिए चार-चार सौ रुपये देने का ऐलान किया है. ज़ाहिर है, यह घोषणा बिहार में नीतीश की कामयाबी से प्रेरित होकर की गई है. माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य एवं प्रवक्ता मोहम्मद सलीम ने चौथी दुनिया को बताया, सरकार ने अपनी ग़लतियों को खुले तौर पर स्वीकारा है.

गोरखालैंड आंदोलन भले ही धधक रहा हो, पर सरकार उत्तर बंगाल के डुआर्स में कुछ हिंदीभाषी स्कूल खोलने की घोषणा कर हिंदीभाषी आदिवासियों का दिल जीतने में ज़रूर कामयाब हुई है. अभी हाल में वाममोर्चा ने स्कूली लड़कियों की यूनीफार्म के लिए चार–चार सौ रुपये देने का ऐलान किया है. ज़ाहिर है, यह घोषणा बिहार में नीतीश की कामयाबी से प्रेरित होकर की गई है. माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य एवं प्रवक्ता मोहम्मद सलीम ने चौथी दुनिया को बताया, सरकार ने अपनी ग़लतियों को खुले तौर पर स्वीकारा है. राजकीय, संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर भूलों को सुधारने की कोशिश हुई है. ग़लती मानने से गुस्सा कम होता है, इस मनोविज्ञान पर माकपा को पूरा भरोसा है. सलीम ने माना कि सरकार खेती के साथ उद्योगों पर ज़ोर देने की अपनी नीति पर क़ायम है. उद्योग ज़रूरी है, इसलिए ममता बनर्जी भी आजकल उद्योग चाहिए की रट लगा रही हैं. कुछ प्रतिशत वोटों का इधर–उधर होना कितना उलटफेर कर सकता है, इसका आकलन पेशेवर चुनाव विश्लेषक भी ठीक से नहीं कर पाते. राजनीतिक रूप से जागरूक बंगाल के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है. सवाल है कि माकपा से नाराज़ चल रहे लोगों का एक हिस्सा अगर फिर साथ हो गया तो हालात कितने बदल सकते हैं? आंकड़ों की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनावों में माकपा को सीटों का भले ही नुक़सान हुआ, पर उसके वोट प्रतिशत में थोड़ी ही कमी आई. माकपा की केंद्रीय कमेटी के बयान के मुताबिक़, पिछले लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी को 2004 के 5.33 प्रतिशत के मुक़ाबले केवल .33 प्रतिशत का ही नुक़सान हुआ, हालांकि सीटों का नुक़सान काफी हुआ. इस तरह 2004 की 43 सीटों के मुक़ाबले उसे सिर्फ़ 16 सीटें ही हासिल हो सकीं. कमेटी के बयान के मुताबिक़, 2009 के लोकसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में पार्टी को 1.85 करोड़ और केरल में 67.17 लाख वोट मिले, जबकि वाममोर्चा को बंगाल में 2004 के संसदीय चुनावों में 1.88 करोड़ मत मिले थे. इस तरह बंगाल में उसे सिर्फ़ 3 करोड़ वोटों का नुक़सान हुआ है. मत प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की वजह से वाममोर्चा को 2004 के 52.72 प्रतिशत के मुक़ाबले 2009 में 43.30 प्रतिशत ही वोट मिले और इस तरह उसे 7.42 प्रतिशत वोटों का नुक़सान हुआ. माकपा का अपने वोटों का हिस्सा भी 38.57 से 33.10 प्रतिशत पर आ गया. कोलकाता के आसपास की सारी सीटें वाममोर्चा हार गया, जिससे साबित होता है कि शहरी युवा और मुसलमानों के वोटों से भी माकपा को महरूम होना पड़ा है. ऐसे हालात में वाममोर्चा पलट कर खड़े होने की रणनीति के तहत दो बातें कर रहा है. वह युवाओं को संदेश दे रहा है कि ममता ने राज्य का औद्योगिक माहौल पूरी तरह तबाह कर दिया है. हर जनसभा में वह नैनो की विदाई का प्रसंग रख रहा है. युवाओं को यह भी बताया जा रहा है कि ज़्यादातर रेल परियोजनाएं हक़ीक़त में नहीं उतरने वालीं और इस संबंध में रेलवे की खस्ताहाल माली हालत का हवाला दिया जा रहा है.

वाममोर्चा ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित 7 प्रतिशत आरक्षण को 17 प्रतिशत कर दिया है और उसमें मुस्लिम समुदाय के पिछड़ों को भी शामिल किया है. मालदा में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा का शिलान्यास हो चुका है. ममता लहर में सत्ता में आई तृणमूल की पंचायतों के भ्रष्टाचार और नाकामी को भी वाममोर्चा ने मुद्दा बनाया है. वाममोर्चा कोलकाता नगर निगम पर क़ब्ज़ा करने वाली तृणमूल के कामकाज को भी लोगों के सामने रख रहा है और पूछ रहा है कि उसका प्रदर्शन वाममोर्चा बोर्ड के कामों से कितना अधिक या अच्छा है? इन सब कारकों के बूते उसे सत्ता विरोधी लहर रोकने का विश्वास है. मई में हो रहे चुनावों के परिणामों पर न केवल देश, बल्कि अमेरिका जैसे पूंजीवादी एवं चीन जैसे मार्क्सवादी देशों की भी नज़र है. एक वर्ग शुरू से ही यह जानने को उत्सुक रहा कि सोवियत संघ के विघटन के दौर में जब दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों से मार्क्सवाद की विदाई हो रही थी तो हर पांच साल पर बंगाल में वामपंथी सरकारें कैसे बनती रहीं? अब जब उसकी विदाई की हवा है तो लोगों की उत्सुकता और बढ़ गई है कि क्या यह वाकई संभव है? पूरे सात बार लगातार चुनकर आती रही वामपंथी सरकार अगर आठवीं बार भी शपथ लेती है तो यह सत्ता विरोधी लहर का भूत भगाने वाली एक ऐतिहासिक घटना होगी और वामपंथी आंदोलन को पूरे देश में नए सिरे से सिर उठाने का मौक़ा मिलेगा. ख़ैर, उपचुनावों एवं पंचायत चुनावों जैसे लीग मैचों का दौर कब का ख़त्म हो गया है. अब तो जंग नॉक आउट चरण में पहुंच गई है. पिछले तीन दशकों में जवान हो चुकी एक पूरी पीढ़ी बंगाल की सत्ता का कप किसे सौंपेगी, यह निर्णायक रूप से बताना भले ही संभव न हो, पर प्रबल दावेदार तो ममता को ही माना जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

फोटो–*देवज्योति चक्रवर्ती*

खंड प्रसार प्रशिक्षक से उनका मूल काम न लेकर लेखाकार का कार्य छह वर्षों से इसलिए लिया जा रहा है, क्योंकि वह शासकीय धनराशि के समायोजन में माहिर माने जाते हैं.

छत्तीसगढ़

फ्लोरेसिस ने पांव पसारे, सरकार बेख़बर

दूषित पेयजल ने क़रीब एक सैकड़ा लोगों का जीवन नारकीय बना दिया है. बड़ी संख्या में लोग विकलांगता की ओर अग्रसर हैं और सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि गांव-गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की तैनाती उसके दावे में शामिल है. यह हाल उस जगह का है, जहां से मात्र दो किलोमीटर की दूरी पर भाजपा सांसद और उनके पुत्र एवं राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का पैतृक निवास है.

रमेश थापक

बस्तर अंचल के संभाग मुख्यालय जगदलपुर से 47 किलोमीटर दूर स्थित आदिवासी बाहुल्य ग्राम बाकेल की आबादी 25 हज़ार है. दूषित पानी की आपूर्ति के चलते इस गांव के 72 लोग फ्लोरेसिस नामक ख़तरनाक बीमारी से पीड़ित हैं, पीड़ितों में महिलाओं और बच्चों की संख्या ज़्यादा है. ग़ौरतलब बात यह है कि यहां से क़रीब दो किलोमीटर की दूरी यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 जगदलपुर-रायपुर मार्ग के 45वें किलोमीटर पर भाजपा सांसद बलिराम कश्यप और उनके पुत्र एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री केदार कश्यप का गृहग्राम फरसागुड़ा है, जहां सांसद एवं उनके मंत्री पुत्र अक्सर आते-जाते रहते हैं.

इसी प्रकार बस्तर विकास खंड की खंडसरा पंचायत के ग्राम नौपारा में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से दो सौ से अधिक बच्चों के दांत काले, भूरे और पीले हो गए हैं और कमज़ोर होकर टूट-टूटकर झड़ रहे हैं. इस बीमारी की शुरुआत ऊपर के दांतों में धनुषाकार आकृति की तरह दाग़ पैदा होने के साथ होती है और फिर यह सभी दांतों को अपनी चपेट में ले लेती है. क्षेत्रीय जनता पिछले पांच-छह सालों से इस बीमारी से पीड़ित है, लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को इसकी कोई ख़बर नहीं है. वहीं दूसरी तरफ़ राज्य सरकार लोक स्वास्थ्य के बड़े-बड़े दावे करते नहीं थकती. स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी गांव-गांव में फैले हैं, बावजूद इसके सरकार इस बीमारी से अनभिज्ञ जान पड़ती है. लोग जानकारी और संसाधनों के अभाव में इधर-उधर भटकने के लिए मजबूर हैं.

स्थानीय दीप्ति हायर सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका रोशनी शिंदे एवं अनिल हर्जपाल के मार्गदर्शन में शुभेंदु राय, मोहनी पटेल, अनुपमा गौण, नंदनी सोनकेशरी एवं हिमांशु गुप्ता नामक छात्रों ने इस बात की जानकारी मिलने पर बाकेल का दौरा किया और लोगों से बातचीत करके बीमारी के कारणों का पता लगाया. इन छात्रों ने जब वहां पेयजल की जांच की तो उन्होंने पाया कि उसमें बड़ी मात्रा में फ्लोराइड है. इस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट जब स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार को भेजी तो हड़कंप मच और तब जाकर प्रशासन हरकत में आया. लेकिन नतीजे ने ढाक के वही तीन पात वाली कहावत को ही चरितार्थ किया. स्वास्थ्य विभाग की महिला सुपरवाइज़र कुमुदनी मांडावी, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता और उप अभियंता सुरेंद्र सिंह एवं आर एस साहू को निलंबित करके शासन ने अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली. जबकि पीड़ित लोगों के सहायतार्थ सरकार की ओर से कोई क़दम नहीं उठाया गया.

बाकेल गांव से छह किलोमीटर की दूरी पर भानुपरी में तीस बिस्तरों वाला एक शासकीय अस्पताल है और 25 किलोमीटर की दूरी पर बस्तर विकास खंड में खंड चिकित्सा केंद्र एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का कार्यालय है, जहां खंड चिकित्सा अधिकारी एवं खंड प्रसार प्रशिक्षक सहित स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा अमला कार्यरत है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि खंड प्रसार प्रशिक्षक से उनका मूल काम न लेकर लेखाकार का कार्य छह वर्षों से इसलिए लिया जा रहा है, क्योंकि वह शासकीय धनराशि के समायोजन में माहिर माने जाते हैं. जबकि असल में उनका काम क्षेत्र में योजनाओं की निगरानी और फैलने वाली बीमारियों के बारे में विभाग को तत्काल सूचित करना है. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अनु विभागीय अधिकारी एवं अन्य अमला भी बस्तर में तैनात है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वह शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. हालांकि इसके लिए कार्यपालन अभियंता ज्यादा ज़िम्मेदार है.

चिकित्सकों के अनुसार, फ्लोरेसिस नामक यह बीमारी पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण होती है. फ्लोराइडयुक्त पानी नियमित रूप से पीने अथवा ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से यह बीमारी दांतों से उत्पन्न होती है और फिर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती है. अधिक मात्रा होने पर मनुष्य की हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है और वह खड़े होने की स्थिति में भी नहीं रहता. चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, इस बीमारी का कोई उपचार नहीं है. फ्लोराइडयुक्त पानी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पाया जाता है, जिसमें बस्तर भी शामिल है. सरकार शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए करोड़ों रुपये व्यय कर रही है और इस कार्य के लिए अलग से एक मंत्रालय भी बनाया गया है. संयोग से उसके मंत्री प्रभावित क्षेत्र के क़रीब के रहने वाले हैं.

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का काम नलकूप खनन करके परीक्षण के उपरांत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है, लेकिन पिछले 5-6 वर्षों से जनता फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर है. इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमारी से ग्रस्त हैं. जल का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया, जबकि विभाग का यह प्रथम कर्तव्य है, इस सवाल का जवाब कार्यपालन यंत्री से लेकर मंत्री तक किसी के पास नहीं है. इतनी बड़ी संख्या में लोगों के इस बीमारी से पीड़ित होने पर मचे बवाल पर पर्दा डालने के लिए कलेक्टर ने दो कार्यपालन यंत्रियों की रिपोर्ट पर विभाग के दो उप यंत्रियों सुरेंद्र सिंह और आर एस साहू को निलंबित कर दिया और बिना कोई आरोपपत्र दिए 45 दिनों के बाद बहाल भी कर दिया. जबकि मुख्य रूप से कार्यपालन यंत्री ही ज़िम्मेदार होता है. उप यंत्रियों को मोहरा बनाकर शेष दोषी लोगों को बचा लिया गया और मामले पर राख डाल दी गई. जब यह स्थिति विभागीय मंत्री के गृहग्राम के बगल के गांव की है तो राज्य के अन्य दूसरे इलाक़ों का क्या हाल होगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है.

पंचायतों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं. गांव की समस्याएं कैसे हल करनी हैं, यह काम उन पर छोड़ दिया गया है. पांच वर्ष पूर्व विभाग द्वारा पानी के परीक्षण के लिए किटें बांटी गई थीं, किंतु पंचायत पदाधिकारियों ने बिना निजी फ़ायदे के इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली. अंचल की पंचायतों के सचिव सरपंचों की अशिक्षा का भरपूर लाभ उठाते हैं. उनका ध्यान जनसमस्याओं के निराकरण में कम और शासकीय धनराशि को हड़पने में ज़्यादा रहता है. समस्याएं उत्पन्न होने का एक कारण यह भी है. देश में भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक नासूर की तरह फैल गया है, जिसका असर संसद से लेकर गांव तक देखा जा रहा है. यही वजह है कि पंचायतों में भी शासकीय धन की बेख़ौफ़ बंदरबांट हो रही है नेता और अधिकारी एक-दूसरे को बचाने में लगे रहते हैं. जनता की शिक़ायत पर कहीं कोई सुनवाई नहीं होती. पीएचई का अमला भी मूल काम के बजाय शासकीय धन के समायोजन में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है. स्वास्थ्य विभाग की निष्क्रियता का हाल यह है कि यहां हर कोई मुफ्त का वेतन उठाना चाहता है और शासकीय राशि हड़पने की योजना में जुटा रहता है.

दूषित पानी पीने से 19 लोग विकलांग हो गए हैं. उन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने फ्लोरेसिस प्रभावित मानकर प्रमाणित किया है. लेकिन इनकी ज़िंदगी कैसे बसर होगी, इस ओर न विभाग और न सरकार की तरफ़ से मदद के कोई संकेत हैं. तीन से लेकर 11 वर्ष तक के इन बच्चों के सामने पहाड़ सा जीवन है. विकलांग बच्चे जब वयस्क होंगे तो उनसे विवाह कौन करेगा? वे अपना जीवनयापन कैसे करेंगे? ऐसे तमाम सवाल लोगों के सामने मुंह बाए खड़े हैं. 11 वयस्क लोग भी इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसमें तीन महिलाएं और आठ पुरुष हैं. विकलांगता के चलते प्रजनन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है. नक्सलवाद की वजह से आदिवासियों की जनसंख्या में काफी कमी आई है. हंगामे के बाद इस बीमारी की रोकथाम के लिए शासन ने बाकेल में फ्लोराइड रिमूवल संयंत्र लगाए हैं. फ्लोराइड प्रभावित ग्राम संघ करमरी, धुरावंड, तुरपुरा, केशरपाल, कुम्हली, सलना बबई, बावनी मारी और चंदेली में भी संयंत्र लगाने के लिए 42 लाख रुपये की प्रथम किस्त जारी की गई है, लेकिन विकलांगों को किसी प्रकार के मुआवज़े अथवा शासकीय मदद की कोई ख़बर नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... रामदेव का नया आसन! ...धीर

गांव में बदलाव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है शराब की खपत में कमी. लोगों का शराब पीना और फिर पत्नी-बच्चों के साथ मारपीट करना आम बात थी और शायद इस बुराई ने इलांगो को गांव लौटने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था.

कुटुंबक्कम

एक गांव, जो विकास का मॉडल है

गांव जिस तरह अंग्रेजों के समय में ग़ुलाम थे, आज भले ही वैसे न हों, लेकिन स्थिति बेहतर हुई हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता. सरकार ने जो हुक्म दे दिया, वह ग्रामसभा का काम है और जो हुक्म नहीं दिया, वह ग्रामसभा का काम नहीं. क़ानून व्यवस्था अंग्रेजों ने इसलिए बनाई थी कि उनका साम्राज्य कभी टूटे नहीं. आज़ादी के बाद भी गांवों की स्थिति कमोबेश वही बनी रही, लेकिन इस सबके बीच उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही है. तमाम क़ानूनी पेचीदगियों के बाद भी कुछ गांव ऐसे हैं, जो ग्रामसभा के ज़रिए विकास की नई इबारत लिख रहे हैं. ऐसा ही एक गांव है कुटुंबक्कम.

शशि शेखर

वर्ष 1857 के आंदोलन को अंग्रेजों ने किसी तरह दबा तो दिया, लेकिन यह बात उनकी समझ से बाहर थी कि आख़िर यह सब हुआ कैसे. यह आंदोलन कैसे हुआ, कैसे इतना फैला और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी. ये सारी बातें समझने के लिए अंग्रेजों ने एक आयोग बनाया, जिसकी अध्यक्षता सर ए ओ ह्यूम को सौंपी गई. आयोग दो–तीन सालों तक जगह–जगह घूमा. जब जांच चल रही थी तो कुछ बातें चौंकाने वाली लगीं. आयोग ने कहा कि भारत में गांव एक समाज है, जो अपनी व्यवस्था स्वयं करता है. वह किसी पर निर्भर नहीं है. यदि कोई अकस्मात बात होती है या ख़तरा आता है तो गांव समाज उसका प्रतिकार करता है. ए ओ ह्यूम ने भी कहा कि यह समाज ऐसा है कि जब कोई संकट आता है तो एक हो जाता है और उसके बाद फिर अपने–अपने काम में लग जाता है. जब तक इस देश में गांव समाज को ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक आपका साम्राज्य स्थायी नहीं रह सकता. इस प्रकार का विद्रोह आपको झेलना ही पड़ेगा. नतीजतन, 1860 के बाद जितने भी क़ानून बने, उनमें से किसी में भी गांव समाज को कोई स्थान नहीं दिया गया. ऐसा कोई क़ानून नहीं, जिसमें गांव समाज की कोई भूमिका हो. आपस में झगड़ा हो जाए तो अदालत और न्याय पंचायत आदि बना दी गई. आप आपस में बात करके झगड़ा सुलझा सकते हैं, पर क़ानूनन सुलझा नहीं सकते. इसके लिए पुलिस है, अदालत है. गांव में जितने भी काम हैं, राज्य को दे दिए गए. हां, आज़ादी मिलने के लंबे समय के बाद पंचायती राज व्यवस्था के लिए क़ानून ज़रूर बने, लेकिन वे भी प्रशासन की अंतिम इकाई यानी गांवों तक पहुंचते–पहुंचते अपना अर्थ खोने लगे. ग्रामसभा नामक संवैधानिक संस्था को पंगु और निष्क्रिय बनाने की भरपूर कोशिश की गई और ऐसा करने वाले अपने मक़सद में सफल भी रहे.

फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, जो वर्तमान नियम–क़ानूनों के तहत ही लोकतांत्रिक ढंग से काम और ग्रामसभा की ताक़त का इस्तेमाल करते हुए अपने गांव की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं. तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से क़रीब 40 किलोमीटर दूर बसा गांव कुटुंबक्कम पिछले 15 सालों से ग्राम स्वराज के रास्ते पर चल रहा है. 15 साल पहले तक यहां हर वह बुराई थी, जो देश के किसी भी अन्य गांव में देखी जा सकती है. शराब पीना, घर में मारपीट, गांव में आपसी झगड़े, छुआछूत एवं गंदगी आदि. गांव में 50 फ़ीसदी आबादी दलितों की है, लेकिन जातियों के बंटवारे इतने गहरे थे कि नीची कही जाने वाली जातियों को कुछ रास्तों पर आने–जाने, कुओं से पानी लेने आदि तक की अनुमति नहीं थी. और, इन सबके चलते एक बर्बाद गांव. हर तरफ़ बेरोज़गारी और ग़रीबी की मार, लेकिन आज इस गांव में आपस के झगड़े लगभग मिट गए हैं. जातियों की दीवारें अब काफी छोटी हो गई हैं. अब वही परिवार एकदम पड़ोस में रह रहे हैं, जो कल तक नीची और ऊंची जाति के झगड़े में उलझे थे. यहां तक कि गांव में अंतरजातीय विवाह भी हुए हैं. शराब पीकर घर में मारपीट करने का चलन अब थम चुका है.

सवाल यह उठता है कि ये हुआ कैसे? इसका श्रेय गांव के पूर्व सरपंच रंगास्वामी इलांगो को दिया जा सकता है. इलांगो एक सफल वैज्ञानिक थे, लेकिन वह 1996 में अच्छी–ख़ासी नौकरी छोड़कर अपने गांव में पंचायत का चुनाव लड़े और जीत भी गए. 15 साल पहले के कुटुंबक्कम गांव का आज के कुटुंबक्कम में परिवर्तन यहीं से शुरू होता है, लेकिन अगर इसे गांव के एक होनहार नौजवान के व्यक्तित्व का चमत्कार और उसकी ऊंची पढ़ाई–लिखाई को इसका आधार मानकर छोड़ दिया जाए तो शायद इलांगो के 15 साल व्यर्थ हो जाएंगे तथा देश के हर गांव में लोग यही दुआ करते रह जाएंगे कि इलांगो जैसा कोई होनहार उनके गांव में भी पैदा हो जाए. कुटुंबक्कम में आए बदलाव को हमें किसी व्यक्ति से ऊपर उठकर इस रूप में समझना पड़ेगा कि यहां क्या–क्या हुआ और कैसे हुआ? शुरुआत तो 1996 में इलांगो के सरपंच बनने से हुई. इलांगो एक दलित परिवार से हैं और बचपन में गांव में झेले गए भेदभाव ने उनके मन में गहरा असर छोड़ा था. वह एक सपना लेकर अपने गांव आए थे, लेकिन एक ऐसे गांव, जिसे जातिपात, शराबखोरी, ग़रीबी एवं बेरोज़गारी जैसी बीमारियों ने हर तरह से तोड़ रखा हो, वहां के लोगों को विकास का सपना दिखाना मुश्किल काम था. फिर भी इलांगो ने गांव के ऊपर अपना सपना नहीं लादा. गांववालों के साथ बैठकर चर्चा से शुरुआत की. इलांगो की ताक़त थी कि उन्होंने पंचायत चुनाव जीतने के लिए न पैसा ख़र्च किया और न शराब बांटी. धीरे–धीरे लोग ग्रामसभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित हुए. इलांगो ने गांव के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई और उस पर गांव में जमकर चर्चा हुई. यह चर्चा एक बैठक तक सीमित नहीं थी, बल्कि वार्ड स्तर पर भी इसके लिए बैठकें आयोजित की गईं. इन बैठकों में आए सुझावों के आधार पर पंचवर्षीय योजना में सुधार किए गए और इस पर काम शुरू हुआ. पूरी पारदर्शिता और हर काम के बारे में खुली बैठकों में चर्चा से लोग पंचायत के कामकाज में दिलचस्पी लेने लगे.

लेकिन सरकारी अधिकारियों–कर्मचारियों का रवैया एक चुनौती था. गांव से लेकर ज़िले तक के अधिकारियों–कर्मचारियों को जब किसी काम से कमीशन नहीं मिला तो वे कुपित होने लगे. नतीज़ा यह निकला कि इलांगो को काग़ज़ों में घेरने की कोशिश की गई. उन पर पंचायत का काम योजना के हिसाब से न कराने के आरोप लगे. ग़ौरतलब बात यह थी कि इलांगो इन सभी मुद्दों पर ग्रामसभा की खुली बैठकों में चर्चा करते थे. अधिकारियों को रिश्वत न देने का परिणाम यह हुआ कि एक मामले में इलांगो को निलंबित कर दिया गया. मामला यह था कि गांव में एक नाली का निर्माण होना तय हुआ और सरकार से इसके लिए 4 लाख 20 हज़ार रुपये का बजट मिला. गांव वालों ने पास की एक फैक्ट्री से बचे ग्रेनाइट पत्थरों को इस्तेमाल करके यह काम मात्र 2 लाख 20 हज़ार रुपये में पूरा कर लिया. जबकि सरकारी योजना के मुताबिक़ उक्त पत्थर पड़ोस के एक स्थान से मंगाए जाने थे. इससे सरकारी पैसा भी बचा और काम भी जल्दी हो गया, लेकिन अधिकारियों ने इसे भ्रष्टाचार माना और इलांगो को निलंबित कर दिया. यहां पर इलांगो का साथ दिया गांधी के प्रयोगों ने. उन्होंने इसका शांति से विरोध किया. नतीज़ा मुख्यमंत्री के आदेश पर ग्रामसभा की बैठक हुई और 2000 लोगों ने इलांगो के पक्ष में वोट दिया. इसके बाद फिर से चुनाव हुए और इलांगो वापस अपने गांव के सरपंच बन गए. इस घटना के दौरान आई एकता ने गांव में जातियों की दीवार को नीचा किया और तब एक और सामाजिक प्रयोग की ज़मीन तैयार हुई. मुख्यमंत्री से मिलकर इलांगो ने ग़रीब परिवारों के लिए एक ऐसी कॉलोनी बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें हर दलित और ग़ैर दलित परिवार को एक–एक घर मिले. यह कॉलोनी सफलतापूर्वक बन गई और आज लोग इसमें अभूतपूर्व मेल–मिलाप से रहते हैं. इसके घर बेहद सस्ती तकनीक एवं सौर ऊर्जा के उपयोग के हिसाब से बनाए गए हैं. गांव में बदलाव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है शराब की खपत में कमी. लोगों का शराब पीना और फिर पत्नी–बच्चों के साथ मारपीट करना आम बात थी और शायद इस बुराई ने इलांगो को गांव लौटने के लिए सबसे ज़्यादा प्रेरित किया था. सरपंच बनने के बाद इलांगो ने इसके लिए पुलिस और मीडिया का तो सहारा लिया ही, नुक्कड़ नाटकों का इस्तेमाल भी किया. चेन्नई के लोयोला कॉलेज के छात्रों की टीम ने गांव में शराब के नुक़सान पर आधारित कई नाटकों का मंचन किया. धीरे–धीरे लोगों को लगा कि वे ग़लत कर रहे हैं और तब यह बुराई ख़त्म हुई. इसके अलावा सड़कों का निर्माण, ग़रीबों के लिए घर एवं रोज़गार के सम्मानित विकल्प आदि ऐसे काम हैं, जो अब इलांगो ही नहीं, गांव वालों के भी सपने बन गए हैं और इस पर काम भी हो रहा है. गांव में 60 फ़ीसदी महिलाएं पढ़ी–लिखी हैं, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं. इसलिए बाल मज़दूरी जैसी बुराइयों का भी ख़ात्मा हो सका.

बीते 15 सालों में और भी कई ऐसे सफल काम हुए, जिनकी सूची बनाई जा सकती है. अब गांव के लोग इलांगो के साथ मिलकर एक और सपना देख रहे हैं और वह है आर्थिक आत्मनिर्भरता का सपना. इस सपने का आधार है यह विश्वास कि आसपास के 10–15 किलोमीटर क्षेत्र में आने वाले गांवों के लोगों की सभी ज़रूरतें स्थानीय स्तर पर ही पूरी हो सकती हैं यानी खाने–पीने से लेकर जीने के लिए ज़रूरी हर वस्तु. रंगास्वामी इलांगो और उनकी टीम अब इस सपने को साकार करने में जुटी हुई है.

shashishekhar@chauthiduniya.com

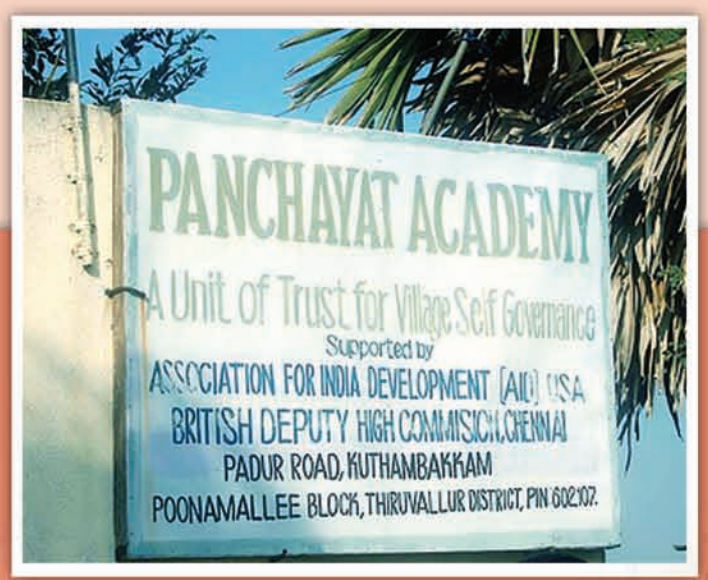

एक ऐसे गांव, जिसे जातिपात, शराबखोरी, ग़रीबी एवं बेरोज़गारी जैसी बीमारियों ने हर तरह से तोड़ रखा हो, वहां के लोगों को विकास का सपना दिखाना मुश्किल काम था. फिर भी इलांगो ने गांव के ऊपर अपना सपना नहीं लादा. गांववालों के साथ बैठकर चर्चा से शुरुआत की. इलांगो की ताक़त थी कि उन्होंने पंचायत चुनाव जीतने के लिए न पैसा ख़र्च किया और न शराब बांटी. धीरे-धीरे लोग ग्रामसभा की बैठकों में आने के लिए प्रेरित हुए. इलांगो ने गांव के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई और उस पर गांव में जमकर चर्चा हुई.

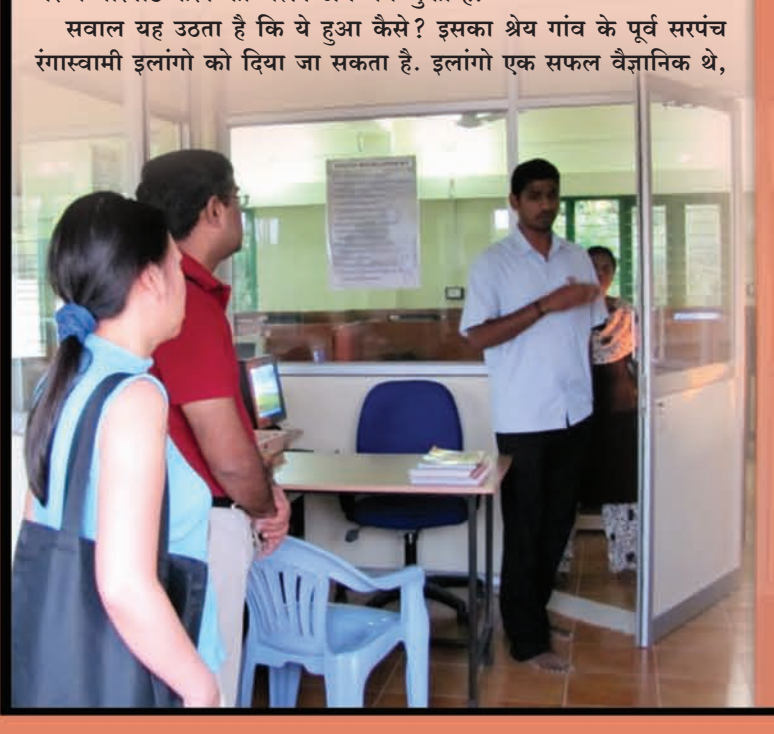

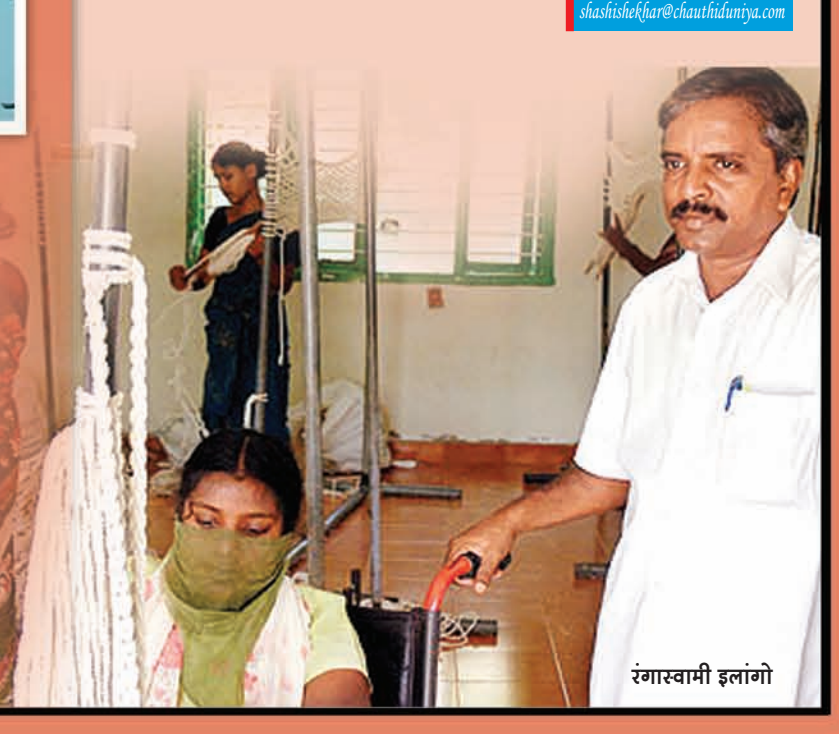

रंगास्वामी इलांगो

विपक्ष किसी भी प्रकार के हथकंडे प्रयोग करके कांग्रेस, विशेषकर सोनिया गांधी और उनके परिवार को बदनाम करने पर आमादा है, ताकि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए और उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए उसकी राह आसान हो जाए.

भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स 2008 के अनुसार, भूख के मामले में गुजरात उड़ीसा से भी पीछे है. इसमें 17 बड़े राज्यों में गुजरात का स्थान 13वां है.

मेघनाद देसाई

मुस्लिम जगत का पुनर्जागरण काल

मध्य पूर्व में गदर करने वाले डटे हुए हैं. ट्यूनीशिया और मिस्र के दो तानाशाहों के ताज अब तक उछाले जा चुके हैं, तख़्त गिराए जा चुके हैं. यमन, बहरीन, लीबिया, अल्जीरिया एवं ईरान में हलचल जारी है. रूढ़िवादी मुस्लिम समाज अब पूरी तरह से बदल रहा है. ईरान, बहरीन एवं लीबिया की सड़कों और गलियों में पर्दानशीं मुस्लिम महिलाएं आज़ादी के लिए नारे लगाते दिख रही हैं. शिया और सुन्नी के बीच स्थित मतभेदों का इस्तेमाल इन देशों के शासक अपना शासन बचाए रखने में करते रहे हैं. सड़कों पर उतर रहे लोगों को देखकर उक्त सारे मतभेद भी इस बार महत्वहीन होते दिख रहे हैं. आख़िर यह सब क्या चल रहा है?

दरअसल, 15वीं शताब्दी में यूरोप में मुस्लिम आधिपत्य धीरे-धीरे कम होता गया, तब उन्हें स्पेन से खदेड़ दिया गया था. 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच यूरोप और एशिया की सीमा तक फैले ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एवं मध्य एशिया में फैले मुगल साम्राज्य ने मुसलमानों को एक ऐसा एहसास दिया, जिस पर वे गर्व कर सकें. 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुग़लों का पराभव शुरू हो गया और इसी समय यूरोप में पुनर्जागरण की वजह से ऑटोमन साम्राज्य भी बिखरने लगा. राजनीतिक सौभाग्य के इसी पतन ने मुस्लिम मानसिकता को अपने रंग में रंग लिया. जैसा कि एम जे अकबर ने अपनी किताब टिंडर बॉक्स में बताया है, औरंगज़ेब की मौत के ठीक बाद ही भारत में मुस्लिम प्रतिरोध दिखना शुरू हो गया था. शुरुआत में तो यह मुस्लिम शासन के अंत का परिणाम दिख रहा था, लेकिन बाद में यह सैयद अहमद बरेलवी के पश्चिम विरोधी आंदोलन के रूप में भी दिखा. इस सबके लिए कुरान के मूलभूत सिद्धांतों और पैग़ंबर द्वारा बताए गए रास्तों को अपनाया गया. भारत में यह दारूल उलूम की स्थापना का आधार बना. एक ऐसा राष्ट्रवादी मकतब, जो शुरू से ही उदारवादी रहा.

मध्य पूर्व में ऑटोमन साम्राज्य की हार के बाद जो पहला आंदोलन हुआ, वह अतातुर्क ने किया यानी एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन, जो धर्म विरोधी था. तुर्की का आधुनिकीकरण और ख़लीफ़ा का अंत हुआ. ब्रिटेन और फ्रांस ने हस्तक्षेप करके कुछ शासकों को सीरिया, इराक़ और जॉर्डन में सत्ता दिला दी. द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जल्दी ही बाथ पार्टी से जुड़े सेकुलर और समाजवादी नेताओं ने कई देशों को नेतृत्व दिया, कुछ देशों में सत्ता भी संभाला. इज़रायल के साथ हुए तीन युद्धों में इन अरब नेताओं की हार ने ही आधुनिकता और पश्चिमीकरण की राह अवरुद्ध कर दी. उक्त सभी अरब नेता कमाल अतातुर्क की तरह अनीश्वरवादी और नास्तिक थे. इसके बाद हमें वहाबी आंदोलन का पुनरुद्भव देखने को मिला और साथ ही यह भी कि कैसे इस्लाम का एक सख़्त प्रारूप धीरे-धीरे सामने आया.

> **अरब के तानाशाह वहाबीवाद को लेकर थोड़े असहज रहते थे, जबकि सऊदी के राजा ने इसे बढ़ावा दिया. इन्हीं वजहों ने ओसामा बिन लादेन और 9/11 जैसी घटनाओं को जन्म दिया. तबसे पश्चिम के देशों में मुसलमानों की पहचान रूढ़िवादी और कट्टर वहाबी अलक़ायदा से जुड़ने लगी. यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसने आधुनिक तकनीक का ख़ुद तो इस्तेमाल किया, लेकिन मुस्लिम जगत के लिए आधुनिकता का कड़ा विरोध किया.**

अरब के तानाशाह वहाबीवाद को लेकर थोड़े असहज रहते थे, जबकि सऊदी के राजा ने इसे बढ़ावा दिया. इन्हीं वजहों ने ओसामा बिन लादेन और 9/11 जैसी घटनाओं को जन्म दिया. तबसे पश्चिम के देशों में मुसलमानों की पहचान रूढ़िवादी और कट्टर वहाबी अलक़ायदा से जुड़ने लगी. यह एक ऐसा आंदोलन था, जिसने आधुनिक तकनीक का ख़ुद तो इस्तेमाल किया, लेकिन मुस्लिम जगत के लिए आधुनिकता का कड़ा विरोध किया. उन सभी देशों में जहां मुस्लिम बहुमत में हैं, कट्टरवादियों ने शरिया कानून के नाम पर एक तरह से आधुनिकता के ख़िलाफ़ लड़ाई छेड़ दी. पाकिस्तान, जिसे अपने उद्भव के लिए जिन्ना और सर सैयद अहमद ख़ान जैसे आधुनिक सोच रखने वाले मुसलमानों का शुक्रगुज़ार होना चाहिए, भी मुस्लिम देशों में इन कट्टरवादियों द्वारा चलाए जा रहे युद्ध से प्रभावित हो रहा है. आज जो अरब देशों की सड़कों और गलियों में हो रहा है, वही असल विद्रोह है. तानाशाहों और रूढ़िवादियों के ख़िलाफ़ एक बग़ावत.

इन लोगों द्वारा अपनी आज़ादी की मांग असल में देरी से उठाया गया एक कदम है. इनसे अलग कई समाज काफ़ी पहले से इस आज़ादी का आनंद ले रहे हैं. पश्चिमी आधुनिकता का वह बाकी अनुबंध अब अरब के देशों में लागू हो सकता है. मानवाधिकार असल में पश्चिमी उदारवादी परंपरा का एक भाग है. ज़ाहिर है, दुनियाभर की महिलाओं का संबंध भी मानवाधिकार के इस मूल्य से जुड़ा हुआ है. भारत में धर्मनिरपेक्षवाद ने सरकार को उन ताकतों को ही मदद पहुंचाने की ओर आगे बढ़ाया है, जो मुस्लिम समुदाय में आधुनिकता के प्रवेश को रोकते हैं. नतीजतन, इस समुदाय में निरंतर अभाव की स्थिति देखी जा सकती है. जब प्रोफ़ेसर वस्तानवी देवबंद में आधुनिक शिक्षा प्रणाली लाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी नियुक्ति को ही रद्द करने की बात चली. वस्तानवी के इस क़दम का विरोध उन लोगों ने किया, जो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज आधुनिक शिक्षा के जरिए अपनी आजादी सुनिश्चित कर सके. हां, वे यह ज़रूर चाहते हैं कि अभी भी मुस्लिम समाज मुल्लाओं के चंगुल में ही रहे. ज़ाहिर है, अरब की गलियों या देवबंद में चल रहा संघर्ष एक ही है.

feedback@chauthiduniya.com

काला धन बनाम राजनीतिक हथकंडे

तनवीर जाफ़री

भारत दुनिया की नज़रों में 15 अगस्त, 1947 को स्वतंत्र हो गया था. उस समय हमारे नेताओं, अधिकारियों एवं देशभक्तों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी इस विशाल राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना. वहीं दूसरी तरफ़ देश के अंदर वे शक्तियां भी सक्रिय हो उठीं, जिन्हें भारत की आत्मनिर्भरता और आम जनता से ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि वे किस प्रकार कम समय में अधिक धन-संपत्ति का संग्रह कर सकें. इन्हीं राष्ट्रविरोधी ताक़तों ने आज़ादी मिलने के तुरंत बाद देश को लूटना और बेचना शुरू कर दिया. देशवासी 1947 के बाद और उससे पहले की स्वतंत्रता से जुड़ी तमाम घटनाओं से वाक़िफ़ हैं तथा वे उसी समय से यह जानते-सुनते आ रहे हैं कि देश के कई नेताओं, अधिकारियों, व्यापारियों एवं जमाख़ोरों का पैसा स्विट्ज़रलैंड अथवा स्विस बैंकों में जमा है. अब तो लोगों को मीडिया के माध्यम से यह भी पता चल गया है कि स्विस बैंकों की तरह खाता संबंधी पूर्ण गोपनीयता बरतने का काम पश्चिमी देशों के कई अन्य बैंकों में भी किया जा रहा है, लिहाज़ा ऐसा काला धन केवल स्विस बैंकों में ही नहीं, बल्कि कई और भी कई विदेशी बैंकों में जमा हो सकता है.

भारतीय अर्थव्यवस्था, यहां व्याप्त ग़रीबी एवं बेरोज़गारी, क़ायदे-क़ानून और अपनी ज़रूरत के लिए विदेशी बैंकों से समय-समय पर क़र्ज़ लेते रहने के हालात निस्संदेह किसी भी भारतीय नागरिक को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वह अपने धन को देश के बैंकों में जमा करने के बजाय विदेशी बैंकों में जाकर जमा करे. यह भी केवल इसलिए कि उसका धन नाजायज़ और ग़लत तरीक़ों से इकट्ठा किया गया धन है, जिसे वह दुनिया की नज़रों से सिर्फ़ इसलिए छुपाकर रखना चाहता है कि एक तो उसका धन सुरक्षित रह सके, दूसरे यह कि वह भारतीय विधिक क़ानून से बचा रह सके और तीसरी बात यह कि वह स्वयं को बदनामी से बचाए रख सके. देखा भी यही जा रहा है कि काला धन जमा करने वाले पश्चिमी देशों के इन बैंकों में गोपनीयता बरक़रार रखने के ऐसे ऊंचे पैमाने निर्धारित किए गए हैं कि कम से कम अभी तक तो किसी खातेदार और उसकी कुल जमाराशि का खुलासा होते नहीं सुना गया. अगर कल को विकीलीक्स जैसी किसी वेबसाइट अथवा अन्य किसी खोजी पत्रकारिता के चलते कुछ नाम उजागर हो जाएं तो यह अलग बात है. ऐसे बैंक काले धन को भी अपने ग्राहक के परिश्रमिक करते हैं. भारत में पिछले कुछ महीनों से विदेशी बैंकों में जमा काले धन का मुद्दा इस क़दर गरमाया हुआ है कि ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे इस विषय पर हंगामा बरपा करने वालों को पता चल चुका है कि किसका कितना धन किस देश के बैंक में जमा है.

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत के आर्थिक हालात क़तई ऐसे नहीं हैं कि यह ऐसे नकारात्मक आर्थिक वातावरण का सामना कर सके. भारत सरकार को इस विषय पर पूरी गंभीरता से काम करना चाहिए और विदेशों में जमा काला धन देश में वापस लाने का प्रयास करना चाहिए. ऐसे ग़ैरक़ानूनी कामों में लिप्त लोगों को, चाहे वे कितनी ही ऊंची हैसियत रखने वाले क्यों न हों, क़ानून के अनुसार सख़्त सज़ा दी जानी चाहिए. ऐसे लोगों के नाम भी उजागर किए जाने चाहिए, ताकि जनता यह समझ सके कि नेता, अभिनेता, अधिकारी, समाजसेवी, धर्मगुरु अथवा व्यापारी के रूप में दिखाई देने वाला यह व्यक्ति वास्तव में वह नहीं है, जो दिखाई दे रहा है, बल्कि यह देश का सबसे बड़ा दुश्मन है. अवैध धन की जमाख़ोरी करने वाले यही वे लोग हैं, जिनके कारण भारत को ग़रीब देश कहा जाने लगा है. विदेशों में जमा काले धन के मुद्दे को लेकर मची हाय-तौबा की आड़ में तमाम भारतीय नेता, राजनीतिक दल और राजनीति में प्रवेश की इच्छा रखने वाले नए चेहरे ऐसे तर्क एवं दलीलें पेश कर रहे हैं, जिनसे यह गंभीर मुद्दा अपने रास्ते से भटकता दिखाई देने लगा है. यह भी साफ़ ज़ाहिर होने लगा है कि इस मुद्दे को लेकर किए जाने वाले हंगामे का मक़सद विदेशों से काले धन की वापसी कम, राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति या दल विशेष को बदनाम करना अधिक है. संभवतः ऐसे लोग भलीभांति जानते हैं कि देश की जनता ऐसी अफ़वाहों पर जल्दी विश्वास कर लेती है और इनके पीछे भागने लगती है. 1986-87 के मध्य का वह दौर राजनीतिज्ञों के लिए एक उदाहरण बन चुका है, जबकि आरोप जड़ने और दूसरों को बदनाम करने में महारत रखने वाले तत्कालीन महारथियों ने बोफ़ोर्स तोप सौदे में कथित दलाली के मुद्दे पर राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन एवं अजिताभ बच्चन सहित कई लोगों को अपने अनर्गल आरोपों के घेरे में ले लिया था. परिणामस्वरूप कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था और भारत में गठबंधन सरकार का दौर उसी समय से ही शुरू हुआ. भारतीय जनता पार्टी बार-बार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है कि वह काले धन के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती. भाजपा ने इस विषय में छानबीन के लिए एक टास्क फ़ोर्स का गठन भी किया, जिसने यह दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष एवं यूपीए प्रमुख सोनिया गांधी स्वयं विदेशों में काला धन जमा करने जैसे ग़ैर क़ानूनी मामलों में लिप्त हैं तथा इनके कई विदेशी बैंकों में खाते हैं. टास्क फ़ोर्स यह पता लगा रही है कि किन-किन लोगों का कितना धन किस देश के बैंकों में जमा है. इस सिलसिले में अपना और स्वर्गीय राजीव गांधी का नाम लिए जाने पर सोनिया गांधी ने भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को पत्र लिखा और कड़ी आपत्ति जताई. सोनिया ने कहा कि किसी भी विदेशी बैंक में उनका कोई खाता नहीं है. जवाब में आडवाणी ने भी सोनिया को पत्र लिखा कि इस मामले में उनके परिवार का ज़िक्र किया गया, इसके लिए उन्हें खेद है. आडवाणी ने कहा कि गांधी परिवार की ओर से इस तरह की सफ़ाई पहले ही दी गई होती तो अच्छा रहता.

> **आडवाणी द्वारा सोनिया गांधी से माफ़ी मांगना या भाजपा द्वारा सोनिया के विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार के लिए खेद जताना निश्चित रूप से शिष्ट राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है. शीर्ष नेताओं के बीच पत्रों के माध्यम से अथवा टेलीफ़ोन पर होने वाली वार्ताएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, परंतु किसी ठोस प्रमाण के बिना सोनिया गांधी, राजीव गांधी या किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाना आख़िर कहां की नैतिकता है?**

आडवाणी द्वारा सोनिया गांधी से माफ़ी मांगना या भाजपा द्वारा सोनिया के विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार के लिए खेद जताना निश्चित रूप से शिष्ट राजनीति का हिस्सा माना जा सकता है. शीर्ष नेताओं के बीच पत्रों के माध्यम से अथवा टेलीफ़ोन पर होने वाली वार्ताएं अक्सर प्रकाश में आती रहती हैं, परंतु किसी ठोस प्रमाण के बिना सोनिया गांधी, राजीव गांधी या किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाना आख़िर कहां की नैतिकता है? सोनिया गांधी या मनमोहन सिंह यदि क़सूरवार हों अथवा उनके विरुद्ध ठोस प्रमाण हों, तब अवश्य उन्हें आलोचना का शिकार बनाया जा सकता है, और उनके विरुद्ध क़ानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन देश की जनता को गुमराह करना, ज़िम्मेदार राजनीतिक नेताओं पर लांछन लगाकर अपने और अपने दल के नेताओं पर लगे काले धब्बों को छुपाने का प्रयास करना सरासर अनैतिक है. बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप से साफ़ ज़ाहिर होता है कि विपक्ष किसी भी प्रकार के हथकंडे प्रयोग करके कांग्रेस, विशेषकर सोनिया गांधी और उनके परिवार को बदनाम करने पर आमादा है, ताकि कांग्रेस कमज़ोर हो जाए और उसे सत्ता तक पहुंचने के लिए उसकी राह आसान हो जाए.

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

गीत, ग़ज़ल और कविता

चौथी दुनिया के साहित्य पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाली सामग्री ज्ञानवर्द्धक होती है. साहित्य की विभिन्न विधाओं में लिखने वाले नए एवं प्रतिष्ठित लेखकों-रचनाकारों के साक्षात्कार पाठकों के लिए लाभप्रद होते हैं. अगर आप इस पृष्ठ पर व्यंग्य, गीत, ग़ज़ल और कविताओं को भी स्थान दे सकें तो अच्छा होगा.

कविता झा, *उत्तम नगर, नई दिल्ली*

ग्राम स्वराज के मायने

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-क्या यही ग्राम स्वराज है, पढ़ा. उत्तराखंड के गांवों की हालत के बारे में जानकारी मिली. शराब माफ़िया और भ्रष्ट राजनेताओं ने गांवों की स्थिति ख़राब कर दी है, केवल निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए. सरकार को जागना चाहिए और जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए.

जय कुमार झा, *ई-मेल से*

बचे देश की साख

राजा का बाजा बजा, अब जागी सरकार
संसद का जिसकी वजह, ठप था कारोबार.
ठप था कारोबार, दिया है तगड़ा झटका
होना है यह हश्र, राह से जो भी भटका.
कहे ओम कविराय, न हो घोटाला ताजा
ऐसे करो उपाय, सुनो मनमोहन राजा.
जिसके कारण देश में लगी हुई थी आग
चुनरी में सरकार की, लगा गया जो दाग.
लगा गया जो दाग, करी जिसने मनमानी
कम है उसको आज, सजा भी काला पानी.
कहे ओम कविराय, ऐसे रखो उदाहरण
बचे देश की साख, डरें सब जिसके कारण.

ओम वर्मा, *ई-मेल से*

विकास की गंगा

चौथी दुनिया के 21-27 फरवरी के अंक में छपा आलेख-गंगा देवी पल्ली में बही विकास की गंगा ख़ासा जानकारीपरक है. अब धीरे-धीरे गांवों में भी विकास होने लगा है. कैसे एक छोटा गांव आदर्श गांव बन गया, यह वहां के लोगों की एकजुटता का प्रमाण है. बिजली, पानी और स्कूल आदि समस्याओं का हल निकाल कर उन्होंने बता दिया कि चाहने से क्या नहीं हो जाता.

प्रदीप कुमार, *हिसार, हरियाणा*

लोकतंत्र और मुसलमान

आवरण कथा-लोकतंत्र के लिए मुसलमान पढ़ी. बात बड़ी सीधी सी है कि जिस देश में खुलकर सांस लेने पर भी पाबंदी होगी, जनता की बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, रोज़गार का कोई साधन नहीं होगा, उसे दो वक़्त की रोटी के लाले रहेंगे तो फिर उसका आक्रोश आख़िर कहां जाएगा? मज़लूम और मासूम जनता जब अपने वतन में हुक्मरानों का वह तल्ख़ रवैया देखती है, जिसमें वे आसमान की बुलंदी पर बैठे हैं और उन्हें दुनिया का हर आराम मुहैया है और उन्हें ज़मीन पर रहने वालों से कोई सरोकार नहीं है. तो ऐसे आंदोलन या क्रांति स्वाभाविक है. मिस्र में जो हुआ, वह कोई दास्तां नहीं है, बल्कि दुनिया में जहां भी ऐसे हालात हुए, वहां बदलाव आकर रहा. यह कहना बेकार है कि मिस्र जैसे मुल्क इस्लाम को मानने या इस्लाम की राह पर चलने वाले हैं. मेरा मानना है कि आज की तारीख़ में इस्लाम को मानने या इस्लाम की राह पर चलने वाला कोई मुल्क नहीं है.

ख़दीजा सिद्दीक़ी, *ई-मेल से*

- मिस्र जैसा कोहराम कहीं नहीं हुआ, यह पहली बार एशिया में देखने को मिला. ऐसा माहौल अब अरब और ग़ैर अरब देशों में देखने को मिल रहा है. इस हंगामे की वजह सरकार है. कहीं भारत में ऐसा न हो जाए, क्योंकि महंगाई, घोटाले और भ्रष्टाचार अपनी सीमाएं लांघ चुके हैं. सरकार को मिस्र से सब1क लेते हुए जनता की समस्याओं को हल करना चाहिए. **राजेश कुमार,** *दरभंगा, बिहार*

महत्वपूर्ण सूचना

अब चौथी दुनिया में अगले सप्ताह से प्रकाशित होने वाले हर अंक के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की तरफ़ से 700 रुपये की किताबें पुरस्कार के रूप में दी जाएगी. पाठक पत्र में अपना पूरा नाम, पता एवं फ़ोन नंबर अवश्य लिखें.

आप अपने स्वतंत्र विचार तथा प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें. संपादक, चौथी दुनिया, एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा, (उत्तर प्रदेश) पिन-201301
ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

जेपीसी की साख दांव पर है

आख़िरकार सरकार ने 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच के लिए 30 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर ही दी. यह कमेटी वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2009 तक के सभी संबंधित दूरसंचार सौदों की जांच करेगी, साथ ही स्पेक्ट्रम आवंटन एवं दूरसंचार लाइसेंस के मूल्यों पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के फ़ैसलों और उनके परिणामों की भी. यक़ीनन प्रधानमंत्री ने यह फ़ैसला बहुत सोच-समझ कर और बेहद दबाव के बाद लिया होगा, क्योंकि जिस तरह शीतकालीन सत्र बिना कार्यवाही के ख़त्म हो गया, उससे यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री को विवशता की हालत में यह फ़ैसला लेना पड़ा. सबसे पहले हम बात करते हैं उन सदस्यों की, जिनको इस कमेटी में शामिल किया गया है. इनमें कांग्रेस के आठ सांसद हैं, जिनमें पी सी चाको, मनीष तिवारी, जयप्रकाश अग्रवाल, अधीर रंजन चौधरी, वी किशोर चंद्रदेव, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, निर्मल खत्री और प्रणब सिंह भगाटूर शामिल हैं.

भाजपा के सांसदों में जसवंत सिंह बड़ा महत्वपूर्ण नाम है. यशवंत सिन्हा भी देश के जाने-माने नेता हैं, हरेन पाठक और गोपीनाथ मुंडे भी इसमें शामिल हैं, ये भी सियासत के अहम मोहरे हैं. डीएमके के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, जनता दल (यू) के शरद यादव, बसपा के दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एवं भाकपा के गुरुदास गुप्ता, यहां तक कि सभी बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं और इन सभी नामों से यक़ीनन सभी परिचित होंगे. मगर इनमें से कितने नेता ऐसे हैं, जिनकी छवि दाग़दार नहीं है या जिन पर देश की जनता भरोसा करती है. इस संबंध में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस स्थिति से सभी पार्टियों को सबक़ लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए यह बेहद ख़तरनाक है कि अपनी मांगों के लिए संसद की कार्यवाही में रुकावट डाली जाए. प्रणब मुखर्जी ने जो बयान दिया है, उससे हम भी सहमत हैं, मगर सच्चाई यह है कि हमारा विपक्ष सही भूमिका नहीं निभा रहा है. लोकतंत्र में जितनी महत्वपूर्ण सरकार होती है, उतना ही महत्वपूर्ण विपक्ष भी.

एक वक़्त था, जब अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का चेहरा माना जाता था और उनके साथ आडवाणी और सुषमा स्वराज के रूप में एक ताक़तवर विपक्ष सामने आता था. सरकार को भी यह डर रहता था कि हमारे सामने एक मज़बूत विपक्ष है, मगर अब ख़ुद भाजपा में इस कदर आपसी फूट और भेदभाव है कि वह अपनी ही नीतियों में उलझ गई है. नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष ज़रूर हैं, मगर सभी जानते हैं कि वह एक अनुभवहीन नेता हैं. मोदी को गुजरात कांड के बाद मुसलमान तो पसंद करते ही नहीं, शिक्षित और धर्मनिरपेक्ष हिंदू भी उन्हें नापसंद करते हैं. ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि यह देखा जाए कि अब जबकि जेपीसी का गठन हो चुका है तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे. अब तक विभिन्न मामलों पर चार बार जेपीसी बन चुकी है और यह पांचवीं बार है. पहली बार 6 अगस्त 1987 को बोफ़ोर्स घोटाले को लेकर, दूसरी बार 6 अगस्त 1992 में हर्षद मेहता शेयर घोटाले की जांच को लेकर, तीसरी बार 26 अप्रैल 2001 में शेयर बाज़ार घोटाले को लेकर और चौथी बार 2003 में जेपीसी का गठन किया गया था, जो भारत में बनने वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स और दूसरे पदार्थों में कीटाणु होने की जांच से संबंधित थी. अगर पहली जेपीसी से अब तक देखा जाए तो किसी के भी ख़ास परिणाम सामने नहीं आए हैं. बोफ़ोर्स घोटाले की जांच, जिसकी अध्यक्षता के सी पंत को सौंपी गई थी, का कोई भी हल सामने नहीं आया. कितने लोगों को जेल में डाला गया, कितनों के ख़िलाफ़ कार्यवाही हुई, कुछ पता नहीं.

असल में जनता को रोज़ी-रोटी के चक्कर में उलझा दिया गया है कि वह चंद दिनों तक किसी भी घोटाले को याद रखती है, फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी की गाड़ी घसीटने में लग जाती है और सब भूल जाती है. अब देखना है कि यह कमेटी, जिसे केवल 6 महीने का समय दिया गया है, क्या तीर मारती है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि इतने बड़े घोटाले की जांच के लिए 6 माह का समय कम है और यह लगभग सभी विश्लेषकों की राय है. हर्षद मेहता शेयर घोटाले और बोफ़ोर्स मामले की जांच के लिए ज़्यादा समय दिया गया था, जबकि उक्त घोटाले इस 2-जी के आगे पैदा हुए बच्चे जैसे थे. उस जेपीसी, जो शेयर मार्केट घोटाले की जांच के लिए बनाई गई थी, को भी एक साल 8 माह का समय दिया गया था. हर्षद मेहता शेयर घोटाले की जांच के लिए एक साल पांच माह का समय मिला था. बोफ़ोर्स घोटाले की जांच के लिए जेपीसी को नौ माह का समय दिया गया था. यहां तक कि पेस्टीसाइड्स के संबंध में जो मामला दर्ज हुआ था, उसे भी लगभग सात माह का वक़्त मिला था. ऐसा लगता है कि सरकार ने बड़ी समझदारी और होशियारी से यह फ़ैसला किया है, ताकि 2014 तक सारे मामले साफ़ हो जाएं और जनता को इतना समय मिल जाए कि वह अगले संसदीय चुनावों तक इसे भूल सके. यहां एक बात ज़रूर अच्छी है कि इस बार हमारे ईमानदार प्रधानमंत्री के तेवर सख़्त हैं. उन्होंने सख़्त लहजे में संसद में यह घोषणा की है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार किसी भी संलिप्त व्यक्ति को नहीं बख़्शेगी. मगर हमें लगता है कि ज़्यादा वक़्त देने से किसी भी मामले की अहमियत ख़त्म हो जाती है, लोग भूल जाते हैं, सरकारी तंत्र भी सुस्त हो जाता है. ऐसे में छह माह की अवधि काफ़ी है.

> **भाजपा के सांसदों में जसवंत सिंह बड़ा महत्वपूर्ण नाम है. यशवंत सिन्हा भी देश के जाने-माने नेता हैं, हरेन पाठक और गोपीनाथ मुंडे भी इसमें शामिल हैं, ये भी सियासत के अहम मोहरे हैं. डीएमके के टीआर बालू, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, जनता दल (यू) के शरद यादव, बसपा के दारा सिंह चौहान, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव एवं भाकपा के गुरुदास गुप्ता, यहां तक कि सभी बेहद महत्वपूर्ण नेता हैं और इन सभी नामों से यक़ीनन सभी परिचित होंगे. मगर इनमें से कितने नेता ऐसे हैं, जिनकी छवि दाग़दार नहीं है या जिन पर देश की जनता भरोसा करती है.**

अब जबकि प्रधानमंत्री ने जेसीपी का गठन कर दिया है तो इस मसले पर घटिया सियासत ख़त्म हो जानी चाहिए. विपक्ष को भी इसे अपनी जीत न मानकर बयानबाज़ी से बचना चाहिए और जिस तरह प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल और सुषमा स्वराज में गर्मागर्म बहस हुई और एक-दूसरे पर ताने कसे गए, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए. आख़िर राजनीतिक दल हर मुद्दे को हार-जीत का मुद्दा क्यों बना लेते हैं. विपक्ष की मांग पूरी हो चुकी है और सरकार भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर चुकी है. ऐसे में दोनों की ही जिम्मेदारी है कि संसद की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलने दिया जाए और देश जो इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार एवं अनिश्चितता की मार झेल रहा है, उससे पहले निपटा जाए. यह एक हक़ीक़त है, ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वह सरकारी अफ़सर हो या मंत्री अथवा किसी विभाग का प्रभारी हो, बिना रिश्वत के मामला आगे नहीं बढ़ता और न ही निपटता है. ऐसे में मीडिया की दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है. मीडिया को प्रतिस्पर्धा की दौड़ से निकल कर सरकारी विभागों, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों यानी सभी को बेनक़ाब करके जनता के सामने लाना चाहिए. देश की जनता की भावनाओं से न खेलकर उसकी समस्याओं को सही तरीक़े से पेश किया जाना चाहिए.

जेपीसी का गठन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, मगर जब तक कोई कारगर हल न निकले, तब तक यह बेकार है. ऐसे में विपक्ष की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. सरकार पर टिप्पणी करने से पहले विपक्ष को ख़ुद अपनी साख पर नज़र डालना चाहिए. यहां फिर हम यह बात कहने पर मजबूर हैं कि अटल जी अगर सक्रिय होते तो वह कभी भी मनमोहन सिंह को अयोग्य प्रधानमंत्री साबित करने पर न तुलते. हां, वह मनमोहन सिंह को उनकी नीतियों और घोटालों के लिए बख़्शते भी नहीं. किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का कमज़ोर होना इस बात का सबूत है कि अब देश ख़तरे में है. इसलिए जेपीसी का गठन अपनी जगह, मगर विपक्ष की जिम्मेदारी अपनी जगह है. जेपीसी अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करे और विपक्ष अपना काम करे. तभी लोकतंत्र की भलाई है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

वाईब्रेंट गुजरात का मिथक

राम पुनियानी

इन दिनों यह मान्यता बहुत तेजी से फैल रही है (या फैलाई जा रही है) कि गुजरात अत्यंत द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, वहां शांति एवं सौहार्द का राज है, अल्पसंख्यक ख़ुशहाल हैं और वह जल्दी ही देश का सबसे उन्नत राज्य बन जाएगा. शाइनिंग इंडिया की तर्ज़ पर एक नया शब्द गढ़ा गया है, वाईब्रेंट गुजरात. इस प्रचार में सत्य का नाम मात्र भी अंश नहीं है. दो हज़ार से अधिक मुसलमानों की हत्या, बलात्कार, लूटपाट एवं आगजनी की यादें मिट नहीं पा रही हैं, क्योंकि हिंसा पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल सका है. उनके पुनर्वास पर भी सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है. सुविधाहीन राहत शिविर बहुत जल्दी बंद कर दिए गए. सरकार ने पुनर्वास के काम से अपना पल्ला झाड़ लिया है.

यद्यपि मुसलमानों के व्यापारी तबके के एक हिस्से को भाजपा एवं प्रभुत्वशाली सामाजिक वर्ग ने अपनी ओर कर लिया है, तथापि अधिकांश मुसलमान आज भी घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं. वे समाज की मुख्यधारा से कटकर अपने में सिमट गए हैं. सभी बड़े शहरों में मुस्लिम बस्तियां बस गई हैं. अहमदाबाद का जुहापुरा इलाक़ा डर और असुरक्षा के उस भाव का जीता-जागता उदाहरण है, जिससे गुजरात के मुसलमान ग्रस्त हैं. मुसलमानों ने अपनी दुकानों-व्यापारिक प्रतिष्ठानों के नाम बदल लिए हैं, जिनसे लगता है कि संबंधित दुकान या फर्म किसी हिंदू की है. मुसलमानों को उम्मीद है कि इससे भविष्य में होने वाले दंगों में उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होगी और उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहेंगी. उन्हें यह भी उम्मीद है कि इससे वे मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करने के विहिप के आह्वान का शिकार होने से बच जाएंगे. इस निराशाजनक परिदृश्य में आशा की एकमात्र किरण यह है कि कुछ मुस्लिम सामाजिक संगठन अपने समुदाय को शिक्षित करने के प्रयास में लगे हैं, जिससे मुस्लिम युवक ऐसे क्षेत्रों में रोज़गार प्राप्त कर सकें, जहां उनके साथ भेदभाव न हो.

अब्दुल सलेह शरीफ द्वारा रिलेटिव डेवलपमेंट ऑफ गुजरात एंड सोशियो-इकोनॉमिक डिफरेन्शियल्स (गुजरात के विकास में सामाजिक-आर्थिक वर्गीय अंतर) विषय पर किया गया विस्तृत अध्ययन गुजरात में मुसलमानों की खस्ताहाली को उजागर करता है. ग़रीबी, कुपोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा जैसे मानकों की दृष्टि से दूसरे समुदायों की तुलना में मुसलमान बहुत पीछे हैं. गुजरात के मुसलमानों के लिए दो जून की रोटी जुटाना उतना ही कठिन है, जितना उड़ीसा एवं बिहार के पिछड़े हुए इलाक़ों के निवासियों के लिए. मुसलमान शिक्षा के मामले में भी पीछे हैं. हीरों के व्यापार एवं कपड़ा उद्योग में एक समय मुसलमानों का बोलबाला था, अब उन्हें पीछे धकेल दिया गया है. उच्च जातियों के हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों में ग़रीबों का प्रतिशत 8 गुना अधिक है. वे अन्य पिछड़े वर्गों से भी काफी पीछे हैं. केवल 12 प्रतिशत मुसलमानों के बैंक खाते हैं और 2.6 प्रतिशत मुसलमानों को बैंकों से क़र्ज़ मिला है. अध्ययन का निष्कर्ष है कि गुजरात में मुसलमानों के साथ घोर भेदभाव किया जा रहा है. यहां तक कि नरेगा में भी उनके साथ पक्षपात होता है. ग़ैर सरकारी संगठन प्रथम के अनुसार, शिक्षा के क्षेत्र में गुजरात बिहार से भी पीछे है. सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट प्रावधान के मामले में 18 बड़े राज्यों में गुजरात का स्थान 17वां है. विभिन्न समुदायों के बीच भावनात्मक दूरियां बढ़ गई हैं और शहरों में उग आईं मुस्लिम बस्तियां इसका प्रमाण हैं. मुस्लिम बस्तियों में बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोलते और टेलीफोन कंपनियां वहां कनेक्शन देने में आनाकानी करती हैं. इन इलाक़ों में नागरिक सुविधाओं का नितांत अभाव है. इन बस्तियों के बच्चों को स्कूल भी नसीब नहीं है.

इस सबके बीच गुजरात में अप्रवासी भारतीयों एवं उद्योगपतियों के सम्मेलन हो रहे हैं और निवेश आमंत्रित किया जा रहा है. ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है, मानों गुजरात में डॉलरों की बरसात हो रही हो. यह सही है कि गुजरात में निवेश हो रहा है और औद्योगीकरण भी, परंतु जितना बताया जा रहा है, उससे कम. 2005 की वाईब्रेंट गुजरात मीट के बाद घोषणा की गई थी कि 1.06 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. बाद में मुख्यमंत्री ने बताया कि इनमें से 74 हज़ार करोड़ रुपये (63 प्रतिशत) का निवेश वास्तविक रूप से हुआ. सूचना के अधिकार के तहत हासिल की गई जानकारी के अनुसार, इनमें से केवल 25 हज़ार करोड़ रुपये (23.5 प्रतिशत) की औद्योगिक परियोजनाएं ज़मीन पर उतर सकीं. तीस्ता सीतलवाड़ के अनुसार, 2007 में गुजरात सरकार ने दावा किया कि उसने 363 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनके अंतर्गत राज्य में कुल 4.61 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा. इस हिसाब में जोड़ की ग़लती थी. सही आंकड़ा 4.51 लाख करोड़ रुपये था. सरकार के अनुसार, इसमें से 2.64 लाख करोड़ रुपये का निवेश वास्तविक रूप से हुआ, परंतु राज्य के उद्योग आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, मात्र 1.22 लाख करोड़ रुपये (27 प्रतिशत) की परियोजनाएं लागू हुईं. 2003, 2005 एवं 2007 में घोषित किए गए निवेशों में से केवल 20.28 प्रतिशत निवेश वास्तविक रूप से हुआ.

जो थोड़ा-बहुत निवेश गुजरात आकर्षित कर सका, वह भी इसलिए हुआ, क्योंकि गुजरात पहले से ही औद्योगीकृत राज्य था. अभी भी गुजरात महाराष्ट्र से पीछे है, परंतु महाराष्ट्र के औद्योगीकरण या वहां हो रहे निवेश के संबंध में मीडिया में कभी इतने जोर-शोर से प्रचार नहीं होता, जितना गुजरात के मामले में. दो दशक पहले गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर 13 प्रतिशत थी. उस समय राष्ट्रीय औसत 7 प्रतिशत के क़रीब था. इस समय गुजरात की आर्थिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत और पूरे देश की 10 प्रतिशत है. ये तथ्य असली कहानी को बयान करते हैं. गुजरात ने सरकारी खजाना उद्योगपतियों के लिए खोल दिया है. उन्हें तरह-तरह की छूटें दी जा रही हैं और अनुदान भी. सस्ती दरों पर ज़मीन एवं पानी और अत्यंत कम ब्याज दरों पर क़र्ज़ की सुविधा है. टाटा के अपनी नैनो परियोजना गुजरात ले जाने के पीछे यह भी एक कारण था. नैनो परियोजना को भारी अनुदान दिया गया है. जहां उद्योगपतियों को गुजरात में सार्वजनिक संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिली हुई है, वहीं रोज़गार के अवसरों के सृजन की ओर सरकार का ध्यान नहीं है. महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में निवेश और रोज़गार सृजन के बीच अनुपात गुजरात की तुलना में कहीं बेहतर है. निवेश की राशि के मामले में खोखले दावे किए जा रहे हैं. अंधाधुंध औद्योगीकरण के कारण पर्यावरण को जो नुक़सान हो रहा है, उससे गुजरात सरकार को कोई मतलब नहीं है.

भारतीय राज्य हंगर इंडेक्स 2008 के अनुसार, भूख के मामले में गुजरात उड़ीसा से भी पीछे है. इसमें 17 बड़े राज्यों में गुजरात का स्थान 13वां है. वह केवल झारखंड, बिहार एवं मध्य प्रदेश से ऊपर है. गुजरात में ग़रीबी एवं बेरोज़गारी बढ़ रही है और कृषि क्षेत्र की भी हालत ख़राब है. कृषि उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है. 2005 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार, गुजरात के चालीस प्रतिशत किसानों ने कहा कि अगर उन्हें आमदनी का कोई दूसरा ज़रिया मिल जाए तो वे खेती-किसानी छोड़ना चाहेंगे. हाल के कुछ वर्षों में किसानों और कृषि श्रमिकों की बदहाली बढ़ी है. विधानसभा में दिए गए एक उत्तर में मोदी ने बताया कि जनवरी 2007 में समाप्त हुए एक वर्ष में राज्य में 148 किसानों ने आत्महत्या की. एक ओर गुजरात विद्युत का निर्यात कर रहा है तो दूसरी ओर गांवों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है. 2007 में राज्य में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच 900 मेगावाट का अंतर था और इस अंतर को पाटने के लिए गांवों में बिजली कटौती की जा रही थी. किसी समुदाय में व्याप्त ग़रीबी को मापने का एक महत्वपूर्ण आधार है वहां एनीमिया से ग्रस्त लोगों का प्रतिशत. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2006 के अनुसार, 1999 में गुजरात में 46.3 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त थीं. 2004 में यह प्रतिशत बढ़कर 55.5 हो गया. इसी अवधि में बच्चों में एनीमिया का प्रतिशत 74.5 से बढ़कर 80.1 हो गया.

(लेखक आईआईटी मुंबई के पूर्व प्राध्यापक हैं)

feedback@chauthiduniya.com

बच्चे के माता-पिता इस बात से हैरान हैं कि उनके आठ साल के बेटे को देश की सशस्त्र सेना की सेवा करने का यह बुलावा आख़िर कैसे आ गया.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

क्या आपके बच्चे को छात्रवृत्ति मिली?

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, ताकि ऐसे बच्चों, जिनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है, की पढ़ाई-लिखाई में दिक्कत न आए. इसके लिए बाक़ायदा नियम-क़ानून भी बनाए गए हैं कि कौन बच्चा छात्रवृत्ति का हक़दार होगा और कौन नहीं. बावजूद इसके कई बार ऐसी ख़बरें आती हैं कि ज़रूरतमंद और असली हक़दार बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती या अभिभावकों से हस्ताक्षर कराकर इस मद का पैसा हड़प लिया जाता है. ज़ाहिर है, इस काम में स्कूल प्रशासन से लेकर अधिकारियों तक की मिलीभगत रहती है. दरअसल, इस समस्या के पीछे कई कारण हैं. मसलन, आम आदमी का जागरूक न होना, उसे अपने अधिकारों की जानकारी न होना. भ्रष्ट पंचायती व्यवस्था का भी इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ाने में बड़ा हाथ है. ग्रामसभा, जो गांवों से जुड़े शासन-प्रशासन को नियंत्रित और उनकी देखरेख करने वाली एक अहम संस्था है, को भी पंगु बना दिया गया है. यदि ग्रामसभा में इन मुद्दों पर ईमानदारीपूर्वक बहस की जाए तो ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ निश्चित तौर पर उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो वास्तव में इसके हक़दार हैं या जिन्हें इनकी ज़रूरत है. बहरहाल, इस अंक में हम छात्रवृत्ति के मुद्दे पर बात कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का गबन होने से रोक सकते हैं. इस अंक में एक ऐसा आवेदन प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके इस्तेमाल से आप छात्रवृत्ति के बारे में सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

मुक़दमा दर्ज करा दिया गया. इस संबंध में मुझे आगे क्या करना चाहिए.

-भुवनेश्वर प्रसाद यादव, *लक्खीसराय, बिहार.*

आप सबसे पहले इसकी शिक़ायत राज्य सूचना आयोग में दर्ज करा सकते हैं. साथ ही इस घटना के बारे में राज्य सरकार को भी सूचित करें. बिहार में आरटीआई क़ानून पर काम करने वाली कई संस्थाएं हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि इस मुद्दे को कारगर ढंग से उठाया जा सके. इससे पहले भी बिहार में इस क़ानून का इस्तेमाल करने वाले कई लोगों को परेशान किया गया, लेकिन जीत सच की हुई.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों के पत्र

मैं एक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता हूं. मैंने और मेरे बेटे ने अपने यहां के प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचना क़ानून के तहत कुछ सूचनाएं मांगी थीं. सूचना तो नहीं दी गई, उल्टे मेरे और परिवार के एक सदस्य पर साजिश के तहत

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

आवेदन का प्रारूप

(विद्यालय में छात्रवृत्ति का विवरण)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,

.....विद्यालय में छात्रवृत्ति वितरण के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराएं :

1. उपरोक्त विद्यालय की कक्षा.....में मेरा पुत्र/पुत्री..... पढ़ता/पढ़ती है. आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक़ क्या वह इस वर्ष छात्रवृत्ति पाने का हक़दार है? यदि हां, तो उसे कितनी राशि मिलनी चाहिए?

2. क्या आपके विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक़ उसे इस वर्ष की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है? यदि हां, तो संबंधित दस्तावेजों/रजिस्टरों के उस भाग की प्रमाणित प्रति दें, जहां उसे छात्रवृत्ति दिए जाने का विवरण दर्ज है.

3. यदि उसे छात्रवृत्ति नहीं दी गई है तो इसका क्या कारण है? संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति दें.

4. उपरोक्त विद्यालय में कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है? प्रत्येक छात्र-छात्रा का नाम, पिता का नाम एवं कक्षा का विवरण दें.

5. वर्ष.....में कुल कितने छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी गई? प्राप्ति रजिस्टर, जिस पर छात्र-छात्राओं या उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर हों, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं.

6. छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए क्या नियम एवं क़ानून हैं? इस संबंध में समस्त शासनादेशों-निर्देशों एवं क़ानूनों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं.

7. सरकार ने विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के लिए कितनी राशि निर्धारित की है?

8. अगर किसी छात्र की छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है? ऐसे सभी छात्रों की सूची दें, जिन्हें अब तक छात्रवृत्ति नहीं दी गई है. सूची में निम्नलिखित विवरण अवश्य शामिल हों:

क. छात्रा का नाम.....
ख. पिता का नाम.....
ग. छात्रवृत्ति न दिए जाने का कारण.....

9. छात्रवृत्ति का भुगतान समय से न किए जाने के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों के नाम एवं पद बताएं? अपना काम विभाग के नियम क़ानूनों के अनुसार न करने वाले इन अधिकारियों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.
या
मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय

नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....
संलग्नक..... (यदि कुछ हो तो)

राशिफल

मेष 21 मार्च से 20 अप्रैल

इस सप्ताह ज़रूरी कार्य पूरे करने की कोशिशों में कोई कमी नहीं रहेगी. अनेक ऐसे प्रस्ताव आपको मिल सकते हैं, जो आपके करियर और लाभ मार्ग से जुड़े हुए हैं. सप्ताह के अंत तक आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी.

वृष 21 अप्रैल से 20 मई

इस सप्ताह किसी भी आलस्य या सुस्ती से बचना चाहिए. बहुत दिनों से आपके करियर और रोज़गार में जो अनिश्चितता चल रही है, उसका समाधान खोजना ज़रूरी होगा. पुराने मित्रों-शुभचिंतकों से अचानक मुलाक़ात हो सकती है.

मिथुन 21 मई से 20 जून

सप्ताह के अंत तक लंबित निर्माण कार्य, घरेलू मशीनरी की मरम्मत अथवा अन्य आवश्यक कार्य आपको अवश्य संपन्न कर लेने चाहिए. हो सकता है कि आपके पीछे परिवारजनों को इसके कारण बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हों.

कर्क 21 जून से 20 जुलाई

आर्थिक तंगी के इस दौर में आपको ऐसे काम हाथ में नहीं लेने चाहिए, जिनसे आगे चलकर और भी बोझ पड़ सकता हो. यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है तो बेहतर है कि घर पर रहकर आराम करें.

सिंह 21 जुलाई से 20 अगस्त

इस सप्ताह बेहतर समय देखकर आप आरंभ के दिनों का उपयोग कर सकते हैं. यदि आपके पास वाहन है तो ज़ाहिर है कि सप्ताह के मध्य में कोई लंबी दूरी की यात्रा आपके लिए सुखद और मनोरंजक सिद्ध हो सकती है.

कन्या 21 अगस्त से 20 सितंबर

इस सप्ताह यदि आप किसी भूले-भटके मित्र या शुभचिंतक से मिलने की योजना बना रहे हैं तो इसके लिए शुरुआत का समय काफी अच्छा रहेगा. किसी सामान या ज़रूरी वस्तु की ख़रीद-फरोख्त करने पर भी आपको छोटा-मोटा लाभ होगा.

तुला 21 सितंबर से 20 अक्टूबर

यह सप्ताह प्रियजनों या फिर छोटे सदस्यों से मेल-मुलाक़ात के लिए बहुत ही शुभ रहेगा. यदि आप अपने घर और बाहर की साजसज्जा करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ ज़रूरी सामान या आरामदायक वस्तुएं ज़रूरी होंगी.

वृश्चिक 21 अक्टूबर से 20 नवंबर

इस सप्ताह यदि आप अपने परिवारीजनों यानी घर के सदस्यों से बहसबाज़ी या तर्क-वितर्क न करें तो अच्छा रहेगा. हो सकता है, आपको किसी अभियोग या लांछन का भी शिकार होना पड़े. आय के नए स्रोत बनेंगे.

धनु 21 नवंबर से 20 दिसंबर

व्यापार या घरेलू जीवन के अलावा आपका एक सामाजिक दायरा भी है. हो सकता है, इस सप्ताह आपका अधिकांश समय किसी नेक काम को करने में व्यतीत हो जाए. किसी संस्था या संगठन का नेतृत्व भी आप कर सकते हैं.

मकर 21 दिसंबर से 20 जनवरी

आपके बौद्धिक विकास के लिए यह सप्ताह बहुत ही उम्दा और सार्थक बनकर आ रहा है. आप किसी प्रकार की ख़रीद-फरोख्त या शॉपिंग की सोच रहे हैं तो अभी रुकें, हो सकता है कि अगले दिनों में आपकी जेब पर ज़्यादा बोझ न पड़े.

कुंभ 21 जनवरी से 20 फरवरी

इस सप्ताह अगर कोई अच्छी ख़बर मिल जाए तो आपका उत्साहित होना स्वाभाविक होगा. यदि आपको धन लाभ होने का इंतज़ार है या फिर किसी लेनदेन में आपकी भागीदारी है तो सप्ताह के मध्य का समय आपके लिए भाग्यशाली सिद्ध होगा.

मीन 21 फरवरी से 20 मार्च

काफी दिनों से जो ख़र्चीला और तनावपूर्ण समय चल रहा है, उसकी इस सप्ताह चरम सीमा हो सकती है. सप्ताह के आरंभ के दिनों से ही कुछ ऐसे फालतू झमेले आपके आगे आएंगे, जिनके कारण आप स्वयं एवं आपके परिवारीजन परेशान हो सकते हैं.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

बिना ताले का बैंक

अभी तक आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के शनि शिगनापुर में घरों में दरवाजे नहीं होते. शनि शिगनापुर में लोगों के घरों में दरवाजों की चौखटें तो लगी हुई हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं हैं. यहां के लोग सुरक्षा के लिए लॉकरों में भी ताले नहीं लगाते हैं. दरअसल, उनका विश्वास है कि मंदिर शनि देवता का निवास स्थान है और इस वजह से वहां कोई भी चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि इससे उसे और उसके परिवारवालों को शनि के क्रोध का सामना करना पड़ेगा. अब बैंक भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले यहां यूको बैंक की एक शाखा शुरू हुई है, जिसके दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगता है. क़रीब 3000 लोगों की आबादी वाले इस अनूठे शहर में सबसे पहले यूको बैंक ने अपनी शाखा शुरू की, जिसका उद्घाटन बीती छह जनवरी को हुआ. स्थानीय धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए बैंक ने निर्णय लिया है कि उसकी इस शाखा के मुख्य दरवाज़े पर कोई ताला नहीं लगेगा.

एक अधिकारी ने बताया, नकदी डिब्बों और अंदर रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की सुरक्षा के लिए एहतियाती क़दम उठाना ज़रूरी था. इसलिए बैंक के छह सदस्यीय कर्मचारी मंडल में से कोई न कोई हर समय शाखा परिसर में रहता है. शाखा प्रबंधक यू के शाह कहते हैं कि यह शहर का पहला बैंक है और हम इसके विकास के प्रति आशावान हैं. उन्होंने बताया कि अब तक 200 से ज़्यादा ग्राहक बैंक से जुड़ चुके हैं और जल्दी ही एक एटीएम की भी व्यवस्था की जाएगी. वैसे बिना ताले के बैंक से स्थानीय प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी ख़ुश नहीं हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सावधानी बरतने के लिए कहा है.

सबसे छोटा जवान

किसी भी देश की सेना में भर्ती के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, इसका अंदाज़ा सभी को है, लेकिन कोई आपको बताए कि यूक्रेन में एक आठ साल के बच्चे को सेना में अनिवार्य भर्ती का बुलावा आया है तो ज़ाहिर है, आपको आश्चर्य होगा. बच्चे के माता-पिता इस बात से हैरान हैं कि उनके आठ साल के बेटे को देश की सशस्त्र सेना की सेवा करने का यह बुलावा आख़िर कैसे आ गया. यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम स्थित इवानो-फ्रेंकोवस्क क़स्बा निवासी इस बच्चे के पिता ने कहा, अधिसूचना देखकर पहले मैं और मेरी पत्नी हैरान रह गए, इसके बाद हम हंसे. हमने तुरंत सेना के कार्यालय में इसकी सूचना दी कि संभवत: ग़लती से यह बुलावा भेजा गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. अधिसूचना के अनुसार, संबंधित व्यक्ति को 19 अप्रैल तक इस बारे में पहल करनी थी. बच्चे के माता-पिता उस दिन सेना के अधिकारियों के पास पहुंचे और उन्हें वह जन्म प्रमाणपत्र दिखाया, जिसके मुताबिक़ उनके बेटे का जन्म 2001 में हुआ. सेना के अधिकारियों ने इस संबंध में कोई प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया. सोवियत संघ के विघटन के बाद बने अन्य देशों और यूक्रेन में 18 वर्ष पूरे होने के बाद ही किसी नौजवान को सेना में भर्ती होने का आदेश दिया जा सकता है. अगर आप भी अपने बच्चे को सेना में भर्ती कराना चाहते हैं तो उसे यूक्रेन भेज सकते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सद्दाम ज़रूरत पड़ने पर मुसलमान बन जाते या सेकुलर. जनता में असंतोष तो फैलना ही था, लेकिन किसी भी तरीक़े के विद्रोही स्वर को ख़ून से रंग दिया गया.

उछलते ताज, गिरते तख्त

इस्लामी दुनिया के महानायक

बात उन दिनों की है, जब मैं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ता था. हॉस्टल के हर कमरे में, सड़कों पर, हाथ से बने पोस्टरों में, ढाबे पर बैठने वाले पत्थरों पर, संकायों के दरवाजों पर कुछ नाम लिखे होते थे और उन नामों के नीचे लिखा होता था क्रांति. ये नाम थे मुअम्मर गद्दाफ़ी, होस्नी मुबारक, सद्दाम हुसैन आदि. तब ये नाम क्रांति और साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ अंतरराष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह थे. लेकिन आज हम उन नामों का, उस क्रांति का सत्य बताना चाहते हैं. अरब देशों में चल रहा संघर्ष नया है भी और नहीं भी. नया इसलिए नहीं है, क्योंकि एक बार पहले भी ऐसी ही क्रांति आई थी और नए नायक बने थे, लेकिन आज यह नई इसलिए है, क्योंकि तब के नायक आज के खलनायक हैं.

मुअम्मर अबू मिन्यार अल-गद्दाफ़ी

लोग इन्हें कर्नल गद्दाफ़ी के नाम से जानते हैं. गद्दाफ़ी लीबिया की फ़ौज में कप्तान हुआ करते थे. 1969 में गद्दाफ़ी ने कुछ और अफ़सरों के साथ मिलकर लीबिया के राजा इदरीस का तख्ता पलट दिया. लगभग 40 साल से वह लीबिया के सर्वेसर्वा हैं. गेबोन के ओमर बोंगो की मृत्यु के बाद, गद्दाफ़ी सबसे अधिक समय तक सत्ता में रहने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी शाही राज परिवार से संबंधित नहीं हैं. गद्दाफ़ी ने लीबिया पर पाश्चात्य देशों की पकड़ को ख़त्म कर दिया और अरब राष्ट्रवाद की नींव रखी. एक कल्याणकारी राष्ट्र की कल्पना की गई. पाश्चात्य देशों से अलग प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की भी कल्पना की गई. इसे इस्लामिक समाजवाद का नाम दिया गया. अपने ख्यालों को गद्दाफ़ी ने ग्रीन बुक नाम की एक किताब में लिखा जिसे लीबिया का संविधान माना जाने लगा. साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलनकारियों को पैसा और हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया.

सिद्धार्थ राय

बात लीबिया में हो रही जनतांत्रिक क्रांति की. यहां प्रति व्यक्ति आय 13400 अमरीकी डॉलर है. ज़ाहिर है, यह देश ग़रीब नहीं है. लीबिया यूरोप का सबसे बड़ा तेल और गैस का सप्लायर है. गद्दाफ़ी ने लोगों को भरोसा दिलाया कि लीबिया के मानव संसाधनों को बढ़ावा दिया जाएगा. लेकिन गद्दाफ़ी ने ऐसा कुछ नहीं किया. पढ़े-लिखे युवा कुंठित हो गए. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? गद्दाफ़ी ने तो साम्राज्यवाद की मुख़ालफ़त करके सत्ता पाई थी. गद्दाफ़ी ने दरअसल इस्लाम के नाम पर लोगों को एकजुट तो किया, लेकिन इस्लामिक राज्य के ही नाम पर लोगों से उनके सारे मूल अधिकार, मसलन सत्ता के विरोध में प्रदर्शन करने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार छीन लिया.

सवाल उठता है कि आख़िर धर्म आधारित सारे अरब और पश्चिमी एशियाई देशों के प्रमुख तानाशाह और निरंकुश क्यों हैं? ज़ाहिर है, धर्म पर लोगों को इकट्ठा तो किया गया, लेकिन धर्म में निहित अतार्किक और असंगत अंकुशों को लोगों के ही ख़िलाफ़ अपनाया जाने लगा. इस तरह सत्ता पर क़ाबिज़ नेता लंबे समय तक लोगों का मुंह बंद करके अपना उल्लू सीधा कर सकते थे. ठीक यही काम गद्दाफ़ी ने भी किया. फ़िलीस्तीन का साथ देने और इज़रायल का विरोध करने के नाम पर गद्दाफ़ी ने अपने लोगों को चुप रहने को कहा. अधिकारों का हनन इस्लाम को बचाने के नाम पर और पाश्चात्य संस्कृति के विरोध के नाम पर ही किया गया. लेकिन जब फ़िलीस्तीन-इज़राइल समझौता हुआ तो फ़िलीस्तीनियों को अपने देश से भगा दिया. इसका सीधा मतलब यह है कि गद्दाफ़ी अपनी सत्ता को सशक्त करने के लिए कपोल कल्पित सिद्धांत गढ़ते रहे.

लीबिया में सैन्य बल का कोई महत्व नहीं है. गद्दाफ़ी ने तख्ता पलट करने के बाद से ही सेना को कमज़ोर करना शुरू कर दिया था. आज लीबिया की सेना एक बहुत ही छोटी और अनुपयुक्त अवस्था में है. दरअसल गद्दाफ़ी की शक्ति का राज़ लीबिया में उसकी पार्टी द्वारा बनाया गया ख़ूनी दस्ता है जिसे स्पेशल ब्रिगेड या रेवोल्युशनरी कमेटी का नाम दिया गया है. ये छोटी-छोटी टुकड़ियां जनता के बीच रहकर पता लगाती हैं कि कौन विरोध के स्वर उंचे कर रहा है और उनको मार डालती हैं. इस्लाम के नाम पर गद्दाफ़ी ने तेल से कमाई संपत्ति अपनी जेबों में रख ली. गद्दाफ़ी के नाम 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में इज़रायली खिलाड़ियों का ख़ून, 1986 में बर्लिन के डिस्को में धमाका, लोकार्बी बम धमाका और ऐसे ही कई अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी हमले जैसे कुख्यात कारनामे दर्ज हैं. ऐसी स्थिति में जब कल का हीरो आज का विलेन बन गया हो तो जनता क्या करती? ट्यूनिशिया और मिस्र ने राह दिखाई और जनता उठ खड़ी हुई है. जनता ने, जिसने कल इसी इस्लामिक कट्टरवाद पर आधारित राज्य व्यवस्था को अपनाया था, आज इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. आज मुस्लिम जनता जाग गई है. इस्लाम के नाम पर वह और शोषण बर्दाश्त नहीं कर सकती.

सद्दाम हुसैन अब्द अल-माजिद तिकरिती

ये 1979 से 2003 तक इराक़ के राष्ट्रपति रहे. ये बाथ पार्टी के सर्वेसर्वा थे. बाथ पार्टी के ही नेतृत्व में इराक़ को राजशाही से छुटकारा मिला था. सद्दाम हुसैन और उनकी बाथ पार्टी अरब राष्ट्रवाद और अरब समाजवाद में अपनी निष्ठा रखते थे. सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक़ ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. ये लोगों के नेता ही नहीं उनके हीरो बनकर उभरे. सद्दाम ने अपने पूरे कार्यकाल के पहले अर्ध में बहुत सारे जनप्रिय काम किए. उन्होंने जनता के बीच के सांस्कृतिक और नस्ली हिंसा पर अंकुश लगाया और एक धर्मनिरपेक्ष राज व्यवस्था का आधार रखा. देश के तेल की संपदा पर से पश्चिमी देशों के एकाधिकार को ख़त्म किया और बाहरी कंपनियों का राष्ट्रीकरण कर दिया. इस समय में इराक़ बहुत तेज़ी से आर्थिक रूप से आगे बढ़ा. अपने समय के अनुसार सद्दाम भी मिस्र के नेता जनरल नासिर से बहुत प्रभावित थे और उनके ही आदर्शों को चरितार्थ करने की कोशिश की. याद रखने की बात यह है कि नासिर ने ही 1956 की स्वेज कैनाल समस्या के समय सारे अरब देशों को अंग्रेज़ी और फ़्रांसीसी साम्राज्यवाद का मुक़ाबला करने की सलाह दी थी. यह समय पूरे पश्चिम एशिया और अरब में क्रांति का काल था जब उदारवाद और साम्राज्यवाद को इन देशों ने उखाड़ फेंका था. सद्दाम भी इसी काल और बौद्धिक प्रवाह से प्रभावित थे. सद्दाम ने इराक़ को एक बार फिर से खड़ा करने का बीड़ा उठाया. इस मुहिम का आधार था इराक़ का पेट्रोल. सद्दाम ने इस पैसे को जनता के कल्याण में लगाया और एक समय वह आया जब इराक़ में पूरे अरब देशों से अच्छी स्वास्थ्य और बाक़ी जनसेवाएं थीं. सद्दाम ने साक्षरता और महिला कल्याण और उत्थान के लिए भी बहुत काम किया. ये भी एक समय इराक़ के निर्विवाद हीरो हुआ करते थे.

लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा इराक़ सद्दाम के नाम से डरने लगा. देश का हीरो जनता का भक्षक कैसे बन गया. एक सुधारवादी व्यक्ति कैसे एक कट्टरवादी इस्लामिक सत्ता का नेता बन बैठा. यह प्रश्न इसलिए भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि आज जो मिस्र, ट्यूनिशिया और लीबिया में हो रहा है, उसका सीधा संबंध इन प्रश्नों के उत्तरों से संबंधित है. सबसे पहली बात जो समझने वाली है वह यह है कि चाहे गद्दाफ़ी हो या सद्दाम, दोनों ही एक सत्ता को पदच्युत करके राष्ट्राध्यक्ष बने थे. गद्दाफ़ी सैन्य विद्रोह से और सद्दाम पहले राजशाही को हटाकर और फिर अपनी ही पार्टी के नेता को दबाकर आगे बढ़े. दोनों ही स्थितियों में जनता का कोई सीधा समर्थन नहीं था. जो भी पहली सरकारी व्यवस्था के विरोध में आया वही हीरो बन गया. सद्दाम ने भी ऐसा ही किया था. जनता को पहले तो धर्म निरपेक्ष व्यवस्था दी, लेकिन जब उनकी अपनी ही सत्ता किसी कारण से हिलती नज़र आई तो उन्होंने उसी जनता को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया. सद्दाम सत्ता में आए थे धर्मनिरपेक्षता का नाटक करके , लेकिन उन्होंने इस्लामी अब्बासी ख़लीफ़ाओं के नाम पर लोगों को एकजुट करने की भी चेष्टा की. ये विरोधाभास आगे चलकर घातक होना था और हुआ भी. जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो सद्दाम ने अपने यहां की शिया जनता का ख़ून पीना शुरू किया. शियाओं का नरसंहार किया. सद्दाम की सत्ता का केंद्र सुन्नी थे, लेकिन इराक़ में सुन्नी अल्पसंख्यक हैं और शिया बहुसंख्यक हैं. इस कारण शियाओं का दमन आवश्यक हो गया. सद्दाम आए तो थे पश्चिमी साम्राज्यवाद की मुख़ालफ़त करके लेकिन ईरान के साथ आठ साला युद्ध में उन्होंने अमरीका, फ़्रांस, जर्मनी सरीखे देशों से भरपूर सैन्य और असैन्य मदद ली. रोचक बात यह है कि अयातुल्लाह खुमैनी, जो कि ईरानी क्रांति के हीरो थे, को सद्दाम ने ही अपने देश में शरण दी थी और पाला पोसा था. जनता के बस एक ही तबक़े को जब सारे फ़ायदे होने लगे तो इराक़ जैसे नस्ली रूप से भिन्नता वाले देश में नस्ली हिंसा का भड़कना तो तय ही था. सद्दाम ने ऐसी ही एक जनजाति जिसका नाम कुर्द है, का नरसंहार शुरू कर दिया. अल-अनफ़ल नाम की एक मुहिम के तहत यह नरसंहार किया गया और सद्दामी सैनिकों ने लगभग दो लाख लोगों को जान से मार दिया.

सद्दाम ज़रूरत पड़ने पर मुसलमान बन जाते या सेकुलर. जनता में असंतोष तो फैलना ही था, लेकिन किसी भी तरीक़े के विद्रोही स्वर को ख़ून से रंग दिया गया. यहां तक कि एक बार अपने ही स्वास्थ्य मंत्री को सद्दाम ने कटवा दिया और लाश के टुकड़े उसकी पत्नी के पास भेज दिए. एक रोचक बात यह भी थी कि सद्दाम अपनी दूसरी पारी में एक कट्टर मुसलमान बनकर उभरे. ऐसा ईरान की इस्लामिक क्रांति के ख़िलाफ़, अरब राष्ट्रवाद और अरब समाजवाद के नाम पर, पश्चिम एशिया के मुस्लिम समाज और अन्य देशों को अपने साथ रखने के लिया किया गया. सेकुलर सद्दाम ने ख़ूनी क़ुरआन लिखवाई जो उन्होंने अपने ही सत्ताईस लीटर ख़ून से लिखवाई थी. ये अलग बात है कि जिस तरीक़े से पश्चिमी देशों ने सद्दाम के साथ व्यवहार किया वह भी राजनीति से ही प्रेरित था. पहले तो सद्दाम से हाथ मिलाया, उसे हथियार और पैसा दिया, ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा किया और बाद में उसे ही मार डाला वह भी प्रजातंत्र और जनता के हितों के नाम पर. एक बार यही सद्दाम अमरीका के चहेते थे और यू.एन.ई.एस.सी.ओ. (यूनेस्को) ने सम्मानित किया था और फिर इसी सद्दाम को विलेन बनाकर फांसी दे दी गई.

मोहम्मद होस्नी सैयद मुबारक

ये मिस्र के चौथे राष्ट्रपति थे. 1975 में इन्हें उप- राष्ट्रपति का कार्यभार सौंपा गया और तत्कालीन राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या के बाद इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला. मुहम्मद अली पाशा के बाद ये सबसे अधिक दिनों तक राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति हैं. ये मिस्र की वायु सेना में कार्यरत थे और रूस की विकसित वायु सेना से भी इन्होंने ट्रेनिंग ली थी. आगे चलकर ये मिस्र की वायु सेना के अध्यक्ष बने. इस कारण 1973 के युद्ध में इज़रायल के विरुद्ध इनकी अहम भूमिका रही.

होस्नी मुबारक ने जब मिस्र की सत्ता संभाली तो उनके पीछे एक बहुत बड़ी परंपरा थी जिससे उन्हें प्रेरणा लेनी थी. वह उत्तराधिकारी थे अनवर सआदत के जिनको नोबल शांति पुरस्कार से नवाज़ा गया था. उससे भी पहले जनरल नसीर थे जो कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रतिपादकों में से एक थे. वे ऐसे व्यक्ति थे जिनकी राह पर पूरा अरब चलता था. वह अरब राष्ट्रवाद और इस्लामी समाजवाद के सबसे बड़े प्रणेता थे. होस्नी मुबारक ने भी अपना कार्यकाल इन्हीं लोगों के पद चिन्हों पर शुरू किया था, लेकिन वह भी सद्दाम, गद्दाफ़ी और आस-पास के बाक़ी इस्लामी राजाओं की ही तरह तानाशाह बनते चले गए. इज़रायल से शांति समझौता तो अनवर सआदत ने किया था जिस कारण से मिस्र की अरब

देशों में नेतागिरी कम हो गई और उसकी इस्लामी छवि पर भी बुरा प्रभाव हुआ, लेकिन होस्नी मुबारक ने इस इस्लामी छवि को सुधारने और अरब देशों के मुसलामानों के नेतृत्व को वापस हासिल करने का भरपूर प्रयास शुरू किया. इज़रायल और ईरान के मुद्दे पर अपने लोगों को कोई भी आज़ादी नहीं दी. इस्लाम के नाम पर उन्होंने सबके मुंह बंद करने की कोशिश की. उन्होंने देश पर तीन दशकों तक राज किया, लेकिन इसमें अधिकतर समय देश में आपातकाल रहा. आपातकालीन स्थिति में देश में सारे नियम क़ानून रद्द हो जाते हैं, जनता के सारे अधिकार भी निलंबित कर दिए जाते हैं. इस तरह होस्नी मुबारक ने देश की जनता का मुंह बंद रखा.

इन सारे तानाशाहों में एक बात समान थी. वह थी इस्लाम का ग़लत फ़ायदा उठाना. ग़लती जनता की भी थी. आख़िर एक समय था जब जनता ने ही इस्लाम को बचाने के नाम पर इन नेताओं को गद्दी सौंपी थी . लेकिन अच्छी बात यह है कि यह क्रांति जो आज पश्चिम एशिया और अरब देशों में खड़ी हो गई है वह इस्लाम के नाम पर न होकर प्रजातंत्र के नाम पर खड़ी हुई है. यह एक नए अरब राष्ट्रवाद का स्वरूप ले सकती है, लेकिन आज अरब देशों की जनता प्रजातंत्र मांग रही है न कि इज़रायल को मटियामेट करना. यह आज उतनी पश्चिम विरोधी नहीं है. मिस्र और लीबिया के लोग तो पश्चिम से नाराज़ हो गए, क्योंकि वहां से उन्हें कोई प्रोत्साहन और मदद नहीं मिल रही. लेकिन पश्चिमी देशों ने भी अपनी ग़लती समझी है. आख़िर इन तानाशाहों को तो उसी ने खड़ा किया था. इसी कारण अमरीका और ब्रिटेन सरीखे साम्राज्यवादी देशों ने भी जनता के साथ ही रहने का फ़ैसला किया. देखना यह है कि यह क्रांति किस हद तक सेकुलर रह पाती है. किस हद तक प्रजातंत्र इन देशों में स्थापित हो पाता है. एक और ख़ास बात, पहले यह लड़ाई किसी नेता के लिए उसकी अगुआई में हुई थी, आज यह लड़ाई ख़ुद जनता की है और नेतृत्व में है बस एक नारा-प्रजातंत्र.

feedback@chauthiduniya.com

मैं ख़ुद अपनी करनी का ज़िम्मेदार हूं. इसलिए जो भी फल मिलेगा, उसका ज़िम्मेदार मैं स्वयं हूं.

कर्मों का लेखा-जोखा

ऑसिम खेत्रपाल

बचपन से हमने अपने जीवन में कर्म को प्रधानता दी है. एक तरफ़ अध्यात्म से रची-बसी भारतीय पृष्ठभूमि तो दूसरी तरफ़ कर्मों की महत्ता. हर घर में बड़ों-बूढ़ों ने सदा ही सुकर्मों की तरफ़ ध्यान खींचा. गीता में भी कर्म की ही बात की गई है. कर्म-अकर्म, सुकर्म-विकर्म का संपूर्ण विवरण है, लेकिन ज़रूरत है इसे आज के संदर्भ में समझने की. कर्म सुकर्म तब बनता है, जब उसका फल सभी के लिए मीठा हो.

अकर्म तब होता है, जब कर्म का फल मिले और समाप्त हो जाए. विकर्म तब बनता है, जब उसका दुष्फल सबको भोगना पड़े. उदाहरण के लिए आपने आम का पेड़ लगाया. जब उससे फल निकले तो वे फल सिर्फ़ आपने खाए और अंत में उसे समाप्त कर दिया. तो यह पेड़ लगाना आपका अकर्म बन जाएगा, जिसका कोई भाग्य या प्रारब्ध नहीं बना. दूसरी तरफ़ आपने अगर पेड़ लगाया, फल आने पर आपने खाए और साथ में अन्य लोगों ने भी खाए. आपके न रहने के बाद भी वह पेड़ सालोंसाल फल देता रहा और उससे कई जीवों का पेट भरा, आपके पुण्य का खाता बढ़ता रहा. सोने पर सुहागा तो तब हो, जब आप उस फल को खाएं और उसके बीज या गुठली को फिर से बो दें, फिर से एक आम के पेड़ के लिए. यह सुकर्म आपके भाग्य को चमका कर आने वाले जन्मों तक आपके लिए खाने की कमी नहीं होने देता. तीसरी तरफ़ जब आपने ज़हरीला बीज बोया और अब उससे जो पेड़ तैयार होगा, उसमें फल भी निकलेगा, लेकिन हर फल ज़हरीला होगा और उसे खाने वालों में ज़हर फैलेगा. सोचें ज़रा कि अब क्या भाग्य बनेगा आपका?

तभी तो जैसा कर्म, वैसा भाग्य. यह है विकर्म, जिसका परिणाम दु:ख-दर्द, अकेलापन एवं अवसाद के रूप में हमारे सामने है. अब सवाल यह उठता है कि इतने जन्मों का लेखा-जोखा हमारे सामने है, कर्म का नियम है कि हर कर्म का हिसाब आएगा ही. हमारी दलील यह रहती है कि इस जन्म में जानबूझ कर हम कोई ग़लत काम नहीं करते, अनजाने में कुछ हो गया तो हम नहीं जानते. मुश्किल यह है कि हमने कर्म को सिर्फ़ कर्मकांड से जोड़ दिया है. क्या मैंने सही रीति से पूजा की, क्या यह तरीक़ा सही है, उपवास कैसे करना चाहिए आदि. हम इस पूरी प्रक्रिया में इस उधेड़बुन में लगे रहे कि भगवान हमसे ख़ुश हो जाए. वह कहीं हमसे नाराज़ तो नहीं है. पर यहां समझने की बात यह है कि न देवी-देवता और न ही भगवान हमारे किसी कर्म के भागीदार हैं और न ही ज़िम्मेदार.

मैं ख़ुद अपनी करनी का ज़िम्मेदार हूं. इसलिए जो भी फल मिलेगा, उसका ज़िम्मेदार मैं स्वयं हूं. हां, इतना अवश्य है कि परमात्मा का दिखाया रास्ता और मार्गदर्शन मेरे लिए सही निर्णय लेने में मदद करता है. मुझे सही दिशा देता है. लेकिन एक बार निर्णय लेने के बाद उस कर्म के अच्छे और बुरे फल की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी होती है. सच बात तो यह है कि हमारे हर कर्म का हिसाब आसमान में बैठा कोई चित्रगुप्त नहीं करता, बल्कि यह मेरे अपने ही अंर्तमन की अवचेतन अवस्था में निहित है. इसके परिणाम समय-समय पर मेरे सामने आते रहते हैं. याद रहे कि अगली बार कोई भी कर्म करने से पहले, जिसकी शुरुआत सोच या विचार से होती है, अपने अंदर जांचें कि यह कर्म मुझे किस ओर लेकर जाएगा. यक़ीन मानिए कि अंतरात्मा की आवाज़ ही आपका सही मार्गदर्शन करेगी. ओम साई राम

feedback@chauthiduniya.com

पहेली का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग साई सच्चरित्र का पाठ करें. सात दिन के अंदर इसका संपूर्ण पाठ करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी.

इस बार का प्रश्न है-साई बाबा को साई कहकर पुकारने वाला पहला व्यक्ति कौन था?

सही जवाब भेजने वाले तीन विजेता पाठकों को फाउंडेशन की ओर से आकर्षक ईनाम मिलेंगे. आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं इस पते पर

शिरडी साई बाबा फाउंडेशन,
एच 252, कैलाश प्लाजा, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश
नई दिल्ली- 110065
आप अपने जवाब info@ssbf.in भी पर भी भेज सकते हैं.
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. 011-46567351, 46567352

ग्यारह वचन

१. जो शिरडी आएगा। आपद दूर भगाएगा।
२. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर। पैर तले दुःख की पीढ़ी पर।
३. त्याग शरीर चला जाऊँगा। भक्त हेतु दौडा आऊँगा।
४. मन में रखना दृढ़ विश्वास। करे समाधी पूरी आस।
५. मुझे सदा जीवित ही जानो। अनुभव करो सत्य पहचानो।
६. मेरी शरण आ खाली जाए। हो कोई तो मुझे बताए।
७. जैसा भाव रहा जिस मन का। वैसा रुप हुआ मेरे मन का।
८. भार तुम्हारा मुझ पर होगा। वचन न मेरा झूठा होगा।
९. आ सहायता लो भरपूर। जो माँगा वह नही है दूर।
१०. मुझ में लीन वचन मन काया। उसका ऋण न कभी चुकाया।
११. धन्य धन्य व भक्त अनन्य। मेरी शरण तज जिसे न अन्य।

संपर्क करें:
शिरडी साईं बाबा फाउन्डेशन
252-H, LGF कैलाश प्लाज़ा, सन्तनगर, ईस्ट अफ़ कैलाश, मेन रोड, नई दिल्ली-110065.
Tel./Fax: 91-11-46567351/52
web: www.ssbf.in

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

कृष्ण की नगरी में आपका अपना घर!

Giriraj Sai Hills

Sai Vihar Township
Spiritual home... away from home

- Fully Furnished and Spacious studio Apartments.
- One Bedroom Apartments.
- Two bedroom Apartments.
- Fully Furnished Villas.

STARTING FROM RS. 9.65 LAKHS*

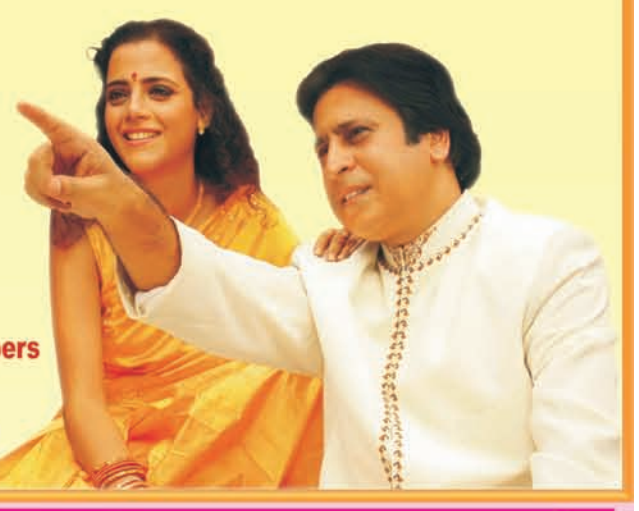

AUM Infrastructure & Developers
Aum Infrastructure & Developers
Email: info@ssbf.in
Website: www.girirajsaihills.in

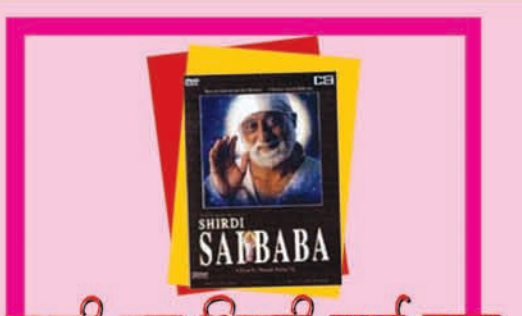

पहली बार शिरडी साई बाबा फीचर फिल्म अब कॉमिक्स के रूप में

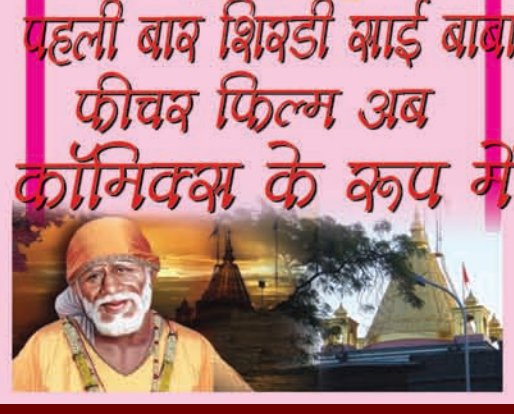

सभी साई भक्तों को विनम्रता से सूचित किया जाता है कि आप अपने साई अनुभव, साई उत्सवों आदि की विस्तृत सूचना, फाउंडेशन में सदस्यता के लिए info@ssbf.in पर मेल या 011-46567351/52 पर संपर्क कर सकते हैं.

पिछले साल अक्तूबर में जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति-चतुर्थ को होस्ट किया था तो पहले दिन की रेटिंग 6.2 प्वाइंट थी और पहले हफ्ते की औसत रेटिंग 5.3 रही थी.

शहंशाह के आगे बादशाह पस्त

अनंत विजय

फ़िल्म की दुनिया के एक प्रतिष्ठित अवॉर्ड समारोह में अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाना था. बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख़ ख़ान समारोह को संचालित कर रहे थे, उन्हें अमिताभ बच्चन को मंच पर आमंत्रित करना था. मंच के शिष्टाचार के मुताबिक़ शाहरुख़ ख़ान को आमंत्रण भाषण में अमिताभ बच्चन के योगदान को रेखांकित करते हुए उन्हें बुलाना था, लेकिन शाहरुख़ ख़ान ने एक बेहद व्यक्तिगत क़िस्सा सुनाते हुए कहा कि आज वह जो कुछ भी हैं, वह अमिताभ बच्चन की वजह से है. शाहरुख़ ने बताया कि जब वह कॉलेज में थे तो उन्होंने अपने माता-पिता से अमिताभ की फ़िल्म दीवार देखने की ज़िद की. शाहरुख़ के अब्बा ने कहा कि अगर परीक्षा में 95 फ़ीसदी अंक आ गए तो उन्हें फ़िल्म दीवार देखने की इजाज़त मिल जाएगी. उस फ़िल्म को देखने के लिए शाहरुख़ ने ज़ोरदार मेहनत की, फिर भी नब्बे फ़ीसदी अंक ही ला पाए, लेकिन पिता ने उदारता दिखाते हुए शाहरुख़ को दीवार देखने की इजाज़त दे दी. जब शाहरुख़ फिल्म देखकर लौटे तो अपनी अम्मी से बोले कि मुझे फ़िल्मों में काम करना है और अमिताभ बच्चन जैसा बनना है. मां ने कुछ देर सुना और फिर अपने बेटे से कहा कि पहले अपना क़द तो अमिताभ जैसा कर ले. मासूम शाहरुख़ अपनी लंबाई बढ़ाने में जुट गए, लेकिन प्रकृति पर किसी का वश नहीं चलता है, सो शाहरुख़ का भी नहीं चला. हारकर उन्होंने अपनी मां से बताया कि तमाम आसन-व्यायाम के बावजूद लंबाई नहीं बढ़ रही है. यह सुनते ही शाहरुख़ की मां हंसी और फिर गंभीर होकर बोलीं कि वह अमिताभ की लंबाई के बारे में नहीं, बल्कि काम के कद के बारे में बात कर रही थीं. शाहरुख़ ने अपनी मां की यह बात अपने पल्लू (शाहरुख़ के शब्द) से बांध ली और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. जोश में बोलते हुए शाहरुख़ ने यह भी बताया कि जब वह फ़िल्म मोहब्बतें में अमिताभ के साथ काम कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि वह जिस कॉलेज के लेक्चरार हैं, अमिताभ उस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं. यह बातें शाहरुख़ ने बेहद संजीदगी से भरी महफ़िल में सबके सामने सुनाईं.

शाहरुख़ की ये बातें बार-बार साबित भी होती हैं कि अमिताभ बच्चन अब भी बेहद लोकप्रिय हैं. चालीस साल से ज़्यादा समय से बॉलीवुड में काम कर रहे अमिताभ अब भी फ़िल्मी दुनिया के नए-पुराने नायकों पर भारी पड़ते हैं. बिग बी का जादू न केवल रुपहले पर्दे पर बरक़रार है, बल्कि छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न के भी वह बेताज बादशाह हैं. पिछले साल के अंत में और इस साल के शुरू में टेलीविज़न पर कई शो हुए, जिनमें फ़िल्म अभिनेता और अभिनेत्री जज या फिर होस्ट की भूमिका में दिखाई दिए, लेकिन कोई भी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति-चतुर्थ की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं पहुंच पाया. इमेजिन पर शाहरुख़ का बहु प्रचारित शो ज़ोर का झटका-टोटल वाइप आउट प्रसारित हुआ, जिसमें वह होस्ट की भूमिका में थे. ज़ोरदार प्रचार और शाहरुख़ के अपने अंदाज़ के बावजूद पहले हफ्ते की रेटिंग में यह शो कोई कमाल नहीं दिखा सका. शाहरुख़ के इस शो के पहले हफ्ते की रेटिंग देखें तो फ़िल्मी सितारों से जुड़े सीरियल में इसकी रेटिंग सातवें नंबर पर रही. यहां भी अमिताभ बच्चन नंबर वन की कुर्सी पर विराजमान हैं. पिछले साल अक्तूबर में जब अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति-चतुर्थ को होस्ट किया था तो पहले दिन की रेटिंग 6.2 प्वाइंट थी और पहले हफ्ते की औसत रेटिंग 5.3 रही थी. अमिताभ बच्चन के शो की रेटिंग की तुलना में शाहरुख़ के शो की रेटिंग कहीं नहीं टिकी. अमिताभ के शो के आसपास अगर कोई शो पहुंच पाया तो वह था झलक दिखला जा सीज़न चार, जिसमें धक-धक गर्ल माधुरी के अलावा मुन्नी बदनाम हुई फ़ेम मलाइका अरोड़ा भी जज हैं. झलक दिखला जा नामक इस शो में माधुरी होस्ट हैं और जब भी मौक़ा मिलता है, वह प्रतियोगियों के साथ ठुमके भी लगाती हैं. माधुरी

के इस शो के पहले दिन की रेटिंग 5.6 प्वाइंट थी और हफ्ते की औसत रेटिंग 4.9 रही. फ़िल्मी सितारों में लोकप्रियता के तीसरे पायदान पर रहीं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा, जिनके शो ख़तरों के खिलाड़ी को 5.5 की ओपनिंग मिली थी और उसके बाद रहा नेशनल बिंगो नाइट, जिसके होस्ट थे अभिषेक बच्चन. अभिषेक बच्चन के शो को भी 5.1 प्वाइंट की रेटिंग मिली थी. लोकप्रियता के मामले में दबंग ख़ान यानी सलमान ख़ान भी शाहरुख़ पर भारी पड़े. बिग बॉस, जिसके होस्ट सलमान ख़ान थे, उसे भी 4.8 प्वाइंट की ओपनिंग मिली थी. यहां तक कि बीते जमाने के हीरो और डिस्को किंग मिथुन चक्रवर्ती के शो डांस इंडिया डांस को भी ज़ोर का झटका से ज़्यादा टीआरपी मिली थी. मिथुन दा के उस शो को पहले हफ्ते में 4.8 प्वाइंट की रेटिंग हासिल हुई थी. शाहरुख़ ख़ान के शो जोर का झटका-टोटल वाइप आउट के शुरुआती एपिसोड को 2.6 प्वाइंट की रेटिंग मिली, जबकि पहले हफ्ते की औसत रेटिंग 2.8 रही. रेटिंग में शाहरुख़ ख़ान को भी ज़ोर का झटका धीरे से लगा और वह पहुंच गए अक्षय कुमार के क़रीब, जिनके शो मास्टर सेफ़ इंडिया को भी तक़रीबन इतनी ही यानी 2.6 की ओपनिंग मिली थी और पहले हफ्ते की औसत रेटिंग 2.2 रही थी.

शाहरुख़ की ये बातें बार-बार साबित भी होती हैं कि अमिताभ बच्चन अब भी बेहद लोकप्रिय हैं. चालीस साल से ज़्यादा समय से बॉलीवुड में काम कर रहे अमिताभ अब भी फ़िल्मी दुनिया के नए-पुराने नायकों पर भारी पड़ते हैं. बिग बी का जादू न केवल रुपहले पर्दे पर बरक़रार है, बल्कि छोटे पर्दे यानी टेलीविज़न के भी वह बेताज बादशाह हैं. पिछले साल के अंत में और इस साल के शुरू में टेलीविज़न पर कई शो हुए, जिनमें फ़िल्म अभिनेता और अभिनेत्री जज या फिर होस्ट की भूमिका में दिखाई दिए, लेकिन कोई भी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति-चतुर्थ की लोकप्रियता के आसपास भी नहीं पहुंच पाया.

अगर हम टीवी प्रस्तोता के तौर पर शाहरुख़ ख़ान के प्रदर्शन को देखें तो वह हमेशा से निराशाजनक रहा है. चाहे वह कौन बनेगा करोड़पति के होस्ट की भूमिका रही हो या फिर क्या आप पांचवीं पास से तेज़ हैं की. दोनों ही ज़बरदस्त तरीक़े से फ्लॉप रहे. दर्शकों ने दोनों शो को इस तरह नकारा कि चैनल ने क़रार के बावजूद शाहरुख़ से फिर कोई काम या शो होस्ट कराने की हिम्मत नहीं की. स्टेज या मंच पर शाहरुख़ का प्रदर्शन हमेशा से बेहतर रहता है. उनके जुमले और वनलाइनर का भी जवाब नहीं, लेकिन जब भी बॉलीवुड का यह बादशाह लगातार चलने वाले किसी शो में आता है या फिर उसे एंकर करता है तो दर्शकों को अपनी ओर खींच नहीं पाता है. वहीं दूसरी ओर अमिताभ बच्चन जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं या फिर प्रस्तोता की भूमिका में होते हैं तो उनके बोलने का अंदाज़ और संवाद अदायगी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है. कौन बनेगा करोड़पति में ख़ालिस हिंदी में बोले उनके जुमले हों या फिर अंग्रेज़ी के शब्द लॉक कर दिया जाए हों, हर किसी की ज़ुबान पर चढ़ जाते हैं. अमिताभ बच्चन के कितने डॉयलाग लोगों को ज़ुबानी याद हैं. वहीं अगर हम शाहरुख़ की फिल्मों के डॉयलाग पर नज़र डालें तो उनकी फिल्म डर के कि..कि..किरण को छोड़कर कोई भी डॉयलाग जनता की ज़ुबान पर चढ़ नहीं सका. यह सफलता का पैमाना नहीं हो सकता, लेकिन इससे सफलता के संकेत तो मिलते ही हैं. इस बात का पता चलता है कि आम जनता आपके अंदाज़ के साथ ख़ुद को कितना आईडेंटिफ़ाई कर पाती है. किसी भी अभिनेता को जनता जब अपने साथ, अपने व्यक्तित्व के साथ आईडेंटिफाई करने लगे तो समझिए कि वह उनके दिलों पर राज कर रहा है. अमिताभ के साथ यही हुआ और हो भी रहा है. चालीस साल के लंबे अंतराल में जब कई हीरो आए और गए, अमिताभ ने न केवल अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी, बल्कि अपने अभिनय और व्यक्तित्व के बल पर दर्शकों पर अपना जादू भी बरक़रार रखा. तभी तो उसी अवॉर्ड समारोह में शाहरुख़ ख़ान ने भी माना कि अमिताभ बच्चन एक्टिंग में सबके बाप हैं.

(लेखक आईबीएन-7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी
हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक
▶ दो टूक-संतोष भारतीय के साथ
▶ ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
▶ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
▶ स्पेशल रिपोर्ट
▶ नायाब हैं हम-उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
▶ साई की महिमा

एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301 www.chauthiduniya.tv

फेसबुक टीम के क़रीब मानी जाने वाली कंपनी आईएनक्यू ने वीडियो एवं तस्वीरों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से जुड़ी कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल फोन तैयार किया है.

कार की बहार

ऑडी का पेट्रोल इंजन 4.2 एल एफएसआई वी-8 367 बीएचपी पॉवर प्रोड्यूस करता है. जबकि डीजल वर्जन का 3.0 एल टीडीआई वी-6 इंजन 247 बीएचपी पॉवर प्रोड्यूस करता है.

भारत में लग्ज़री कारों में एक बड़ा नाम है ऑडी. भारतीय बाज़ार में ऑडी ने ए-8 नाम से एक नया मॉडल लांच किया है. ऑडी का यह मॉडल मर्सिडीज की एस क्लास और बीएमडब्ल्यू की 7 सीरीज का मुक़ाबला करेगा. इसके काफी फंक्शन ऑडी ए-4 से मिलते-जुलते हैं. अगर एक्टिरियर्स की बात करें तो फ्रंट साइड अलग ही लुक देता है और बेहद स्टाइलिश है. इस मॉडल के पेट्रोल और डीजल यानी दोनों वर्जन उपलब्ध हैं. ऑडी का पेट्रोल इंजन 4.2 एल एफएसआई वी-8 367 बीएचपी पॉवर प्रोड्यूस करता है. जबकि डीजल वर्जन का 3.0 एल टीडीआई वी-6 इंजन 247 बीएचपी पॉवर प्रोड्यूस करता है. इसकेअलावा ऑडी एक और मॉडल वर्ष की दूसरी तिमाही में पेश करेगी, जिसका इंजन 493 बीएचपी का होगा. तकनीक के मामले में भी यह कार अन्य कारों से कहीं आगे है. ऑडी ए-8 बीएमडब्ल्यू ग्रांड टूरिज्मो, जगुआर एक्सएफ, बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, वॉक्स वैगन फैंटन, बीएमडब्ल्यू 6 सीरीज और मर्सिडीज बेंज-एस क्लास को टक्कर देती है. कंपनी का दावा है कि इस सेगमेंट में यह कार सर्वाधिक लग्ज़री और कंफर्टेबल होगी. इस कार के 3 एक्सक्लूसिव वेरिएंटस बाज़ार में आने की उम्मीद है, जिनमें से 2 पेट्रोल मॉडल हैं और एक डीजल. सभी इंजन टर्बोचार्ज्ड हैं और डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम वाले हैं.

ऑडी-8 का पेट्रोल वेरिएंट टीएफएसआई क्वात्रो 8 सिलेंडर इंजन 290 पीएस पॉवर प्रोड्यूस करता है. डीजल वेरिएंट 8 स्पीड टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन से सुसज्जित है. इसका कंपार्टमेंट भी शानदार है. बाहर की ओर का मिरर बॉडी कलर से पेंट किया गया है. इसकी बॉडी पर दी गई क्रीज बोल्ड हैं और इसे अद्भुत लुक देती हैं. गाड़ी का इंटीरियर परंपरागत ऑडी ब्रांड जैसा है. ऑडी ए-8 में टर्बोचार्ज्ड डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन है. इस तकनीक से कम ईंधन में अधिक पावर मिलता है. ऑडी ए-8 3.0 टीएफएसआई क्वात्रो पेट्रोल 6 सिलेंडर के इंजन से सुसज्जित है.

इसका शक्तिशाली इंजन सिक्स स्पीड टिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन के साथ 62 मील प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में मात्र 6 सेकेंड का समय लेता है. जबकि ऑडी ए-8 4.2 लीटर टीएफएसआई पेट्रोल वेरिएंट में यह केवल 5.8 सेकेंड ही लेता है. कार की अधिकतम गति 155 मील प्रति घंटा है. ऑडी ए-8 की बॉडी बहुत संतुलित है, जिससे इसकी हैंडलिंग और मूवमेंट काफी सहज है. बड़ी कार पसंद करने वालों के लिए यह बहुत शानदार विकल्प है. इसका टर्निंग रेडियस लगभग 12.3 मीटर का है. ऑडी ए-8 की क़ीमत 72,50,000 से लेकर एक करोड़ 26 लाख रुपये तक है.

प्यास की नई आस

भारतीय खानपान उद्योग में अग्रसर कंपनी पारले एग्रो ने सोडा श्रेणी में प्रवेश किया है. पेय बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए संकल्पित पारले एग्रो का बैली सोडा उपभोक्ताओं पर किए गए अनुसंधान के परिणामों के आधार पर तैयार किया गया एक उत्पाद है. इस ब्रांड ने गैस की उच्च मात्रा के साथ द स्ट्रांग सोडा के रूप में ख़ुद को स्थापित कर लिया है. शोध के नतीजों से यह पता चला कि भारतीय उपभोक्ताओं को तीक्ष्ण स्वाद पसंद है. यह सोडा कंपनी की टैगलाइन मोर पावरफुल दैन पावरफुल, वी फुलफिल दिस कन्ज्यूमर नीड के पूर्णत: अनुकूल है. स्ट्रांग सोडा की बोतल का आकार एक ग्रेनेड के समान है, जो काफी आकर्षक है. आर्मी कैमोलॉज थीम के अनुरूप इस्तेमाल किया जाने वाला लेबल बैली सोडा की अनूठी एवं विशिष्ट पैकेजिंग को प्रदर्शित करता है. दो तरह की पैकिंग में लांच किया गया बैली सोडा 600 एवं 300 मिली की बोतलों में उपलब्ध है, जिनकी क़ीमत क्रमश: 14 और 9 रुपये है. यह एक मात्र ऐसा सोडा ब्रांड है, जो 300 मिली की बोतल में उपलब्ध है. यह निर्णय पारले एग्रो की उस एसकेयू रणनीति से मेल खाता है, जो ग्रामीण बाज़ारों में इस ब्रांड के बेहतर वितरण एवं घुसपैठ को सुनिश्चित करती है. बोतल का यह आकार सिंगल सर्व उपभोक्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करता है, जो एक बोतल को खोलते समय हर बार एक सनसनाती ताज़गी से रूबरू होने के ख्वाहिशमंद होते हैं.

फोटो- सुनील मल्होत्रा

नई दिल्ली में वरसेस घड़ी की नई सीरीज पेश करते हुए बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु

डर्ट बाइकिंग इज फन

कावासाकी ने डर्ट बाइकिंग के लिए 2011 मॉडल कावासाकी के एक्स 450 एफ को कुछ समय पहले अमेरिका में एक डर्ट रेसिंग ट्रैक पर उतारा था. निश्चित रूप से डर्ट बाइकिंग में कावासाकी की बाइक्स काफी पसंद की जाती हैं. बाइक के लुक के बारे में यही कहा जा सकता है कि पहली नज़र में यह अपने पूर्ववर्ती मॉडल की तरह लगती है. कावासाकी ने इसमें कुछ बदलाव करके इसे 2011 मॉडल के नाम से बाज़ार में उतारा है. बाइक के इंजन का परफार्मेंस काफी अच्छा है, हालांकि इसके लुक में थोड़ा बदलाव किया जाना चाहिए. आख़िर कावासाकी इसके लिए 8149 डॉलर वसूल रही है. इस ख़ास बाइक का इंजन 449 सीसी लिमिटेड कूल्ड सिंगल डीओएचसी और 4 वॉल्व है, जो इसे ज़बरदस्त मज़बूती प्रदान करता है. इसका फ्रंट सस्पेंशन कायाबा एओएस 48 एमएम फोर्क है और यह 22 पोजीशन कम्प्रेशन एवं 20 पोजीशन रिबाउंड डंपिंग एडजस्टमेंट से लैस है, जिससे बाइक चलाना हो जाता है और भी आसान. इसका रियर सस्पेंशन यूनीट्रैक कायाबा गैस चार्ज्ड शॉक 22 पोजीशन लो स्पीड एवं स्टेप लैस हाई स्पीड कम्प्रेशन डंपिंग देता है, जिससे बहुत ज़्यादा उबड़-खाबड़ सड़कों पर भी बाइक और राइडर को कोई नुक़सान नहीं पहुंचता है. इसकी फ्यूल डिलीवरी फ्यूल इंजेक्शन के ज़रिए होती है. इसका क्लच मल्टी प्लेट केबल एक्चुएशन है, जिससे चालक को काफी आसानी होती है. इसके 5 गियर ट्रांसमिशन राइडर को काफी कंफर्टेबल करता है. इस स्टाइलिश बाइक में फ्रंट ब्रेक में 250 एमएम पेटल डिस्क है और ड्यूल पिस्टन कैलिपर लगे हैं. रियर ब्रेक 240 एमएम पेटल डिस्क है और एक पिस्टन कैलिपर है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

इस ख़ास बाइक का इंजन 449 सीसी लिमिटेड कूल्ड सिंगल डीओएचसी और 4 वॉल्व है, जो इसे ज़बरदस्त मज़बूती प्रदान करता है. इसका फ्रंट सस्पेंशन कायाबा एओएस 48 एमएम फोर्क है और यह 22 पोजीशन कम्प्रेशन एवं 20 पोजीशन रिबाउंड डंपिंग एडजस्टमेंट से लैस है, जिससे बाइक चलाना हो जाता है और भी आसान.

फेसबुक का फोन

दुनिया भर में पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के क़दम अब नए धंधे की तरफ़ हैं. ख़बर है कि फेसबुक अब बाज़ार में मोबाइल फोन लाने की तैयारी में है. एक मोबाइल फोन निर्माता कंपनी पहला फेसबुक फोन लाने वाली है. मोबाइल निर्माता कंपनी आईएनक्यू मोबाइल ने ऐलान किया है कि 18 से 28 वर्ष की उम्र वाले फेसबुक उपयोगकर्ताओं के लिए दो प्रकार के एंड्रॉयड स्मार्ट फोन तैयार किए गए हैं. आईएनक्यू क्लाउड टच और आईएनक्यू क्लाउड क्यू नामक मोबाइल फोन सबसे पहले इंग्लैंड के बाज़ार में उपलब्ध कराए जाएंगे. बताया जा रहा है कि फेसबुक टीम के क़रीब मानी जाने वाली कंपनी आईएनक्यू ने वीडियो एवं तस्वीरों के साथ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से जुड़ी कई अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस मोबाइल फोन तैयार किया है. उपभोक्ता इस नए फेसबुक मोबाइल फोन से चैटिंग एवं संदेश प्रेषण समेत कई अन्य सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे. आईएनक्यू के सह संस्थापक केन जॉनस्टन ने कहा, इस मोबाइल से उसी तरह संदेश भेजा जा सकेगा, जैसे हम फेसबुक में वाल पर लिखकर भेजते हैं.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सूबे के लिए गौरव का विषय रहा, लेकिन समाज के गरीब तबकों के लिए यह अभिशाप बनकर सामने आया.

करे कोई भरे कोई

राजेश एस कुमार

हमारे देश में क्रिकेट के अलावा लगभग सभी खेलों की स्थिति एक जैसी है यानी बदहाल और उपेक्षित. भले ही वे क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले खेल हों या फिर राज्य स्तर पर. जब भी इन खेलों का आयोजन होता है, कभी मेज़बानी को लेकर समस्या पैदा हो जाती है तो कभी प्रायोजकों की भागीदारी को लेकर. अगर भूले-भटके उक्त दोनों समस्याओं से निजात मिल भी जाए तो असुविधा और बदइंतज़ामी मार जाती है. इन सभी समस्याओं से इतर भी एक समस्या है, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता हो. यह समस्या है उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की, जो इन बदइंतज़ामियों के शिकार हो जाते हैं. उनका करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है. कई सालों के अथक परिश्रम और प्रशिक्षण के बाद वे इस तरह की प्रतिस्पर्धाओं के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कब ये खेल राजनीति या फिक्सिंग के शिकार होकर उनका करियर चौपट कर देंगे.

33वें राष्ट्रीय खेलों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी. वर्ष 2003-2004 में उसके आयोजन के लिए हरी झंडी भी मिल गई थी, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि उस आयोजन के रद्द होने के पीछे क्या कारण थे. ऐसा नहीं है कि इन खेलों का आयोजन एक बार ही रद्द हुआ हो, चार बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन रद्द हो चुके हैं. अब जाकर ये खेल संपन्न हुए हैं. लोग जश्न मना रहे हैं. कई प्रतिस्पर्धाओं में झारखंड के खिलाड़ियों ने कई पदक भी अपने नाम किए हैं, लेकिन इस बार प्रतिस्पर्धा में शामिल होने वाले खिलाड़ी नए थे. इनमें वे खिलाड़ी नहीं थे, जो पिछले आयोजन को लेकर तैयार थे. पुराने खिलाड़ी अपनी प्रतिभा दिखाने से वंचित रह गए. अगर ये राष्ट्रीय खेल सही समय पर होते तो इनकी तस्वीर कुछ और ही होती. खेल संघ को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस दौरान खिलाड़ियों का कितना क़ीमती वक्त बर्बाद हुआ. उन्हें सही समय पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौक़ा नहीं मिला.

ग़ौरतलब है कि हर बार राष्ट्रीय खेलों के ज़रिए खिलाड़ियों की एक नई पीढ़ी उभर कर सामने आती है, लेकिन अगर एक बार प्रतिस्पर्धा रद्द हो जाए या मेज़बानी छिन जाए तो न जाने कितनी प्रतिभाएं गुमनामी में खो जाती हैं. जिन खिलाड़ियों को पिछली बार अवसर नहीं मिला, उनमें से कुछ खिलाड़ी इस बार की प्रतिस्पर्धा में शामिल तो हुए, पर उम्र ज्यादा होने या अन्य कारणों से भाग लेने से वंचित रह गए. झारखंड में खेलों की बदहाली के पीछे के कारणों को समझना जरूरी है. दरअसल जब भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो सभी राज्यों को मेज़बानी के लिए दावेदारी करनी होती है. यह दावेदारी राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली बेहतरीन सुविधा के आधार पर मजबूत होती है. बस इसी मामले में झारखंड की हालत ढीली हो जाती है. इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता कि अगर एक बार मेज़बानी छिन जाए तो कितना नुक़सान होता है. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को नुक़सान तो होता ही है, साथ ही राज्य को आर्थिक क्षति भी होती है. उदाहरण के लिए आयोजन के पहले विज्ञापन हेतु लाखों रुपये ख़र्च हो जाते हैं. कई समितियां बनाई जाती हैं, जिन पर मोटा ख़र्च आता है. इसके अलावा जो बदनामी होती है, वह अलग. इस सबके बावजूद झारखंड ने महेंद्र सिंह धोनी के अलावा हॉकी, तीरंदाज़ी, एथलेटिक्स और अन्य खेलों में कई बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं. सोचने वाली बात यह है कि अगर इस सुविधाविहीन माहौल में इतनी प्रतिभाएं पैदा हो सकती हैं तो फिर अगर सब कुछ सही समय पर और सुविधाओं के साथ हो तो खेलों और खिलाड़ियों का भविष्य कितना उज्ज्वल होगा.

rajeshy@chauthiduniya.com

34वें राष्ट्रीय खेल

बदइंतज़ामी भारी पड़ी

नवल किशोर सिंह

झारखंड में पंचायत चुनावों के बाद राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन मुंडा सरकार की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जोड़ गया. कई बार आयोजन की तिथि टलने के बाद राज्य के हाथों से इसकी मेजबानी छिन जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया था. अभी भी आयोजन समिति की तैयारियां आधी-अधूरी ही थीं, लेकिन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और खेल मंत्री सुदेश महतो की दृढ़ता के कारण भारतीय ओलंपिक संघ, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन और राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति को सक्रिय होकर शेष तैयारियां निर्धारित समय सीमा के अंदर करनी पड़ीं. इन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन काफ़ी भव्य तरीक़े से किया गया, लेकिन व्यवस्था संबंधी गड़बड़ियां भी अपने चरम पर रहीं. उद्घाटन के दिन बालीवुड के कई सितारे बुलाए गए. प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने कार्यक्रम का रोचक ढंग से संचालन कर लोगों को आकर्षित किया. कलाकारों ने राज्य की संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम पेश किए. मुख्य स्टेडियम में लघु भारत का नज़ारा दिखा.

राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सूबे के लिए गौरव का विषय रहा, लेकिन समाज के गरीब तबकों के लिए यह अभिशाप बनकर सामने आया. आयोजन के एक पखवारे पूर्व से ही पूरे शहर में फुटपाथ के दुकानदारों और ठेला-खोमचा वालों पर पुलिस का कहर टूट पड़ा. उनकी रोज़ी-रोटी का आधार छीन लिया गया. ऑटो चालकों पर भी प्रशासन की गाज गिरी. क़रीब पांच हज़ार लोगों के 50 हज़ार आश्रितों के सामने दो जून रोटी की व्यवस्था करना कठिन हो गया. प्रशासन ने उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं समझी. रोज़ कमाने-खाने वालों पर राष्ट्रीय खेल बहुत भारी गुज़रे. शहर की यातायात व्यवस्था पर भी इसका असर पड़ा. सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री के कारण आवागमन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में बाधा पड़ी. शहर में जहां-तहां लोगों को वाहन चेकिंग के नाम पर परेशान किए जाने और अवैध वसूली का सिलसिला जारी रहा. इस तरह आम लोग इस आयोजन से ख़ुश कम, पीड़ित ज़्यादा नज़र आए.

बाहर से आए खिलाड़ियों के ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें भी मिलती रहीं. हालांकि इस आयोजन में आवागमन की सुविधा के लिए क़रीब 10 हज़ार लग्ज़री वाहन किराए पर लिए गए, जिन पर प्रतिदिन क़रीब एक करोड़ रुपये का ख़र्च आया. भोजन पर भी प्रतिदिन 50 लाख रुपये ख़र्च किए गए. उद्घाटन और समापन समारोह पर भी करोड़ों रुपये फूंके गए. जब राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी मिली थी तो अनुमानित खर्च 500 करोड़ रुपये था, लेकिन तिथि टलने के साथ-साथ बजट भी बढ़ता गया. सिर्फ़ रांची में स्टेडियम और भवन निर्माण (खेलगांव) पर ही क़रीब 100 करोड़ रुपये का ख़र्च आया. जमशेदपुर और धनबाद में आयोजित होने वाली खेल प्रतिस्पर्धाओं की तैयारियों का ख़र्च भी कई गुना बढ़ गया.

यह आयोजन प्रारंभ से ही वित्तीय अनियमितताओं के कारण चर्चा में रहा. खेल सामग्रियों की ख़रीददारी से लेकर अन्य तमाम मदों में काफ़ी गड़बड़ी की शिकायतें मिलती रहीं. निगरानी विभाग और उच्च न्यायालय में मामले भी दर्ज किए गए. झारखंड कुश्ती संघ के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने तत्कालीन खेल सचिव रविशंकर वर्मा, खेल निदेशक पी सी मिश्रा, आयोजन समिति के महासचिव एस एम हाशमी और कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक के विरुद्ध खेल सामग्रियों की खरीद सहित अन्य मदों में 51 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया. निगरानी में इनके विरुद्ध मामला लंबित है. दूसरी तरफ़ महालेखाकार ने भी वित्तीय अनियमितताओं के मद्देनज़र आयोजन के बाद सभी कमेटियों को बरक़रार रखने का निर्देश दिया है. सभी खर्चों की विस्तृत जांच-पड़ताल की जाएगी. बहरहाल, अगर कॉमनवेल्थ खेलों की तरह यह आयोजन भी अपनी गड़बड़ियों के लिए लंबे समय तक चर्चा में रहे तो कोई हैरत की बात नहीं होगी.

feedback@chauthiduniya.com

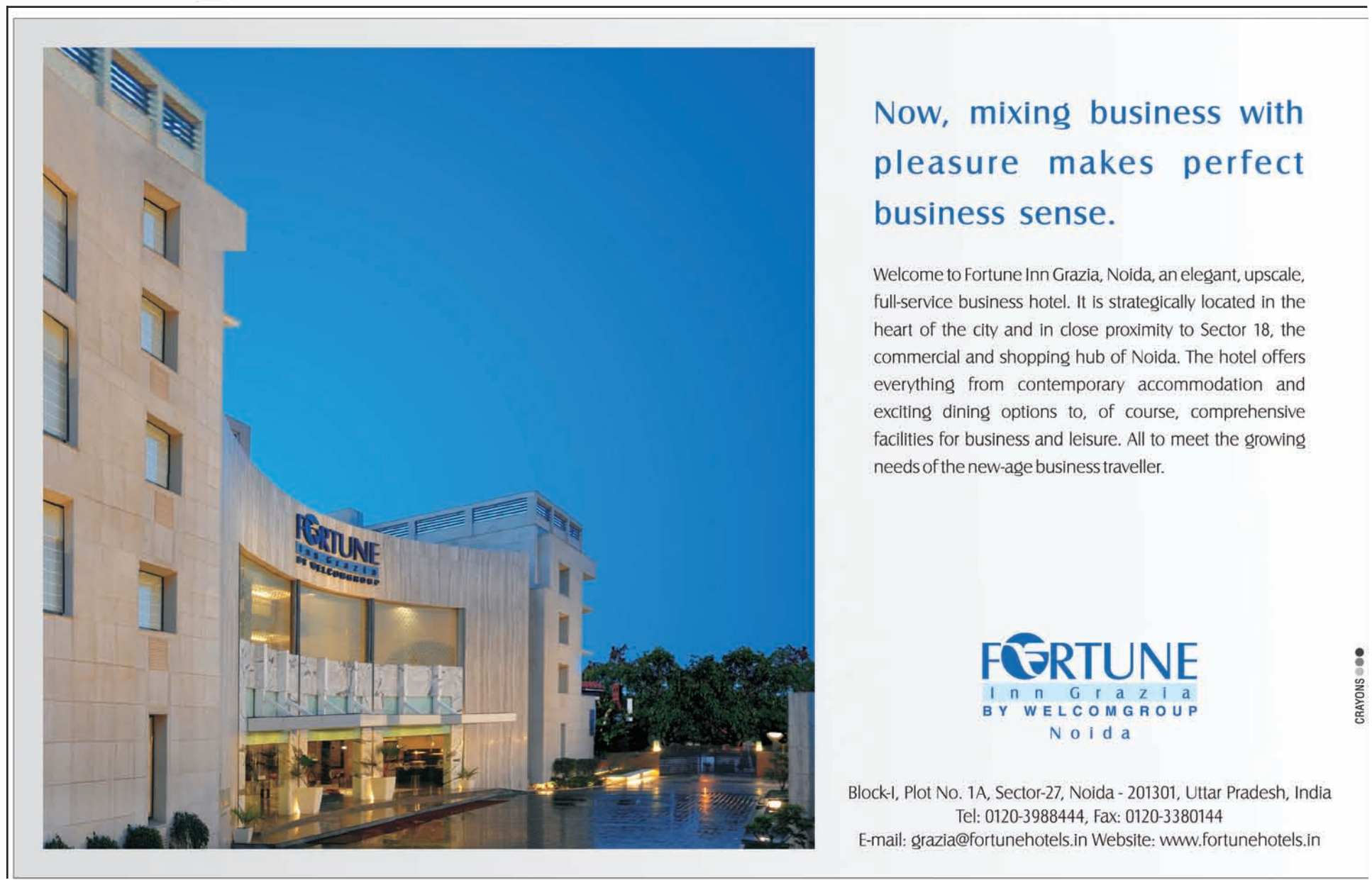

एक कॉलोनी बसाने के लिए कम से कम दस एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है. विभिन्न शहरों में 13 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

यह वन अधिनियम के ख़िलाफ़ है. इन निर्देशों के कारण प्रशासन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब शिवभक्तों को भगवान भरोसे धाम तक पहुंचना है.

एक नज़र

केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना का संकल्प

मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर आईएमए हाल में मीडिया ग्रुप के तत्वावधान में एक बैठक आयोजित की गई. इसमें मौजूद सभी वक्ताओं ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर संघर्ष का बिगुल फूंकने का निर्णय लिया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समाजसेवी सह राजद के वरीय नेता बजरंगी नारायण ठाकुर ने कहा कि वे इसके लिए पूरे चंपारण के लोगों के सहयोग से संघर्ष का बिगुल फूंकेंगे. वही जदयू के वरीय नेता राय सुंदरदेव शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि सभी लोग अब एक मंच पर आएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए संघर्ष की धार तेज़ करें. इस मौक़े पर केसरिया विधायक संजय सिंह, अब्दुल हमीद कैप्टन,संजय कौशिक के अलावा मीडिया ग्रुप के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद थे.

रक्सौल स्टेशन रोड क्षेत्र में अवैध दुकानें

रक्सौल में अवैध रूप से संचालित हो रही है स्टेशन रोड की दुकानें. जब रेल अधिकारी आते हैं तो रोड किनारे अतिक्रमण कर लगाई गई दुकानों को रेलवे सुरक्षा बल द्वारा हटा दिया जाता है, परंतु अधिकारियों के जाते ही फिर से दुकान सज जाती हैं. वैसे प्रतिष्ठान संचालक जबरन रेल की भूमि का अतिक्रमण नहीं करते हैं. इसके लिए दुकानदार रेलवे के विभिन्न महकमों को सुविधा शुल्क देते हैं, इसी वजह से मुख्य प्रवेश द्वार से मुख्य पथ तक अतिक्रमण कर दुकानें चल रही हैं. जिससे सरकार को हर साल चूना लग रहा है.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

पौधे बर्बाद हो रहे हैं

मोतिहारी में मनरेगा के तहत घोड़ासहन नहर तटबंध पर लगे वृक्ष फल देने से पूर्व ही नहर से निकाली गई मिट्टी में दबकर दफन होने लगे हैं. इन्हें बचाने के लिए कोई ठोस उपाय न ही मनरेगा कार्यालय कर रहा है और न ही अनुमंडल अंतर्गत पंचायत के मुखिया. इस कारण पौधों पर सरकार द्वारा ख़र्च किए गए लाखों रुपये बर्बाद हो रहे हैं. इस स्थल पर सागवान के पौधे लगाए गए, परंतु इस क्षेत्र में दूर-दूर तक एक भी पौधा दिखाई नहीं पड़ता. उधर मनरेगा के पदाधिकारी जितेंद्र कुमार का कहना है कि उन्होंने स्थल का निरीक्षण किया है. पौधे बड़े हो गए हैं. इस मिट्टी से कोई खास क्षति नहीं होगी. एक अनुमान के मुताबिक नहर की सफ़ाई में निकलने वाली मिट्टी से हजारों पौधे दबकर नष्ट हो जाएंगे.

–चौथी दुनिया ब्यूरो

जनप्रतिनिधियों को कोई सुविधा नहीं मिली

राज्य में 32 वर्षों बाद संपन्न पंचायत चुनाव में चुने गए जनप्रतिनिधियों को अबतक कोई सुविधा नहीं मिली है. यहां तक कि ज़िला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी, उपाध्यक्ष परिमल कुमार सिंह उर्फ़ भूपेन सिंह को भी कार्यालय में बैठने एवं जनसमस्याओं को सुनने का स्थान नहीं उपलब्ध कराया गया है. वहीं पंचायत के प्रमुख एवं मुखिया को भी उचित स्थान न मिलने से जनप्रतिनिधियों में असंतोष पनप रहा है. चुने गए जनप्रतिनिधियों को ज़िला प्रशासन की ओर से सुविधा न उपलब्ध कराने का मामला ज़ोर पकड़ने लगा है. ज़िला परिषद अध्यक्ष किरण कुमारी ने बताया कि जनता की परेशानियों का निदान के लिए भी अबतक कोई गाइड लाइन अथवा नियम आदि उपलब्ध नहीं कराए हैं, जबकि ज़िला प्रशासन की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के आदेश जारी किए जा रहे हैं.

–रणजीत झा

नीतीश कुमार की आलोचना

भारत सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं में से एक अति महत्वकांक्षी योजना मनरेगा के कुछ साल पूरे होने पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया. यह आयोजन पंचायत भवन विद्यापति मार्ग में हुआ. इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी महबूब अली कैसर ने अपने भाषण में एक ओर जहां पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बधाई दी, वहीं नीतीश सरकार की कड़ी आलोचना की. इसी अवसर पर बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ. अनिल सुलभ ने कहा कि कांग्रेसजन को केंद्र पोषित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन के कार्य अपने हाथ में लेने चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपने स्तर से बीपीएल समेत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों की सूची स्वयं बनाएं तथा जहां भी उन्हें लगे कि सही व्यक्तियों के नाम सूची में नहीं है तो न केवल इसके लिए विरोध जताएं बल्कि इसमें उनके नाम जोड़ने के लिए संबद्ध व्यक्तियों को बाध्य करें. साथ ही इस बात की तस्दीक करें कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है या नहीं.

तबले का नन्हा उस्ताद

महनार बाज़ार के स्टेशन रोड निवासी रमेश पोद्दार का सात वर्षीय पौत्र कुमार आदर्श तबला वादन के क्षेत्र में उस्ताद होता जा रहा है. कुमार आर्दश को तीन वर्ष की उम्र से ही संगीत का लगाव था, इसलिए उसके दादा ने उसका तबला वादन आरंभ करवाया. वर्तमान में सने महनार महोत्सव ,वैशाली महोत्सव, संत निरंकारी समागम, वाराणसी, सोनपुर, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि के कार्यक्रम में अपनी कला प्रदर्शन कर पुरस्कृत हो चुका है. वैशाली डीएम भी इस नन्हे कलाकार को पुरस्कृत कर चुके हैं. रमेश पोद्दार की इच्छा है कि मुख्यमंत्री आदर्श को अपने आवास पर बुलाकर उसका मनोबल बढ़ाएं.

उर्दू की किताबों की दुर्दशा

राज्य की द्वितीय राज्यभाषा होने के बावजूद सरकारी अधिकारियों द्वारा उर्दू के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है. महनार प्रखंड के संसाधन केन्द्र में उर्दू की सैकड़ों पाठ्य पुस्तकें ख़राब हो रही हैं और मेस चलाने वाले इसका रद्दी में उपयोग कर रहे हैं. वहीं उर्दूभाषी बच्चे पुस्तक के लिए बिलबिला रहे हैं. इस संबंध में विधायक डा. अच्युतानन्द ने प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कुमुद झा को अविलम्ब पुस्तक वितरण करने का निर्देश दिया था, किन्तु उनके निर्देश को बीईईओ ने ताक पर रख दिया. सूत्र बताते हैं कि जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के पीछे जिस तरह पुस्तकें जलाई गईं थीं इसी तरह इसे भी जलाकर अल्पसंख्यक छात्रों को इनकी मातृभाषा से वंचित कर देने की साजिश है. इस विषय पर जब बीईईओ से पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया.

अंग्रेज़ी ज्ञान समय की मांग : नवीन मिश्रा

अंग्रेज़ी ज्ञान समय की मांग है तथा इसके बिना सफलता अधूरी है. यह बात जेड जेनियम इंग्लिश स्पोकन सेंटर के डायरेक्टर नवीन मिश्रा ने एक समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए कहा. उन्होंने बताया कि इनके संस्थान के दर्जनों छात्र आज विदेश में नौकरी कर रहे हैं तथा उनका सपना है कि महनार का एक-एक बच्चा अंग्रेज़ी सीखे . श्री मिश्रा ने बताया कि इनकी योजना है कि अगले वर्ष से गरीब बच्चों को पोशाक,पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य तरह की सहायता संस्थान की तरफ़ से मिल सकें. उन्होंने बताया कि संस्थान शीघ्र ही कंप्यूटर शिक्षा पर भी ध्यान देगी.

–अंजुम परवेज़

यातायात जाम से महनारवासी परेशान

प्रशासन की लापरवाही के कारण महनार बाजार में यातायात जाम एक दिनचर्या बन चुकी है. मदन चौक पर रिक्शा, ठेला, न्यू रोड में विक्रम, स्टेषन रोड में टेम्पो तथा अस्पताल रोड में बस, जीप इत्यादि आधे से अधिक सड़क पर कैंजा जमाए रहते हैं. अस्पताल के मुख्य द्वार पर ही बस पड़ाव बना ली गई है, जबकि ये साइलेन्स जोन के दायरे में आता है. इस संबंध में कइ बार जिलाधिकारी ने थानाध्यक्ष को कार्रवाई का आदेश दिया है किन्तु पुलिस इस मामले में बिल्कुल खामोश है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पुलिस और नक्सलियों के बीच पिसते लोग

इमामगंज विधानसभा क्षेत्र

सुनील सौरभ

झारखंड की सीमा से लगे बिहार के गया ज़िले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग राज्य में विकास के तमाम दावों को झुठलाते हुए पुलिस और नक्सलियों के बीच पिस रहे हैं. इनकी जान संसत में पड़ी है. इस विधानसभा क्षेत्र का चप्पा-चप्पा प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के प्रभाव में है. प्रतिदिन कोई न कोई घटना होती रहती है. पुलिस भी खानापूर्ति के लिए ही सही कुछ न कुछ करती रहती है. नतीजा यह है कि जंगल और पहाड़ों से आच्छादित यह क्षेत्र जहां विकास के लिए छटपटा रहा है, वहीं दूसरी ओर पुलिस व नक्सली प्रताड़ना से मुक्ति की चाहत में है.

डुमरिया प्रखंड की छकरबंधा पंचायत का बरहा गांव आज पुलिस-नक्सली की हरकतों से कराह रहा है. गत 17 जनवरी को इस गांव के बाहर नक्सलियों द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंग में सीआरपीएफ़ का एक जवान शहीद हो गया था. इस ही घटना के बाद इस गांव के लोगों पर आफ़त का पहाड़ टूट पड़ा. पुलिस गांव के सैकड़ों लोगों को हिरासत में लेकर नक्सली साबित करने पर तुली हुई है. वहीं चारों ओर नक्सलियों का बसेरा होने के कारण गांव वाले कुछ भी कहने से डरते हैं. एक ओर कुंआ तो दूसरी ओर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है. फिर भी पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को नक्सली घटनाओं में संलिप्त होने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया. बरहा गांव में स्थित स्कूल भवन में सीआरपीएफ़ का कैंप बना दिया गया. लगभग एक पखवाड़े तक पुलिस कैंप रहा. पुलिस कैंप के हटते ही नक्सलियों ने बरहा गांव के

स्कूल भवन को ही डायनामाइट लगाकर उड़ा दिया, जबकि ग्रामीण नक्सलियों से मनुहार करते रहे कि वे ऐसा न करें, परंतु नक्सली नहीं माने और यह कहते हुए उड़ा दिया कि यह भवन पुलिस का ठिकाना बनता जा रहा है. इसलिए इसे नहीं रहना चाहिए. यह स्थिति सिर्फ़ बरहा गांव की ही नहीं, बल्कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड इमामगंज, डुमरिया, बांकेबाज़ार की भी है. पूरे क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की समानांतर सरकार चलती है.

कहने को वर्तमान राज्य की सरकार सुशासन और विकास की बात करती है, लेकिन इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की स्थिति पर कोई टिप्पणी तक नहीं की जाती, क्योंकि यहां से जदयू के निर्वाचित प्रतिनिधि उदय नारायण चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं. दबी ज़बान में यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने विधानसभा चुनाव में जदयू प्रत्याशी का विरोध किया, उन लोगों को सबक़ सिखाया जा रहा है. हालांकि, बरहा के निर्दोष लोगों की गिरफ़्तारी पर राजद के पूर्व सांसद रामकृपाल यादव समेत अनेक वरिष्ठ नेता इमामगंज में धरना-प्रदर्शन में शामिल हो चुके हैं. इस विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद है, क्योंकि अधिकतर गांवों में स्कूल भवन ही नहीं हैं. जहां बचे हैं वहां या तो पुलिस कैंप है या फिर उन्हें नक्सलियों ने ध्वस्त कर दिया है. दूसरी ओर पदस्थापित शिक्षक भी ग्रामीणों, पंचायत प्रतिनिधियों, नक्सलियों को मैनेज कर अपना वेतन उठा रहे हैं. पुलिस की निर्दोष लोगों पर कार्रवाई किए जाने से ग्रामीण परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों का घेरा भी ग्रामीणों को परेशान कर रहा है. फलतः इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकांश समर्थ लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. गांव से पलायन करना उनकी लाचारी हो गई है. फिर भी राज्य सरकार पूरे दुनिया में विकास की नई इबारत लिखने की बात कर रही है.

> पूरे क्षेत्र में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की समानांतर सरकार चलती है. ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह बंद है. बरहा गांव में स्थित स्कूल भवन में सीआरपीएफ़ का कैंप बना दिया गया.

feedback@chauthiduniya.com

मवेशियों की तस्करी सीमांचल के रास्ते होती है

नीरज कुमार सिंह

सीमांचल में मवेशियों की तस्करी बदस्तूर जारी है. आज पूर्णिया का बायसी, दालकोला, कटिहार का बलरामपुर थाना, समेत किशनगंज व पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर ज़िला पशुओं की तस्करी का डंम्पिंग स्टेशन बना हुआ है. यह इलाक़ा बंग्लादेश की सीमा से लगता है, जिससे यहां डंप मवेशियों को रात्रि में बॉर्डर पार कराने में कोई दिक्क़त नही होती है. ये पशु तस्कर दबंग अपराधी प्रवृत्ति व हथियारों से लैस रहते हैं, जिसके सामने आम लोग तो क्या बड़ों की भी बोलती बंद रहती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय मवेशियों की बांग्लादेश में काफ़ी मांग है, जिससे इनको बांग्लादेश में मुंहमांगी क़ीमत मिल जाती है. इसी वजह से कई संगठित गिरोह इस धंधे में जुट गए हैं. मवेशियों की तस्करी के दो तरीक़े हैं. पहला पूर्णिया, अररिया, कटिहार व किशनगंज के स्थानीय हाटों में ख़रीदे गए पशुओं को पैदल चलाकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है, वहीं राज्य के दूरस्थ ज़िलों व अन्य राज्यों से मवेशियों को बड़े-बड़े ट्रकों में भरकर सीमावर्ती क्षेत्रों में लाया जाता है. फिर इन ट्रकों को इंट्री माफ़िया के द्वारा पास कराया जाता है. एंट्री माफ़िया की मिलीभगत बिहार के परिवहन विभाग से लेकर पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग तक है. पश्चिम बंगाल के फुलवाड़ी, मैनागुड़ी, माथाभंगा, कुचबिहार रामगंज, कच्चीकली जैसे कई ऐसे स्थान हैं, जहां से पशुओं को बांग्लादेश भेजा जाता है. कभी-कभी भारतीय तस्करों का मवेशी माल बांग्लादेशी तस्कर एवं एजेंट हज़म कर जाते हैं. इससे इनको नुक़सान पहुंचता है और बांग्लादेश की सीमा के अंदर चले जाने के कारण उनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं. तस्करों को बंगाल पुलिस से लाइन मिलने का इंतज़ार करना पड़ता है. मवेशी तस्करी से जुड़े लोगों का कहना है कि पुलिस को हर माह सुविधा शुल्क जमा करना पड़ता है. भारत की ख़ुफ़िया ऐजेंसी इस संबंध में गोपनीय रिपोर्ट सरकार को भेजकर मवेशी तस्करी, नक़ली नोट के कारोबार व आतंकवादी संगठनों के तार जुड़ने की जानकारी दे रही है, वहीं बीएफ़ के सूत्रों का कहना है कि मवेशी तस्करी रोकने का हर संभव प्रयास किया जाता है, लेकिन सीमा पर अंधेरे का फ़ायदा उठाकर तस्कर मवेशी को सीमा पार करा लेते हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारियों को इस बारे में जानकारी है, लेकिन इसके बावजूद तस्करों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती. अगर इसी तरह तस्करी जारी रही तो वह दिन दूर नहीं जब लोग दूध तक के लिए तरस जाएंगे.

> पश्चिम बंगाल के फुलवाड़ी, मैनागुड़ी, माथाभंगा, कूचविहार रामगंज, कच्ची कली जैसे ऐसे कई ऐसे स्थान हैं, जहां से पशुओं को बांग्लादेश भेजा जाता है. कभी-कभी भारतीय तस्करों का माल बांग्लादेशी तस्कर एवं एजेंट हज़म कर जाते हैं और वे कुछ नहीं कर पाते. मवेशी तस्करी से जुड़े लोगों का कहना है कि पुलिस को हर माह सुविधा शुल्क जमा कराना पड़ता है.

feedback@chauthiduniya.com

नटराजन की वापसी से समीकरण बदला

नवल किशोर सिंह

समय बड़ा बलवान होता है. यह कहावत आइपीएस अधिकारी पीएस नटराजन के मामले में पूरी तरह चरितार्थ हो रही है. यौन शोषण के आरोप में पिछले क़रीब छह वर्षों से निलंबित नटराजन कैट के आदेश के बाद निलंबन मुक्त हो चुके हैं और उन पर आरोप लगाने वाली महिला सुषमा बड़ाइक सलाख़ों के पीछे पहुंच चुकी है. उन पर झारखंड आर्मी नामक आपराधिक संगठन का सरगना होने का आरोप है. सूबे के आइपीएस अधिकारियों के दो गुटों की वर्चस्व की लड़ाई का टर्निंग प्वाइंट काफ़ी दिलचस्प हो गया है. झारखंड पुलिस मुख्यालय में कहीं खुशी कहीं गम का माहौल बन गया है. पीएस नटराजन का निलंबन मुक्त हो जाना उनके विरोधी ख़ेमे की बेचैनी का सबब बन गया है. नटराजन के मुख्यालय में योगदान के बाद अगले डीजीपी की रेस में शामिल आला अधिकारियों की पेशानी पर बल पड़ने लगे हैं. उल्लेखनीय है कि वर्तमान डीजीपी नेयाज़ अहमद फ़रवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं. वरीयता क्रम के मुताबिक़ उनके बाद वीडी राम का नंबर आता है. वह फ़िलहाल होमगार्ड के डीजी हैं. वह एसएस फ़ंड दुरुपयोग मामले के आरोपी होने के कारण पहले ही रेस के बाहर हैं. उनके बाद पीएस नटराजन का नाम आता है, लेकिन वह निलंबित थे. इस कारण उनके बाद वरीयता क्रम में चौथे नंबर पर शामिल एडीजी जीएस रथ के डीजीपी बनने की संभावना प्रबल हो गई थी. वे किसी ख़ेमे में नहीं हैं, निष्पक्ष माने जाते हैं. मगर उनके नाम पर अगले डीजीपी पद के लिए अंतिम मुहर लगने की तिथि के ठीक पहले कैट के रांची सर्किट की संयुक्त खंडपीठ द्वारा नटराजन के निलंबन आदेश को सिरे से ख़ारिज़ कर दिए जाने के कारण सारा समीकरण गड़बड़ा गया है. अब नटराजन इस पद के प्रबल दावेदार बन गए हैं.

उल्लेखनीय है कि 31 जुलाई 2005 को एक टीवी चैनल पर कथित यौन शोषण से संबंधित सीडी के प्रसारण के बाद गृह विभाग ने नटराजन को आनन-फानन में अधिसूचना जारी कर निलंबित कर दिया था. निलंबन की अधिसूचना तक नटराजन के विरुद्ध न कोई प्राथमिकी दर्ज थी और न ही कोई विभागीय जांच चल रही थी. निलंबन से पूर्व उन्हें अपना पक्ष रखने का मौक़ा भी नहीं दिया गया. यह

सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन था. निलंबन के कारणों को भी स्पष्ट नहीं किया गया था. नटराजन का कहना है कि वरीय अधिकारियों का एक गुट किसी तरह उन्हें उलझाकर निलंबित कराना चाहता था, ताकि पुलिस मुख्यालय में उनके ग़लत कारनामों का विरोध करने वाला कोई न रहे और वे मनमाने ढंग से अपना सिक्का चला सकें. ग़ौरतलब है कि नटराजन के निलंबन के बाद ही एसएस फ़ंड के दुरुपयोग, एसपीओ फ़ंड में गोलमाल जैसी घटनाओं को अंजाम दिया गया. समय के अंतराल में यह बात भी सामने आई कि सुषमा बड़ाइक नामक जिस महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया था वह दरअसल आपराधिक प्रवृत्ति की है. फ़िलवक्त वह आपराधिक गिरोह चलाने के आरोप में जेल में बंद है. सूत्रों के मुताबिक़ कुछ वरीय पुलिस अधिकारियों से इसके गहरे ताल्लुक़ात हैं जिनके कहने पर वह कुछ भी करने को तैयार रहती है और उन्हीं के संरक्षण में झारखंड आर्मी नामक आपराधिक गिरोह का संचालन करती है. इस बात का ख़ुलासा इसके गिरोह के कुछ अपराधियों ने गिरफ्तारी के बाद किया है.

कैट की खंडपीठ ने निलंबन से जुड़े सभी तथ्यों पर गहराई से नज़र डालने और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपने फ़ैसले में नटराजन के निलंबन को पूरी तरह अवैधानिक क़रार दिया. न्यायमूर्ति एके जैन और न्यायमूर्ति रेखा कुमारी ने राज्य सरकार द्वारा जारी निलंबन की अधिसूचना निरस्त करने एवं नटराजन को तत्काल पुनर्नियुक्त करने, निलंबन की तिथि से लेकर अब तक के बक़ाया वेतन व अन्य भत्तों के भुगतान व तमाम सेवा लाभों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. 9 फ़रवरी 2011 को जारी कैट के आदेश के आलोक में नटराजन ने राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, डीजीपी व गृह सचिव को पत्र प्रेषित कर पुलिस मुख्यालय में योगदान देने की अनुमति मांगी. बहरहाल, नटराजन की वापसी को लेकर पुलिस मुख्यालय में हलचल तेज़ हो गई है. एक ख़ेमा उनकी वापसी को लेकर खुशी का इज़हार कर रहा है तो दूसरे ख़ेमे में मायूसी देखी जा रही है. नटराजन डीजीपी बनेंगे या नहीं यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कैट के फ़ैसले के बाद सबसे मज़बूत दावेदारी उन्हीं की है. अब झारखंड सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे नटराजन विरोधी खेमे के ताक़तवर लोग कैट के फ़ैसले को किस रूप में लेते हैं और उनका अगला रुख़ क्या होता है, यह देखना भी दिलचस्प होगा.

feedback@chauthiduniya.com

गुप्ताधाम पर वन विभाग की टेढ़ी नज़र

सासाराम

देश के कोने-कोने में बसे शिवभक्तों के लिए पौराणिक काल से ही आस्था का केंद्र रहे रोहतास ज़िले के दक्षिणी-पश्चिमी कोने में बैठे भगवान गुप्तेश्वर के दर्शन करने वाले शिवभक्तों की कठिन परीक्षा का दौर अब शुरू होने वाला है. पर्यटन विभाग एवं धार्मिक न्यास बोर्ड की तरफ़ से की जाने वाली पहल को देखकर यह जान पड़ा था कि अब इस धार्मिक केंद्र के दिन बहुरने वाले हैं, लेकिन अब इस पर वन विभाग की नज़र टेढ़ी हो गई है. कल तक जो विभाग शिवभक्तों को पवित्र गुफ़ा तक पहुंचाने के लिए दुर्गम पहाड़ी इलाक़ों में 30 किलोमीटर की लंबी सड़क बना रहा था, अब वही अपने वन्य प्राणियों को बचाने के लिए वन विभागीय पर्चा लेकर शिवभक्तों के सामने खड़ा है. इसका असर इस वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर गुप्ताधाम में लगने वाले मेले पर साफ़ दिखा. जहां पहुंचने के लिए न तो विभाग ने सड़क बनवाई और न ही प्रशासन पहले की तरह गुफ़ा में लगने वाले ऑक्सीज़न गैस के सिलेंडर एवं दवाइयां लेकर पहुंचा. भला हो इन स्वयंसेवी संस्थाओं का, जिनके सदस्य कांधे पर कांवड़ लिए चेनारी प्रखंड मुख्यालय से पैदल ही दुर्गम पहाड़ियों की ओर बढ़ने वाले शिवभक्तों के लिए चाय-बिस्कुट एवं मरहम-पट्टी के कुछ सामान लेकर खड़े थे. बताते चलें कि पौराणिक काल से ही भगवान शिव की इस गुफ़ा में स्थित प्राकृतिक शिवलिंग के दर्शन व जलाभिषेक करने बिहार ही नहीं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों एवं नेपाल देश से शिवभक्त आते रहे हैं. पूर्व में इस गुफ़ा के अंदर दम घुटने के कारण कई श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है. इसके बाद प्रशासन ने यहां ऑक्सीज़न गैस के सिलेंडरों की व्यवस्था की थी. अब वन विभाग पूरे अभ्यारण्य क्षेत्र में रहने वाले वनचरों की जान की दुहाई देकर यह आदेश निर्गत किया है कि इस क्षेत्र से होकर गाड़ियां नहीं गुज़रेंगी और झुंड के झुंड पहाड़ी पर जयघोष कर जाने वाले शिवभक्तों के कारण जानवरों पर प्रतिकूल असर पड़ता है. यह वन अधिनियम के ख़िलाफ़ है. इन निर्देशों के कारण प्रशासन ने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और अब शिवभक्तों को भगवान भरोसे धाम तक पहुंचना है. वन विभाग के इस निर्देश के ख़िलाफ़ चेनारी प्रखंड मुख्यालय पर स्वयंसेवी संस्थाओं ने धरना-प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ा. दूर से आने वाले शिवभक्तों की यात्रा जारी है. हालांकि, सुविधाओं की कमी देखकर वे भी निराश ही लौट रहे हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

दस लाख में मिलेगा बंगला

लोगों का बंगले में रहने का सपना अब पूरा हो सकता है. संजीवनी बिल्डकॉन ने मात्र दस लाख रुपये में 15 सौ वर्ग फ़ीट में बंगला और 18 लाख रुपये में डुप्लेक्स बनाकर देने का ऐलान किया है. संजीवनी बिल्डकॉन बंगले के साथ ही बिजली पानी एवं सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया कराएगा. यह जानकारी संजीवनी के निदेशक श्याम गुप्ता ने दी. वे पटना के फ्रेजर रोड स्थित ग्रैंडप्लाजा में कंपनी के कार्यालय के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. ऑफिस का उद्घाटन लोकप्रिय लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर चेतन भगत ने किया. निदेशक श्याम गुप्ता ने कहा कि कंपनी हर तरह की सुविधाओं से युक्त एक कॉलोनी का विकास करती है. एक कॉलोनी बसाने के लिए कम से कम दस एकड़ ज़मीन की ज़रूरत होती है. विभिन्न शहरों में 13 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. दो प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं. एक कॉलोनी में दो सौ से तीन सौ तक घर बनाए जाते हैं. रांची के ओरमांझी चौक के पास पाटलीपुत्र-बिरसा कॉलोनी नामक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है. देश के तक़रीबन सभी बड़े शहरों में कंपनी के अपने गेस्ट हाउस हैं. ग्राहकों के लिए गेस्ट हाउस में मुफ्त रहने की व्यवस्था भी है. ग्राहक चाहें, तो अपने दोस्तों के साथ भी गेस्ट हाउस में भी ठहर सकते हैं.

> एक कॉलोनी में दो सौ से तीन सौ तक घर बनाए जाते हैं. रांची के ओरमांझी चौक के पास पाटलीपुत्र-बिरसा कॉलोनी नामक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

PATALIPUTRA SCHOOL OF FIRE & SAFETY MANAGEMENT
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, which is Govt. of India registered, Regd. No. 03-09284 of 2000-2001.
ISO 9001:2000 certified, Regd. No. CCPL/QMS/C1487
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where Practicals are conducted.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where one full paper of 100 marks on petroleum is taught.
Only one Institute of Bihar & Jharkhand, where students of Industrial Safety Management Course of Patna University & Magadh University get Practical Training.
FREE Demo-Classes in the Morning & Evening from Monday to Friday
Excellent Placement with Handsome Salary
Website: www.psfsm.com
410, Ashiana Galaxy, Exhibition Road, Patna-800 001
Ph: 0612-6455019, Mob.: 9334107607, 9835042835, 9234729075

एक नज़र

नेहरू युवा केंद्र का भवन निर्माण अधर में

युवाओं पर आधारित गतिविधियों सहित इसमें राष्ट्रीय भाव जागृत करने के उद्देश्य से खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा संचालित नेहरू युवा केंद्र के भवन का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पांच वर्ष पूर्व किया गया था जिसका निर्माण आज तक नहीं हो सका. तत्कालीन जिलाधिकारी महेश्वर प्रसाद सिंह ने आनन-फानन में भवन के लिए ज़मीन आवंटित कर इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री के हाथों करा दिया, लेकिन इसके बाद नेहरू युवा केंद्र का स्थल तीन बार बदले जाने के बाद भी निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं दिख रही. नीतीश कुमार के पुन: मुख्यमंत्री बनने के बाद लोगों में अब नेहरू युवा केंद्र के उद्धार की उम्मीद जगी है, लेकिन पहल कब शुरु होगी यह बताने वाला कोई नहीं है.

सेल को चिड़िया माइंस मिली

भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) को झारखंड स्थित चिड़िया माइंस से खनन व क्रशिंग की अनुमति मिल गई है. केंद्रीय वन एवं पर्यावरम मंत्रालय ने 13 शर्तों के आधार पर सेल को चिड़या माइंस से खनन की स्वीकृति दी है. मालूम हो कि सेल और झारखंड सरकार के बीच चिड़िया माइंस लीज नवीकरण का मामला वर्षों से लंबित था. केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने सेल के भविष्य को देखते हुए 50 वर्षों के लिए चिड़िया माइंस आवंटित किया है. उल्लेख्य है कि चिड़िया माइंस में करोड़ों टन का लौह अयस्क का भंडार है. मंत्रालय ने समीपवर्ती गावों में कल्याणकारी कार्यों पर कुल लाभ का दो फ़ीसदी ख़र्च करने की शर्त पर यह आवंटन दिया है.

अमर नाथ पाठक तीसरी बार महासचिव बने

मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ के चुनाव में अमरनाथ पाठक लगातार तीसरी बार महासचिव पद पर निर्वाचित किए गए. वही अध्यक्ष पद पर फ़हीमउद्दीन चुने गए. श्री पाठक ने अपने विरोधी को बड़े अंतर से पराजित किया, जबकि अध्यक्ष पद के लिए छह प्रत्याशी थे. जिनमें से फ़हीमउद्दीन निर्वाचित किए गए. बताया जाता है कि अमरनाथ पाठक शिक्षकेतर कर्मचारियों के हित के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं और कर्मचारियों की समस्याओं का सामाधन कराने में सफल रहे हैं. यही कारण है कि कर्मचारियों ने इन्हें लगातार तीसरी बार महासचिव पद पर निर्वाचित किया है जो कि एक रिकार्ड है.

–सुनील सौरभ

नई इबारत लिख रहे हैं

गया ज़िले के उग्रवाद प्रभावित नीमचक बथानी अनुमंडल के सुदूरवर्ती झरना सरेन गांव में गौतम बुद्ध शिक्षण संस्थान ग़रीब बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा देकर सराहनीय कार्य कर रहा है. ग़रीब विशेषकर जिनके अभिभावक अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं, उन्हें अपने आवासीय संस्थान में रखकर मुफ्त शिक्षा दे रहा है. इसके संचालक चन्द्रमौली प्रसाद बौद्ध के इस प्रयास की सराहना मगध प्रमंडल के आयुक्त से लेकर अनेक पदाधिकारी कर चुके हैं. इस विद्यालय में बच्चे और शिक्षक सभी एक जैसे परिधान में रहते हैं. उग्रवाद प्रभावित और पिछड़े इलाक़े में ग़रीब बच्चों को मुफ्त आवासीय परिसर में रखकर शिक्षा प्रदान करने की यह अच्छी मिसाल है.

–जयनाथ प्रसाद गुप्ता

दुकानदार घटिया खाना परोस रहे हैं

समस्तीपुर में चाहे लालू राज हो या नीतीश राज यहां के स्टेषन चौक स्थित दुकान प्रतिष्ठान एवं होटलों में कोई फ़र्क़ नज़र नहीं आता. चौबीसों घंटे चहल -पहल वाले स्टेषन चौक में शायद ही इक्के-दुक्के व्यवसायिक प्रतिष्ठान होंगे जिनके कर्मचारियों को बिहार राज्य दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत सेवा कार्डफ (परिचय पत्र) मिला होगा. रेलवे अधिनियम के अंतर्गत समस्तीपुर जंक्शन के सभी नौ प्लेटफ़ार्मों पर यात्रियों को खान-पान की समुचित सुविधा नहीं मिलती है जिस कारण यात्री स्टेशन के बाहर स्थित होटलों में अपनी भूख-प्यास मिटाते हैं. कहते हैं कि स्टेशन चौक के दुकान एवं होटल चौबीस घंटे सेवा नहीं दे तो रेल यात्रियों को खान-पान की सुविधा के लिए काफ़ी परेशानी होगी. इन दिनों स्टेशन चौक के विभिन्न होटल संचालक सत्ता शासन से बेख़ौफ़ होकर ग्राहकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. अस्सी फ़ीसदी होटल में बर्तनों की साफ़-सफ़ाई की समुचित व्यवस्था नहीं है. साथ ही ग्राहकों को दिए जानेवाले भोजन की गुणवत्ता भी निम्नस्तरीय है. अच्छे तेल एवं वनस्पति के बजाय मिलावटी व सस्ते विकल्पों का प्रयोग किया जाता है.

शराब की कालाबाज़ारी

समस्तीपुर ज़िले में शराब की कालाबाज़ारी जारी है. शराब की खपत में यह जिला हर वर्ष पहले या दूसरे नंबर पर रहता है. इसके बावजूद ज़िला मुख्यालय स्थित शराब की दुकानों से निर्धारित दर से अधिक क़ीमत पर शराब बेची जा रही है. बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़िला मुख्यालय से पांच रुपये कम क़ीमत पर शराब बिक रहे हैं. ज़िला मुख्यालय के सुप्रसिद्ध थानेश्वर मंदिर के समीप खुली शराब की दुकानें सरकारी नियमों की अवहेलना कर रही हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी इस तरफ़ से आंखें मूंदे बैठे हैं.

–विकास कुमार

शहीद स्मारक स्तंभ का शिलान्यास

झारखंड के अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव की स्मृति में हटिया स्थित चांदनी चौक पर स्मारक स्तंभ का शिलान्यास केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोधकांत सहाय ने किया. इस अवसर पर श्री सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि शहीदों के पदचिन्हों पर चलना और इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. स्मारक स्तंभ के निर्माण में उन्होंने आर्थिक सहयोग का भी आश्वासन दिया. इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता नवीन शाहदेव ने की. इस मौक़े पर सूरज शाहदेव, प्रो. अनिल ठाकुर, ठाकुर युगल किशोर नाथ शाहदेव, जयकिशन राम, अब्दुल क़ादिर, राजकपूर, उमेश प्रसाद सहित की गण्यमान्य लोग उपस्थित थे.

'शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण' टेक्नो मिशन स्कूल का मुख्य उद्देश्य

समस्तीपुर शहर के पटेल मैदान के दक्षिण-पश्चिम कोने पर अवस्थित विधि महाविद्यालय के नजदीक 'टेक्नो मिशन स्कूल' के प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् ए. के. लाल का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा के माध्यम से समाज का सशक्तिकरण. समस्तीपुर में स्कूली शिक्षा का स्वरूप अभी भी विकसित नहीं हुआ है इस विकृति को दूर करने के लिए टेक्नो मिशन स्कूल की स्थापना की गई है जहां बच्चों को समुचित शिक्षा इस तरह मिले कि उनका सर्वांगीन विकास हो. यह विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली के नई शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा प्रदान करेगा. विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 का ध्यान शुरू से ही रखा जायेगा ताकि नर्सरी एवं कक्षा एक में उन समूह के बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिल सके.

टेक्नो मिशन की स्थापना से उत्साहित ए. के. लाल समस्तीपुर के लिए कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में यहां के बच्चे यहीं रहकर ऐसी शिक्षा ग्रहण करें कि उनका नाम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो. वे इस स्कूल को राष्ट्रीय स्तर की ख्याति दिलाने हेतु कृत संकल्पित हैं जिसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिली है. वर्ष 1987 में स्थापित होली मिशन स्कूल से शिक्षा जगत में कदम रखनेवाले श्री लाल के नेतृत्व में होली मिशन का संबद्धन सी. बी. एस. ई. से मिला. सन् 2000 में ये होली मिशन के प्राचार्य बने और होली मिशन की ख्याति राष्ट्रीय स्तर तक फैली. हर छोटे-बड़े शहरों में होली मिशन स्कूल के बच्चे अपना नाम कर रहे हैं. श्री लाल की सोच एवं प्रबंधन नीति का परिणाम है कि देश की जानी-मानी संस्था इण्डियन इन्स्टीच्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नई दिल्ली ने इन्हें शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ प्राचार्य का पुरस्कार दिया.

समय ने करवट बदली किसी कारणवश उन्हें होली मिशन स्कूल छोड़ना पड़ा. कुछ लोगों को श्री लाल की लोकप्रियता रास नहीं आ रही थी. लोग इनकी सहनशीलता को कमजोरी समझ बैठे थे पर वे क्या जानें कि श्री लाल की प्रतिभा को दबाना या कुचलना मुश्किल ही नहीं असंभव है. शहर के बच्चों, अभिभावकों एवं शुभचिन्तकों का सहयोग उन्हें मिलता रहा है और आगे भी मिलता रहेगा ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है. इस विद्यालय के प्रबंधक एम. के कर्ण बताते हैं कि विद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया सरस्वती पूजा के दिन से शुरू हो गई है. सामान्य वर्ग के बच्चों को नामांकन में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. अलाभकारी एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों का नामांकन नि:शुल्क किया जायेगा. इन बच्चों के लिए नर्सरी एवं कक्षा एक में 25 प्रतिशत स्थान सुरक्षित होगा. विद्यालय प्रबंधन की सोच है कि एक ही छत के नीचे के. जी. से पी. जी. तक की पढ़ाई हो जिसकी सफलता के लिए हम कृत संकल्पित हैं. इसके लिए युवाओं एवं अनुभवी लोगों की टीम बनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करने का संकल्प लिया गया है.

ए.के.लाल चेयरमैन टेक्नो मिशन स्कूल

रंगों का त्यौहार होली की **नामांकन सूचना** हार्दिक शुभकामनायें

Phone : 0612-2252999 / 2253290 Visit us : www.iiher.org

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH

Health Institute Road, Beur (Near Central Jail), Patna -2.

(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)

AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

We Impart :-

Name of Cources		Eligibility
POST GRADUATE COURSES :		
MPT	Master of Physiotherapy	BPT
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT
UNDER GRADUATE COURSES :		
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc
BMRT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc
B.Sc. Bio Technology		I.Sc
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc
B.Ed.	(Special Education)	Graduate
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT		
DIPLOMA COURSES :		
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate
CERTIFICATE COURSES :		
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc
Foundation Course For Teachers in Disability		

बिहार में पहली बार फिजियोथेरापी में मास्टर डिग्री तथा ऑफ्थालमोलॉजी, मेडिकल लैब तथा एक्स-रे में डिग्री

अब बिहार में भी फिजियोथेरापी तथा अकुपेशनल थेरापी में मास्टर डिग्री की पढ़ाई शुरू हो गयी है। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना निर्गत कर, बेऊर पटना स्थित इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च में शैक्षणिक सत्र 2008-09 से उपरोक्त पाठ्यक्रमों में पढ़ाई आरंभ करने के साथ, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 की घारा-21(2 डी) के प्रावधानों के अनुसार, मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत संबंधन की स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्गत अधिसूचना सं० -1/पी.एम.आई.-01/04 - 1110 (1), दिनांक 23-10-2008 के अनुसार इस संस्थान को बैचलर ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ एक्स-रे टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तथा बैचलर ऑफ ऑप्थालमोलॉजी पाठयक्रमों लिये भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्मरणीय है कि इस संस्थान में बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी, बैचलर ऑफ अकुपेशनल थेरापी, बैचलर ऑफ प्रॉस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक, बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी तथा बी.एड स्पेशल एजुकेशन को राज्य सरकार तथा मगध विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व से हीं स्थायी संबंधन और स्वीकृति प्राप्त है। इस संस्थान में चलाये जा रहे वे सभी पाठ्यक्रम जो भारतीय पुनर्वास परिषद के अंतर्गत आते हैं, सभी परिषद से भी मान्यता प्राप्त है।

विकलांगों के उपचार और उनके पुनर्वास के क्षेत्रों में नयी तकनोलॉजी के विकास से इस क्षेत्र में युगान्तरकारी और सकारात्मक परिवर्तन आये हैं। इससे एक ओर जहां विकलांगता निवारण तथा विकलांगों के उपचार में सफलता का दर बहुत तेजी से बढ़ा है, वहीं इस क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने वाले पुनर्वास-कर्मियों को भी विशिष्टता के साथ देश-विदेश में रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त हो रहे हैं। नयी तकनोलॉजी के विकास के साथ इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों जैसे फिजियोथेरापी, अकुपेशनल थेरापी, ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच थेरापी, प्रोस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक इंजीनियरिंग, आदि में कोर्स का भी विस्तार हुआ है और उन्हें परिष्कृत कर अन्य चिकित्सकों की समकक्षता के काफी करीब ले आया गया है। इन पाठ्यक्रमों में मास्टर डिग्री तथा डिग्री स्तर की शिक्षा में विशेषज्ञों को इतना योग्य बना दिया जाता है कि वे अपने-अपने कार्य में स्वतंत्र रूप से रोगियों की पहचान और उपचार करने में दक्ष हो जाते हैं। फिलवक्त पूरे देश में विकलांगों के पुनर्वास से संबंधित पाठ्यक्रमों में डिग्री स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने वाले संस्थान कुछ एक हीं हैं। उन्हीं में से एक इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेऊर (सेंट्रल जेल के निकट), पटना, पुनर्वास विज्ञान के इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान है।

इस संस्थान ने फिजियोथेरापी तथा अकुपेशनल थेरापी पाठ्यक्रमों में एक वर्षीय एब्रीज्ड डिगी-पाठ्यक्रम आरंभ कर देश के उन सभी प्रोफेशनल्स के भी भविष्य के दरवाजे खोल दिये है, जो इन क्षेत्रों में डिप्लोमा धारक थे और अपनी योग्यता को नहीं बढ़ा पा रहे थे। ऐसे व्यक्तियों के लिये एब्रीज्ड कोर्स एक वरदान के रूप में सामने आया है।

इस संस्थान की शुरूआत 1990 में फिजियोथेरापी, प्रोस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक्स-रे टेक्नोलॉजी तथा हॉस्पीटल मैनेजमेंट में डिप्लोमा की पढ़ाई से हुई थी।शैक्षणिक सत्र 1997-98 से इसमें डिग्री पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।मगध विश्वविधालय डिग्री पाठ्यक्रमों की परीक्षा लेती है।

राज्य सरकार ने हाल ही में एक अलग अधिसूचना निर्गत कर इस संस्थान में पूर्व से संचालित इ.सी.जी. तथा ओ.टी. टेक्नीशियन में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को उत्क्रमित कर डिप्लोमा स्तर का कर दिया है। मेडिकल ड्रेसिंग में सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। डिप्लोमा तथा सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों की परीक्षा राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा ली जाती है।

बैचलर ऑफ फिजियोथेरापीः- यह पाठ्यक्रम ऐसे ग्रेजुयेट फिजियोथेरापिस्टस तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो स्वतंत्र रूप से शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता के मरीजों की जांच-पड़ताल एवं उपचार कर सके । यह बताने की जरूरत नहीं है कि इस विशेष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, पोलियो और लकवा सहित हड्डी, जोड़, नस एवं मांसपेशियों से संबंधित सभी प्रकार के दर्द एवं विकलांगता का इलाज किया जाता है, जो किसी भी अन्य प्रकार से संभव नहीं है। इस पद्धति में भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यायामों तथा इलेक्ट्रीकल एवं कंप्युटराइज्ड मशीनों एवं उपकरणों की मदद से उपचार किया जाता है, जिनमें लेजर थेरापी, माइक्रोवेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी, अल्ट्रासाउन्ड, ऑटोट्रैक्शन, मायोग्राफर, इलेक्ट्रीक स्टूमलेशन, हाइड्रोथेरापी, इंटर फेरेंशियल करेंट थेरापी आदि शामिल हैं । एक ग्रेजुएट फिजियोथेरापिस्ट की देश-विदेश में बड़ी मांग है ।

साढ़े चार वर्षीय (जिसमे 6 माह का इंटर्नशिप शामिल है) इस पाठ्यक्रम में नामांकन की न्यूनतम योग्यता - बायोलॉजी के साथ इंटर मीडियेट विज्ञान है।

बैचलर ऑफ अकुपेशनलथेरापी :- यह पाठ्यक्रम भी बैचलर ऑफ फिजियोथेरापी कोर्स से बहुत हदतक मेल खाता है । किन्तु इस पद्धति में इलेक्ट्रीकल उपकरणों के इस्तेमाल कम होते हैं। इसके द्वारा ऐसे विकलांगों को पुनर्वासित करने का कार्य किया जाता है, जो फिजियोथेरापी की सीमा से आगे बढ़ चुके होते हैं और उनमें स्थायी विकलांगता आ चुकी होती है ।एक अकुपेशनल थेरापिस्ट, स्थायी रूप से विकलांग हो चुके मरीजों को न केवल स्वतंत्र रूप से अपना सभी आवश्यक कार्य संपन्न करने योग्य बनाता है, बल्कि उसके योग्य रोजगार परक अकुपेशन (प्रशिक्षण) अपनाने की सलाह भी देता है । वस्तुतः ऐसे विकलांगों के लिये एक अकुपेशनल थेरापिस्ट देवदूत सरीखा होता है।

साढ़े चार वर्षीय (जिसमे 6 माह का इंटर्नशिप शामिल है) इस पाठ्यक्रम में नामांकन की न्यूनतम योग्यता - बायोलॉजी के साथ इंटर मीडियेट विज्ञान है।

बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजीः- यह पाठ्यक्रम ऐसे ग्रेजुएट ऑडियोलॉजी एण्ड स्पीच पैथोलॉजिस्ट (हियरींग एण्ड स्पीच थेरापिस्ट) तैयार करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जो स्वतंत्र रूप से श्रवण (हियरींग) एवं वाक् (स्पीच) दोषों के मरीजों की जांच और उपचार कर सके । स्पीच पैथोलॉजी तथा ऑडियोलॉजी एक दूसरे के पूरक चिकित्सा विज्ञान है और इसी लिये ये दोनों विषय एक साथ पढ़ाये जाते हैं ताकि इसके ग्रेजुएट दोनों हीं क्षेत्रों मे अपना कैरियर बना सके । स्पीच थेरापी के माध्यम से आवाज, वाक् तथा उच्चारण के दोषों को ठीक किया जाता है,जबकि ऑडियोलॉजी का संबंध श्रवण-दोष की विभिन्न प्रकार की जांच के तरीकों से है । इसके द्वारा श्रवण-क्षमता की सटीक जांच की जाती है तथा कम सुननेवाले एवं बहरे लोगों का उपचार और हियरींग-एड (श्रवण-यंत्र) की सहायता से उनका पुनर्वास भी किया जा सकता है । इसमें प्रशिक्षित व्यक्तियों के लिये रोजगार एवं निजी प्रैक्टिश के व्यापक क्षेत्र हैं । इनका समायोजन अस्पतालों, स्पीच एण्ड हियरींग केन्द्रों, नाक, कान एवं गला विभाग, शिशुरोग विभाग सहित न्युरोलॉजी, प्लास्टीक सर्जरी, रिहैब्लिटेशन मेडिसीन, प्रिवेन्टीव मेडिसीन विभागों तथा गुंगे-बहरे एवं मानसिक विकलांग विद्यालयों मे स्पीच पैथोलॉजीस्ट और / या ऑडियोलॉजिस्ट के पदों पर किया जाता है ।

चार वर्षीय (इसमे एक वर्ष का इंटर्न शिप शामिल है ।) इस पाठ्यक्रम में नामांकन की न्युनतम योग्यता इंटरमीडीएट विज्ञान है ।

बैचलर ऑफ प्रौस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक इंजीनियरींगः- इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य ऐसे प्रोस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक ग्रेजुएट इंजिनीयर तैयार करना है, जो स्थायी रूप से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये स्वतंत्र रूप से मरीजों की पहचान तथा उन्हें आवश्यक कृत्रिम अंग (आर्टिफिशियल लिम्ब) देकर उन्हें सामान्य जीवन जीने योग्य बना सके।

यह विज्ञान विकलांगों के पुनर्वास के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । क्योंकि स्थायी रूप से विकलांग हो गये व्यक्ति जिनके हाथ या पैर कट चुके होते हैं, उन्हें सारा जीवन कृत्रिम अंग के सहारे जीना पड़ता है। यह प्रोस्थेटिक एण्ड ऑर्थोटिक इंजीनियर हीं है, जो उनके शारीरिक बनावट और कटे हुये स्थान के मुताबिक कृत्रिम पैर या हाथ (जरूरत के अनुसार) देकर उन्हें सामान्य जीवन जीने लायक बनाते हैं।

इस क्षेत्र में तेजी से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हो रहे हैं। आज इस तरह के कृत्रिम हाथ-पैर बनाये जा रहे हैं, जो न केवल देखने में, बल्कि उपयोग में भी प्राकृतिक जैसे लगते हैं । इनके अतिरिक्त एक प्रोस्थेटिक इंजीनियर पोलियो के जूते, कैलिपर, बैशाखी, गर्दन के कॉलर, कमर के बेल्ट तथा कई अन्य सहायता सामग्री एवं उपकरण बनाते हैं, जिनकी फिजियोथेरापी, अकुपेशनल थेरापी तथा पुनर्वास के लिये जरूरत होती है । एक प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक इंजीनियर के विना किसी पुनर्वास केन्द्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लिहाजा यह एक बहुत हीं रोजगार परक क्षेत्र है। अपना ''कृत्रिम अवयव निर्माण केन्द्र'' स्थापित कर लाभप्रद स्वरोजगार भी प्राप्त किया जा सकता है ।

चार वर्ष ऑर ६ माह इंटर्नशिप के इस पाठ्यक्रम में नामांकन की न्यूनतम योग्यता इंटरमीडियेट विज्ञान है। इस संस्थान में उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मेडिकल लैब. टेक्नोलॉजी (पैथोलॉजी). एक्स-रे टेक्नोलॉजी (रेडियोग्राफी) ओ.टी. असिस्टेंट, ड्रेसर, इ.सी.जी. तकनीशियन तथा हॉस्पीटल मैनेजमेंट में भी डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम चलाये जाते हैं।

संस्थान में शैक्षणिक सत्र-2010-11 में नामांकन जारी है :- फॉर्म तथा प्रोस्पेक्टस किसी भी कार्य दिवस में संस्थान कार्यालय, हेल्थ इंस्टीच्युट रोड, बेऊर, पटना-2 से 300 रूपये मात्र का नगद भुगतान कर, अथवा 350 रूपये मात्र का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट, जो कि ''इंडियन इंस्टीच्युट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एण्ड रिसर्च, पटना'' के नाम देय हो, भेजकर डाक से मंगाया जा सकता है।

संस्थान द्वारा संचालित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ

- स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श
- टीकाकरण
- फिजियोथेरापी
- अकुपेशनल थेरापी
- स्पीच थेरापी
- नेत्र जांच
- सभी प्रकार की विकलांगता पोलियो, लकवा, गठिया, हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित सभी प्रकार के रोगों की जांच एवं उपचार
- हकलाना, तुतलाना सहित गूंगे-बहरों की जांच एवं उपचार हियरिंग-एड
- मानसिक विकलांगता तथा मंद बुद्धिपता जांच एवं उपचार
- कृत्रिम हाथ, पैर, कैलीपर, पोलियो के जूते, वैशाखी, सरवाइकल कॉलर, बेल्ट आदि का निर्माण एवं वितरण
- लाचार विकलांगों को तिपहिया -साइकिल तथा व्हीलचेयर
- विकलांगों की शल्य चिकित्सा (सर्जिकल करेक्शन)
- रियायती दर पर पैथोलोजिकल जांच
- एक्स-रे, इ.सी.जी. तथा शल्य चिकित्सा।

डा० अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख